असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

03 मार्च, 2016

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

प्रश्नोत्तर काल ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमारः महोदय, राज्य में पंचायत का चुनाव प्रारम्भ हो गया है । राज्य में पंचायत का चुनाव शुरू हो गया है और पिछड़ी जाति के कोटे में 17 जातियों को जोड़ा गया है महोदय और महादलित में 3 जातियों को शामिल किया गया है महोदय । हमलोगों ने मांग किया था राज्य सरकार से कि अतिपिछड़ो को 20 के बजाय 30 परसेंट किया जाय और 16 परसेंट जो महादलित का है बढ़ाकर 19 परसेंट किया जाय । हम सरकार से मांग करना चाहते हैं हुजूर ।

अध्यक्षः नेता, प्रतिपक्ष आपको तो मालूम है इसको कब उठाना है ।

श्री प्रेम कुमारः बिल्कुल ।

अध्यक्षः आपको तो मालूम है । अभी प्रश्नोत्तर काल बाधित करके उठा रहे हैं ।

श्री श्याम रजकः अध्यक्ष महोदय, नेता, प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं लेकिन हम इनसे जानना चाहते हैं कि बी0जे0पी0 की सरकार है प्रोन्नति में आरक्षण का मामला अभी तक वहां अटका हुआ है सारे दलित लोग परेशान हैं । क्या उसके लिए वहां अपने सांसदों को और अपनी सरकार को दबाव देकर प्रोन्नति में आरक्षण बिल को पास करायेंगे ?

श्री प्रेम कुमारः महोदय, हम बिहार की बात अभी कर रहे हैं । आप अन्य राज्यों की बात कर रहे हैं । हम बिहार की बात कर रहे हैं । अतिपिछड़ों की बात कर रहे हैं, आप विषय डायवर्ट कर रहे हैं । हम बिहार की बात कर रहे हैं । आपने अतिपिछड़ों के कोटे में सेंधमारी करने का काम किया है, हकमारी करने का काम किया है । इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार शून्य काल में इस पर जवाब दे ।

अध्यक्षः शांति । तारांकित प्रश्न ।

तारांकित प्रश्न संख्या-398 (श्री समीर कुमार महासेठ)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्माः अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल प्रखंड के सरिसबपाही पश्चिमी पंचायत के हाटी बरवाहा टोला में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में एक अदद इंडिया मार्क-3 एवं एक अदद साधारण चापाकल निर्मित है जो चालू अवस्था में है एवं जलापूर्त्ति हो रही है ।

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहेंगे । चूंकि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं मेरा प्रश्न है कि जो लगा चालू हुआ ही नहीं और मंत्री जी का जो जवाब है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं । आपका संरक्षण चाहिए ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आपने कहा है कि दो चापाकल है दोनों चालू है । मा0 सदस्य का कहना है कि जो लगा वह चला ही नहीं । इसकी वरीय पदाधिकारी से जांच करा लीजिये ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्माः महोदय हम बिल्कुल कन्फर्म हैं चालू है वहां मिड डे मील बनता है । फिर बच्चे सब को दिया जाता है, कैसे बनता होगा ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, उस इलाके से हैं ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्माः माननीय सदस्य जब कह रहे हैं तो हम इसको दिखवा लेंगे ।

अध्यक्षः ठीक है इसको वरीय पदाधिकारी से दिखवा लें ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्माः ठीक है दिखवा लेंगे ।

श्री नंद किशोर यादवः इतना गंभीर विषय है महोदय । माननीय सदस्य उस क्षेत्र के विधायक हैं । वे दावे के साथ कह रहे हैं कि चालू नहीं है और माननीय मंत्री दावे के साथ कह रहे हैं कि चालू है । महोदय, विधान सभा की कमिटी बनाकर भिजवा दीजिये जांच के लिए । आपका संरक्षण चाहिए महोदय । यह स्थिति पूरे बिहार की है महोदय । सभी विद्यालयों में जो चापाकल लगे हैं चालू नहीं हैं महोदय । इसलिए मेरा आग्रह होगा कि पूरे विषय पर एक कमिटी बना दीजिये, चुनौती दी जा रही है मंत्री के जवाब को तो महोदय इसका निदान तो होना चाहिए न । महोदय, आपसे आग्रह होगा कि निदान कराइये और माननीय सदस्य ने जो चुनौती दी है उसका निराकरण कराइये ।

अध्यक्ष: माननीय नंद किशोर जी, आप सारी बातों से अवगत हैं कि जब कभी माननीय मंत्री के प्रश्न के उत्तर को संबंधित सदस्य चुनौती देते हैं तो वरीय अधिकारी से इसकी जांच करायी जाती है । यही प्रक्रिया आप भी मंत्री थे तो करते थे ।

श्री नंद किशोर यादव: जांच की बात पर वे कह रहे हैं कि वे आश्वस्त हैं । माननीय मंत्री ने जो कहा उसको सुन तो लीजिये पूरा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-399 (श्री जिवेश कुमार)</u>

श्री महेश्वर हजारी: महोदय, (1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बुडको के पत्रांक-1610 दिनांक 28.05.2014 द्वारा तीनों तालाबों से संबंधित विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर) तैयार करने हेतु परामर्शी मेसर्स सिकॉन प्राईवेट लिमिटेड को स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया है ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि मेसर्स सिकॉन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा समर्पित ड्राफ्ट डी0पी0आर0 की जांच बुडको द्वारा की गयी है और बुडको के पत्रांक- 234 दिनांक 01.02.2016 कतिपय बिन्दुओं पर परामर्शी से पृच्छा की गयी है, जो अभी तक अप्राप्त है। इस हेतु परामर्शी को बुडको के पत्रांक-536 दिनांक 02.03.2016 द्वारा स्मारित किया गया है । बुडको से प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात् निधि की उपलब्धता के आलोक में कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

श्री जिवेश कुमार: महोदय, डी0पी0आर0 2014 में बना है और उस समय से लेकर अभी तक लगभग डेढ़ वर्षो का समय बीत गया इतने दिनों में इस पर काम चालू क्यों नहीं हुआ । हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि इस काम को आगे कब तक प्रारम्भ किया जाएगा कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे क्या ?

श्री महेश्वर हजारी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता से मैं चिंतित जरूर हूं और हमने अपने विभाग को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस पर विचार करके पैसा प्रबंध करके इसका प्रबंध किया जाय और इस पर हमलोग जल्द से जल्द कार्य को प्रारम्भ करायेंगे ।

श्री संजय सरावगी: महोदय, ये जो तीन पोखर है वह ऐतिहासिक पोखर है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जल्द से जल्द का क्या मतलब । जल्द से

जल्द तो दो तीन दिन भी होता है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह के साथ पूछना भी चाहता हूं कि कब तक यह हो जाएगा स्वीकृत । क्योंकि दो साल हो गया डी0पी0आर0 बने हुए महोदय ।

श्री महेश्वर हजारी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी वहीं का हूं और मैं भी वहां की समस्या को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं । यदि माननीय सदस्य इतना चिंतित हैं तो पहले भी ये सरकार में थे । उस समय भी कहते लेकिन मैं वहां का प्रभारी भी हूं । जल्द कराउंगा काम ।

तारांकित प्रश्न संख्या-400 (श्री फैयाज अहमद)

श्री महेश्वर हजारी: (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि कुसुमपुरम कॉलोनी में एक आवासीय G+2 का नक्शा पारित किया गया है दिनांक 04.02.2016 को ।

(3) मास्टर प्लान, नये क्षेत्र एवं पुराने क्षेत्र की अधिसूचित होने पर 12 फीट एवं 16 फीट सड़क पर भवन उपविधि 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसार नक्शा पास करने की दिशा में कार्रवाई की जायेगी।

श्री फैयाज अहमद: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो नक्शा 6 महीना से पड़ा हुआ है और वहां के पुराने एवं नये क्षेत्र के वर्गीकरण का दावा आपत्ति प्राप्त करके अनुमोदन के लिए विभाग में भेजा गया और अभी तक यहां पेंडिंग पड़ा हुआ है । तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि कितने दिनों में जितना नक्शा पेंडिंग है उसको स्वीकृत करा देंगे । एक ही क्यों स्वीकृत हुआ बहुत सैकड़ों की संख्या में वहां नक्शा पेंडिंग है ।

श्री महेश्वर हजारी: अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में ही हमलोगों ने ई0 म्युनिसपल का शुभारंभ किया है उसमें ऑन लाईन नक्शा का कर दिया गया है और जब भी चाहें आवेदक जो व्यक्ति चाहें तो जो बिल्डिंग बाइलॉज है उसके अनुसार बनाकर दें वह ऑन लाइन नक्शा स्वीकृत होने का काम होगा । चूंकि ऑन लाइन कर दिया गया इसलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-401 (श्री फैयाज अहमद)

श्री महेश्वर हजारी: महोदय,(1)स्वीकारात्मक है ।

(2) राज्य सरकार से संबंधित नहीं है ।

श्री फैयाज अहमद: माननीय अध्यक्ष महोदय इसको शामिल कर लेंगे तो सरकार को ही न फायदा होगा टैक्स मिलेगा और शहरी क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा । इसलिए हमारा आग्रह है आपके माध्यम से कि शामिल कर लें उसको चुनाव के पहले ।

टर्न-2/बिपिन/03.03.2016

तारांकित प्रश्न सं0-402 (श्री विजय कुमार खेमका)

श्री महेश्वर हजारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णिया नगर निगम में कुल 46 वार्ड है । सभी वार्डों में पी.सी.सी.सड़क एवं नाला-नाली निर्माण का कार्य चल रहा है । इसके अतिरिक्त स्लम क्षेत्र में IHSDP एवं RAY के अन्तर्गत भी आधारभूत संरचना यथा- पी.सी.सी.सड़क, नाला एवं शौचालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है ।

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया नगर निगम 40 वार्ड का है । कम-से-कम 20 ऐसा टोला है जिस टोले में न पानी है, न बिजली है, न नाला है, न सड़क है। वार्ड नम्बर-2 मधुबनी में स्थित, मैं नाम गिनाता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को, मंत्री जी ने कहा है कि नाला, पानी की व्यवस्था वहां हो रही है, पी. सी.सी. सड़क बन रही है, वनभाग, आशीर्वादनगर, वार्ड नम्बर-17-18, सर्वोदय नगर, भगवानपुर, रिफ्युजी कॉलोनी, बक्साघाट, चिमनी बाजार, इन सब जगहों पर पिछड़ा, अतिपिछड़ा के साथ-साथ एस.सी. और एस.टी. सब छोटा-छोटा टोला, जहां न बिजली पहुँची है, न सड़क है, न पानी और न नाला की व्यवस्था है । अध्यक्ष महोदय, पांच छ: वार्ड ऐसे हैं जिन वार्डों में एस.सी. और एस.टी. के लोग रहते हैं...

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री विजय कुमार खेमका: जी । इन वार्डों में और इस नगर निगम में आधारभूत संरचना भी खड़ी नहीं है और विकसित वार्ड है, ऐसे बसावट जो हैं, इन बसावटों में कब सड़क और बिजली की व्यवस्था होगी ?

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं और चार ऐसी बड़ी-बड़ी सड़कें हैं जिनको पांच-पांच वार्ड जोड़ता है उन वार्डों को जोड़ने के लिए वो सड़कें जर्जर है, वहां तक छात्रों को, वहां के लोगों को जाने-आने में असुविधा होती है ।

अध्यक्ष : यह तो आप सूचना दे रहे हैं । इससे संबंधित प्रश्न पूछिए न !

श्री विजय कुमार खेमका: मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि ये सड़कें और यहां जो व्यवस्था है वह कब तक बनेगी ?

श्री महेश्वर हजारी: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो क्वेश्चयन किए हैं उसमें किसी रोड का स्पेसिफिक कोश्चयन नहीं किया गया है । महोदय, कोई सुविधा आधारभूत संरचना नहीं है तो जेनरल बोले हैं, व्यक्तिगत् कोई रोड का देंगे, कोई मुहल्ला का देंगे तो उसे हम दिखवाने का काम करेंगे, उसको करवाने का काम करेंगे ।

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी गिनाया, और मैं आसन को भिजवा सकता हूं । कम-से-कम 20 ऐसा मुहल्ला है जहां न बिजली है, न पानी है, न सड़क है...

अध्यक्ष : अलग-अलग वह सब आप लिखकर दे दीजिएगा । माननीय मंत्री जी उसको दिखवा लेंगे ।

श्री अशोक कुमार : एक हमारा सुझाव है अध्यक्ष महोदय । माननीय मंत्री जी विधान सभा में हमलोगों को आश्वस्त करें कि नगर पंचायत के चुनाव में माननीय सदस्य जो लिख कर देते हैं वही रोड स्वीकृत होता है । माननीय सदस्य उससे वंचित रहते हैं और यह जो योजना देना चाहते हैं वह हो नहीं पाता है इसलिए हम आपका संरक्षण चाहते हुए सारे विधायकों के तरफ से यह प्रस्ताव करता हूं कि माननीय विधायक डायरेक्ट मंत्री को जिन रोडों की अनुशंसा करके दें, उनमें यहां से पैसा भेजने का ये काम करें ताकि माननीय विधायकों के क्षेत्र में काम हो सके ।

अध्यक्ष : ठीक है, आप अपना सुझाव सरकार को दे दीजिए ।

श्री अशोक कुमार: अध्यक्ष महोदय, इस पर वक्तव्य दें मंत्री जी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य नन्द किशोर यादव ।

(व्यवधान)

श्री नन्द किशोर यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा मौजू सवाल खड़ा किया है । विधायकों के अधिकार लगातार कम होते जा रहे हैं महोदय । अब नगरीय क्षेत्र में विधायक की अनुशंसा पर न कोई सड़क बनने वाला है, न कोई गली बनने वाला है, न कोई नाली बनने वाला है चूंकि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना समाप्त हो गई । मुख्यमंत्री चापाकल योजना समाप्त हो गई और विधायकों का दर्द महोदय, आपके सामने झलक रहा है महोदय । यह सवाल किसी पार्टी के विधायक का नहीं है, यह विधान सभा के सारे सदस्यों का सवाल है । इन सारे सवालों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर क्या सोचती है ? विधायक कैसे काम करेगा ? विधायक कैसे लोगों का दिल जितेगा ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये । माननीय नन्द किशोर बाबू, केवल यही प्रश्न नहीं, हर प्रश्न सदन की प्रोपर्टी होती है । कोई प्रश्न एक माननीय सदस्य का नहीं होता है । इसलिए हर प्रश्न का अलग-अलग महत्व होता है और जहां तक यह प्रश्न श्री विजय कुमार खेमका जी का है, यह पूर्णिया नगर निगम से जुड़ा हुआ है । इसका विधायक किस कमिटी में है, नहीं है, इससे कुछ लेना-देना नहीं है ।

श्री नन्द किशोर यादवः है महोदय ।

अध्यक्ष : नहीं है ।

श्री नन्द किशोर यादवः है महोदय ।

अध्यक्ष : नहीं है ।

श्री नन्द किशोर यादवः है महोदय ।

अध्यक्ष : कैसे है ?

श्री नन्द किशोर यादवः है महोदय । विधायक लिख कर देगा, तब भी नहीं बनेगा महोदय। नई योजना में नहीं बनेगा महोदय । जब नगर विकास योजना समाप्त हो गई, चापकल योजना समाप्त हो गई ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप अगर उस प्रश्न को उठाते हैं तो उसके लिए अलग तरीका है । आप जानते हैं । आप जानते हैं उस बात को ।

(व्यवधान)

<u>प्रश्न संख्या-403 (श्री (मो0)नवाज आलम)</u>

(व्यवधान)

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्माः अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है । वर्त्तमान में आरा शहर में 14 अदद जलापूर्त्ति योजनाओं के माध्यम से जलापूर्त्ति की जाती है । कराए गए जल-जांच के आधार पर कुछ प्रभारी नलकूप 14अदद जलापूर्त्ति योजनाओं के जल में आर्सेनिक की मात्रा मानक के अन्तर्गत है । अतएव इनसे प्राप्त जल पीने योग्य है । भोजपुर जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर से प्रतिवेदन के आधार पर 09 फरबरी, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक सदर अस्पताल आरा में आर्सेनिक से प्रभावित मरीजों की संख्या शून्य है ।

2. उपरोक्त खंड मं स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री (मो0) नवाज आलमः महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि शुद्ध जल पेय के लिए पूरे भोजपुर में हाहाकार मचा हुआ है । माननीय महोदय, आपने आर्सेनिक के मामले में कुछ बातें रखने का काम किया है । मैं आपसे जानना चाहता हूं माननीय महोदय कि आरा शहर को शुद्ध पेयजल की आपूर्त्ति कब तक करेंगे और उनके समाधान के लिए उन समस्या, जो बीमारियां हैं, उसका कब तक निराकरण करेंगे ?

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्माः उसकी जांच कर ली गई है और जो रिपोर्ट आई है जांच का, उसमें ऐसी कोई खतरनाक बात नहीं कही गई है और वह जल पीने के योग्य है । कहीं

से भी कोई मरीज के प्रभावित होने की कोई सूचना नहीं है । इसलिए मुझे लगता है कि माननीय सदस्य की चिंता गलत है ।

श्री (मो0) नवाज आलमः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि अगर इस तरह की बात नहीं है तो जांच कमिटी बैठा दें और जांच कर लिया जाए । दूध-का-दूध और पानी-का-पानी हो जाएगा ।

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में भी यही समस्या है । इनकी बात बिल्कुल सत्य है ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूरा इलाका जो गंगा के किनारे का क्षेत्र है बड़ी समस्या है । उसके लिए माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए सदन के अंदर कि उसके लिए आपकी कोई योजना है सरकार के द्वारा कि कोई टेस्टिंग लैब की व्यवस्था है अलग-अलग क्षेत्रों में और अगर वहां पर इस तरह की योजना है तो कैसे हम पहल करें, इस विषय पर कैसे जानकारी करें । यह बड़ी समस्या है इन क्षेत्रों के लिए । पांच प्रतिशत पीने का शुद्ध पानी मिलता है । आज तक पीने का पानी हमारे यहां तो नहीं ही गया ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, पेयजल उपलब्ध कराना हमारे विभाग की प्राथमिकता है । इसलिए जहां अगर ज्यादा आर्सेनिक की समस्या है भी तो वहां पर जांच करा करके वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है । अगर पार्टिकुलर कोई खास जगह की बात है तो आप बताएं, हम उसको दिखवा लेंगे ।

<u>प्रश्न संख्या-404 (श्री विजय कुमार सिन्हा)</u>

श्री अवधेश कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि लखीसराय जिलान्तर्गत हलसी प्रखंड के नौमा तरारी गांव में पशु चिकित्सालय नहीं है । गांव के पशुओं का इलाज एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्य हलसी में कार्यरत पशु चिकित्सालय किया जाता है जिसकी दूरी 8कि0मी0 है । यहां डा0 रजनीश लाल पशु चिकित्सा का कार्य करते हैं ।

जहां तक बड़हिया प्रखंड के चेतनटोला खुटहा का प्रश्न है तो बड़हिया प्रखंड के खुटहा में पशु चिकित्सालय कार्यरत है । चेतनटोला का पशु चिकित्सालय खुटहा से मात्र दो किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है । उक्त पशु चिकित्सालय में डाक्टर अनूप कुमार पशु चिकित्सक के रूप में पदस्थापित हैं ।

2. उपर्युक्त कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

टर्न–3/राजेश/3.3.16

श्री विजय कुमार सिन्हा:– अध्यक्ष महोदय, जिस खुटहा की चर्चा हो रही है वह दियारा क्षेत्र है, न वहॉ अस्पताल कार्यरत है और न ही डाक्टर वहॉ जाते हैं और दूसरी चीज जिस नोमा की चर्चा किये हैं, तो वह 8 किलोमीटर, 10 किलामीटर है। इसलिए अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जनसंख्या का अनुपात जब बढ़ता है, तो मनुष्य के लिए अस्पताल बढ़ता है और पशु की जनसंख्या में कितनी वृद्वि हुई है और कितना अस्पताल होना चाहिए और कितना अभी है, यही जानकारी ये दे दें ।

श्री अवधेश कुमार सिंह:– माननीय सदस्य जी, आपका जो प्रश्न है,उस हिसाब से आपने इलाज की बात की है और इलाज में हमने स्पष्ट कहा कि दो जगह इलाज चल रहा है और दो डाक्टर जिसका नाम हमने आपको स्पष्ट बताया है, माननीय सदस्य अगर वहॉ ये दोनों डाक्टर नहीं रहते हैं, अगर आप इसकी सूचना सरकार को देंगे, तो सरकार जांच करायेगी और जहॉ तक नये हॉस्पिटल खुलने की बात है तो जो क्राईटेरिया अभी फिक्स्ड किया गया है, उस क्राइटेरिया में आगे हम कार्रवाई करेंगे ।

श्री विजय कुमार सिन्हा:– अध्यक्ष महोदय, यह चर्चित विभाग रहा है, बहुत चर्चा में रहा है, बिहार का बहुत नाम इससे हुआ है और इस विभाग के अंदर में माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से चुनौती देते हैं कि आप प्रखंड और जिला के अंदर इसकी जांच करा लें कि आपके कितना अस्पताल में गर्भाधान का कार्य चल रहा है और रोग के दवा की सूची क्या है, आप बता दें कि कौन–कौन सी दवा की सूची उपलब्ध है अस्पताल के अंदर, केवल खानापूर्ति करके जो जवाब वहॉ

से भेजा जाता है, उसकी जांच करा लें, किसी स्टेट लेवेल के पदाधिकारी को भेजकर इसकी जांच करवा लें ।

अध्यक्षः- माननीय मंत्री जी, आप जांच करा दीजिये ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः- महोदय, जांच तो करा देते हैं और अध्यक्ष महोदय को हम संतुष्ट भी करना चाहते हैं कि हलसी प्रखंड में 2013-14 में चिकित्सा-1991, बंध्याकरण-940, टीकाकरण-15500, गर्भाधान-20, उसीतरह 2014-15 में चिकित्सा-2331, बध्याकरण-226,, टीकाकरण-2100 एवं कृत्रिम गर्भाधान-250 एवं 2015-16 में चिकित्सा-1639, बंध्याकरण-62, टीकाकरण-2500 एवं गर्भाधान-109, उसी तरह खुटहा में 2014-15 में चिकित्सा-1238, बंध्याकरण-4 एवं 2015-16 में चिकित्सा-2174 एवं बंध्याकरण-48 ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए और जो बातें कही है विभाग के बारे में .....(व्यवधान)

अध्यक्षः- आप जांच तो करवा दीजिये ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः- जांच भी करवा देंगे अध्यक्ष जी ।

अध्यक्षः- ठीक है ।

श्री विजय कुमार सिन्हाः- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री के द्वारा जो ऑकड़े पेश किये गये हैं, हम अनुश्रवण के अध्यक्ष के नाते एक, डेढ़ महीना में बैठक लेते हैं और आपके विभाग के अधिकारी आकर रिर्पोट देते हैं, हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप जांच के माध्यम से सच्चाई से अवगत हो लेंगे और इसका लाभ पूरे बिहार को मिलेगा, सिर्फ ऑकड़ा का खेल प्रस्तुत करके जो सदन को गुमराह किया जा रहा है, इसकी जांच आप करा लें, यही हमारा आग्रह है माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे ।

अध्यक्षः- आप अच्छी बात कह रहे हैं, आप जांच करा दीजिये ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः- हम इसकी जांच करा देंगे और सदन को कभी भी गुमराह करने की कोशिश नहीं करेंगे ।

श्री रविन्द्र यादवः- अध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग का यह हालत है कि एक-एक डाक्टर 10-10 पोस्ट का प्रभार लिये हुए है, तो माननीय मंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि पशुपालन विभाग में डाक्टरों की बहाली के लिए कौन-सी कार्रवाई कर रहे हैं सर ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-405 (डा0 रामानुज प्रसाद)</u>

श्री महेश्वर हजारी:- अध्यक्ष महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि पहलेजा घाट स्थित शवदाह गृह का जीर्णोद्धार नमामी गंगे योजना में भेजा जाना प्रस्तावित है, इस हेतु बिहार राज्य जल पर्षद् द्वारा एक करोड़, 63 लाख, 73 हजार का प्राक्कलन बनाया गया है ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है। भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, नेशनल मिशन फॉर क्लिन गंगा एन0एम0सी0जी0 योजना से स्वीकृति प्राप्त होने पर जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया जायेगा ।

डा0 रामानुज प्रसाद:- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, ये कहते हैं कि प्राप्त होगा केन्द्र से, जब सैंक्सन होगा तब जाकर हम करेंगे, तो क्या सरकार पहल करेगी की जल्द से जल्द हो जाय ।

श्री महेश्वर हजारी:- महोदय, मैंने माननीय सदस्य को बताया कि एक करोड़, 63 लाख, 73 हजार का प्राक्कलन बन गया है, चूंकि वह चालू नहीं हो पाया था, यह आवश्यक है वहॉ के लिए, हमने इस काम के लिए अपने विभाग में कहा है कि जल्द से जल्द काम को प्रारंभ करें ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-406 (श्री विजय कुमार खेमका)</u>

श्री अब्दुल जलील मस्तान:- महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है। जिला मूल्यांकन समिति द्वारा राज्य के किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम मूल्यांकन की मार्गदर्शिका में वृद्धि नहीं की गयी है, मात्र शहरी क्षेत्र में जिला पदाधिकारी द्धारा पदाधिकारियों की टीम गठित कर सर्वेक्षण किया गया है, जिन स्थानों पर बाजार मूल्य अपेक्षाकृत अधिक है, वहॉ के न्यूनतम मूल्यांकन की मार्गदर्शिका पंजी पर नियमानुकूल वृद्धि की गयी है ।

श्री विजय कुमार खेमका:- अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो निबंधन शुल्क बढ़ा है, उसमें जो मूल्यांकन किया गया है मधुबनी मौजा, मुहल्ला-राजेन्द्रनगर, जिसका 3 लाख 50 हजार था, मूल्यांकन करने के बाद 5 लाख 50 हजार सीधे कर दिया गया है, यह शहर के एक मौजा का है, उसीतरह अनेक मुहल्ले है, जिनका दुगुना, तीगुना, चौगुना तक भैल्यूशन करके 60 प्रतिशत तक शुल्क बढ़ाया गया है, उसी तरह जो ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें फतेहपुर मौजा है, जिसकी प्रधान सड़क का मूल्य एक लाख 40 हजार था, उसका मूल्यांकन दो लाख 40 हजार किया गया है। अध्यक्ष महोदय एक साथ जो धरातल पर मूल्य का मूल्यांकन होना चाहिए, वह नहीं करके बिना किसी राय विचार के, बिना किसी आपत्ति दायर करके जो मंत्री जी ने

कहा कि वहॉ पर मूल्यांकन के लिए आपत्ति दावा भी रखा गया था, बगैर किसी को इसकी जानकारी दिये एक साथ इतना मूल्यांकन बढ़ा करके 67 से 60 प्रतिशत तक निबंधन शुल्क बढ़ाया गया है, इससे निबंधन में भी गुणात्मक कमी आयी है और राजस्व की भी क्षति हो रही है, मंत्री जी उसी क्षेत्र से है ।

अध्यक्षः- ठीक है । माननीय मंत्री जी सुन लीजिये । माननीय मंत्री जी इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ाया गया है ।

टर्न-04/कृष्ण/03.03.16

श्री अब्दुल जलील मस्तान : नहीं,नहीं । माननीय सदस्य को मालूम नहीं है ग्रामीण क्षेत्र क्या है और शहरी क्षेत्र क्या है ? (व्यवधान)

मेरा कहने का मतलब यह है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र क्या होता है । आप अपनी बात कहिये ।

श्री अब्दुल जलील मस्तान : मैं यह कह रहा हूं एक तो शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र के बगल में पेरिफेरियल इलाका है । इन दोनों इलाके में भौतिक जांच कर के वहां का एम0वी0आर0 अगर बाजार मूल्य से बहुत कम है तो वहां बढ़ाया गया है । शहरी क्षेत्र में और पेरिफेरियिल इलाके में ही बढ़ाया है और बढ़ाने का जो नियम था, जिला पदाधिकारी के माध्यम से एक कमिटी गठित करके वहां उसको बढ़ाया गया है । फिर आपत्ति के लिये एक डेट रखा गया था कि 15 दिनों के अंदर अगर किसी व्यक्ति को इस दिशा में कुछ कहना है तो वह कहेंगे । उसके बाद ही वहां फिक्स किया जाता है । इसलिए मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि आपका जो दावा है कि शहरी क्षेत्र में बढ़ाया है लेकिन ऐसी कोई बात नही है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य खेमका जी, आपने जो अभी उदाहरण दिया, जहां-जहां जिस-जिस मुहल्ले में बढ़ा है तो आपने बढ़ोत्तरी का प्रतिशत 60 से 70 प्रतिशत तक अधिकत्तम बताया। तब आप प्रश्न में 4 गुणा का क्यों जिक्र कर दिये ?

श्री विजय कुमार खेमका : शुल्क में 60 प्रतिशत हुआ है ।

अध्यक्ष : हमारा सिर्फ यही कहना है, आपकी बात सही है लेकिन जो आप प्रश्न पूछते हैं उसको भी वास्तविकता के जितना नजदीक रखेंगे, उतना ही फायदा होगा ।

श्री विजय कुमार खेमका : कहीं दो गुणा है, कहीं 4 गुणा है, अधिकत्तम 4 गुणा है ।

अध्यक्ष : आपने जो उदाहरण दे दिया, उसमें आप ही ने कहा कि 60 से 70 प्रतिशत तक बढ़ा है।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने मौजा बताया, उस मौजे में चार गुणा है,चार गुणा अधिकतम था।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी को आप दे दीजियेगा, ग्रामीण क्षेत्र में जहां बढ़ा है।

श्री प्रेम कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में जिस तरह मनमाने तरीके वृद्धि की जा रही है,पूर्णियां तो उदाहरण है । माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, कई गुण बढ़ाया गया है । सरकार की क्या नीति है ? क्या हर साल 4 गुणा, 6 गुणा बढ़ाने का है ? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आपने जो डी0एम0 को वृद्धि करने का अधिकार/प्रस्ताव दिया है तो सरकार की क्या नीति है ? क्या हर वर्ष 4 गुणा, 6 गुणा बढ़ाने की नीति है ?

श्री अब्दुल जलील मस्तान : महोदय, 10 परसेंट से 50 परसेंट तक वृद्धि हुई है । आप जो बोलते हैं 3 गुणा, 4 गुणा यह बात सही नहीं है ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, जो हर वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में जो 10 डीड होता है उसका जो ज्यादा से ज्यादा मूल्यांकन होता है, उसी पर 20 परसेंट अतिरिक्त जोड़ा जाता है। महोदय, हर साल बराबर वित्तीय वर्ष से पूर्व 2 गुणा, 3 गुणा वृद्धि कर दिया जाता है । पूरे राज्य का यह मामला है । केवल पूर्णियां का मामला नहीं है । शादी-विवाह, मरनी-जीनी में लोग अपनी जमीन बेचते हैं, कुछ करते हैं, उसमें लोगों को भारी परेशानी हो रही है । वे अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं । सारा ऐसा जमीन है, जिसका जमीन अगर 10 हजार है, वहां मूल्यांकन 40 हजार कर दिया गया है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब को चुनौती देता हूं, दरभंगा में जांच करा लें, । 2 गुणा, 3 गुणा बहुत सारे मुहल्ले में है।

अध्यक्ष : आप दे दीजियेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 407 (श्री राज कुमार राय)</u>

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री चापाकल योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2015-16 के लक्षित कुल 570 चापाकल के विरूद्ध 527 चापाकल का निर्माण प्लेटफार्म के साथ माननीय सदस्य की अनुशंसा पर किया जा चुका है । कुछ जगहों पर चापाकल की मरम्मति की आवश्यकता पड़ती है, उसको ठीक करा कर चापाकल को चालू करा दिया जाता है ।

3. वर्ष 2014-15 के लक्ष्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री चापाकल योजना के अंतर्गत निर्मित चापाकलों में से अवशेष 45 अदद चापाकलों में नाली एवं प्लेटफार्म का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जायेाग ।

4. उपर्युक्त खंडों के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री राज कुमार राय : महोदय, मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि वास्तव में चापााकल गड़बड़ है । गर्मी का समय है । विद्यालय में मैंने अक्सर चापाकल देखा है, जिसको अनुशंसा किये हैं , अक्सर चापाकल बंद रहता है । मैंने कई बार पदाधिकारी को भी बताया कि बंद है, उसको ठीक कराईये । लेकिन आज तक वह ठीक नहीं किया है । मेरे समझ से संवेदक और पदाधिकारी जो दोषी है, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाय । सैकड़ों चापाकल बंद है और रिपोर्ट कर दिया जाता है कि ठीक है । मेरे क्षेत्र की बात है । हमलोग घूम-घूम कर देख रहे हैं । प्लेटफॉर्म आज तक नहीं बने हैं । इसलिए मैं चाहूंगा सदन के माध्यम से कि दोषी पर कार्रवाई की जाय और बंद पड़े चापाकलों को चालू कराया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या दोषियों पर कार्रवाई किया जायेगा ?

श्री कृष्णनन्दन वर्मा : माननीय सदस्य द्वारा अगर किसी स्पेसिफिक दिया जायेगा तो हम उसको दिखवा लेंगे । लेकिन सामान्य रूप से गर्मी आने के पहले सब जगह मिस्त्री के द्वारा ठीक करवा दिया जाता है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपने तो भले कहा कि जहां का माननीय सदस्य देंगे, वहां का आप जांच करवा लीजियेगा । आगे आप क्यों बढ़ते जा रहे हैं ?

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 408 (डा0 अशोक कुमार)</u>

श्री कृष्णनन्दन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, 1 उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत शिवाजी नगर प्रखंड के तहत बल्लीपुर ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना के पुनर्गठन की स्वीकृति वर्ष 2010-11 में दी गयी थी । इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 4 एजेंसियों को आवंटित किया गया था । इस योजना में बोरिंग का कार्य पूर्ण होने के उपरांत सोलर पम्प सेट भी अधिष्ठापित कर दिया गया है । जलापूर्त्ति की जांच कर ली गयी है । परन्तु पाईप लाईन के विशेष मरम्मति का कार्य अभी अधूरा रहने के फलस्वरूप जलापूर्त्ति पूर्णतः चालू नहीं हुआ है । जल मीनार निर्माण का कार्य भी अधूरा है। पाईप लाईन एवं जल मीनार के अधूरे कार्य को शीघ्र पूरा कराकर योजना को चालू करने हेतु संवेदक को निर्देश दे दिया गया है ।

डा0अशोक कुमार : महोदय, इन्होंने कहा कि पाईप लाईन का कार्य अधूरा है । पाईप लाईन जो भी बना, वह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, लीकेज और जर्जर हो चुका है । यह 25 साल पहले बना था । जल मीनार के लिये 6 पोल खड़ा है और मीनार का काम अधूरा है । क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि विलंब का क्या कारण है और उस दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करेंगे जांच कराकर ?

श्री कृष्ण नन्दन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कहीं-कहीं पर ऐसा होता है कि संवेदक की लापरवाही से काय्र पूर्ण नहीं हो पाता है ।

अध्यक्ष : वही तो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अगर इस योजना में भी संवेदक की लापरवाही से ऐसा हुआ है तो आप उसकी जांच कराकर कार्रवाई कीजिये ।

श्री कृष्ण नन्दन वर्मा : मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि मैं इसकी जांच करा लुंगा और रिपोर्ट से माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा।

डा0 अशोक कुमार : महोदय, इस योजना का कार्यान्वयन कब तक कराने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : आप का क्या है ?

श्री रविन्द्र यादव : जहां-जहां जल मीनार तैयार है और जलापूर्त्ति नहीं हो रही है, ऐसी जगहों पर पानी की आपूर्त्ति कराना चाहते हैं ?

श्री कृष्ण नन्दन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अवगत होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री के 7 निश्चिय में मेरा भी एक निश्चय है । मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि युद्ध स्तर पर काम कराया जायेगा और हर गांवों को जलापूर्त्ति की जायेगी ।

टर्न-5/सत्येन्द्र/4-3-15

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ये पूछ रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ करियेगा?

श्री कृष्णनन्दन प्र0 वर्माः अगले वित्तीय वर्ष में।

तारांकित प्रश्न संख्या- 409

श्री महेश्वर हजारीः अध्यक्ष महोदय(1)उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन टी-01 से शेरपुर पथ पर स्थित है। पथ की लम्बाई 3.283 कि0मी0 है। पाईप फैक्ट्री के पास एक 1x4mx3m की आर0सी0सी0 पुलिया पूर्व से निर्मित है। इसकी गुणवत्ता संतोषप्रद है। पुल का पारापेट टूट गया है। प्रधानमंत्री ग्राम

सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन पथ के निधि से 15 दिनों में पुल के पारापेट का निर्माण करा दिया जायेगा।

डॉ0 विनोद प्रसाद यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्णित पुल का स्थल नगर पंचायत क्षेत्र शेरघाटी में है और उक्त पुल के पास से ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण किया जा रहा है और माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि पुल क्षतिग्रस्त है इससे आये दिन दुर्घटनाएं हो जाती है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या उक्त पुल का निर्माण राज्य योजना मद से करवाने का विचार रखती है?

श्री महेश्वर हजारी: चूंकि वहां के जिला समाहर्त्ता से रिपोर्ट पूछे थे तो जिला समाहर्त्ता ने रिपोर्ट दिया था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना है और गारंटी पीरियड रोड का है इसलिए 15 दिनों के अन्दर में वो वोले हैं कि उसको बनवा देंगे। माननीय सदस्य को जब समय 15 दिनों का दे रहे हैं, उसके बाद नहीं होगा तो बात कीजियेगा हमसे।

तारांकित प्रश्न संख्या- 410

श्री कृष्णनंदन प्र0 वर्मा: अध्यक्ष महोदय,इस प्रश्न का जवाब तैयार नहीं हो सका है, इसका अगले दिन देंगे। समय चाहिए।

अध्यक्ष: स्थगित हुआ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 411

श्री राजीव नंदन: पूछते हैं।

अध्यक्ष: श्री राजीव नन्दन जी,सदन की परम्परा है कि लोग कहते हैं मैं पूछता हूँ, पूछते हैं नहीं, मैं पूछता हूँ।

श्री कृष्णनन्दन प्र0 वर्मा: मैं बताता हूँ।

अध्यक्ष महोदय,(1)आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत गुरूआ ग्रामीण पाईप लाईन का कार्य पूर्ण है। जलापूर्त्ति चालू है परन्तु सड़क निर्माण के क्रम में पाईप लाईन 5 जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे एक माह में मरम्मति कराकर जलापूर्त्ति पुन: सुचारू रूप से चालू कर दी जायेगी। गुरारू ग्रामीण पाईप जलापूर्त्ति योजना में जलमीनार एवं पाईप लाईन का कार्य पूर्ण है एवं योजना आंशिक रूप से चालू है। पाईप लाईन में 8 स्थानों पर लिकेज है जिसकी मरम्मति कराकर पेयजल आपूर्त्ति 15 दिनों में सुचारू रूप से चालू करा दिया जायेगा। परैया ग्रामीण पाईप जलापूर्त्ति योजना में वितरणी प्रणाली का कार्य, जलमीनार निर्माण का कार्य पूर्ण कर चालू की गयी है। पाईप लाईन में 6 स्थानों पर

लिकेज है जिसकी मरम्मति 20 दिनों में कराकर सुचारू ढंग से जलापूर्त्ति करा दी जायेगी।

श्री राजीव नंदन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब से हम संतुष्ट हैं लेकिन आसन की ओर से प्रश्न है कि आसन का विश्वास चूंकि यह प्रश्न सदन में उठा है और यह प्रश्न उठने का मतलब है कि जनता को एक महीने के बाद पानी मिल जायेगा इन क्षेत्रों में। आसन क्या आश्वस्त करता है कि एक महीने में पानी मिल जायेगा?

अध्यक्ष: राजीव नंदन जी, आप बैठ जाईए। जब कोई दूसरा बोलता है तो सदस्य बैठ जाते हैं। दूसरी बात, सदन में माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं, पूरक पूछते हैं और सरकार उत्तर देती है और आपको संतुष्ट उसी से होना पड़ता है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 412

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय,(1)उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिला में वर्त्तमान में 6 पशु चिकित्सक पदस्थापित हैं जो जिला में पशु चिकित्सा का कार्य करते हैं। अभी तक उक्त जिला में पशु चिकित्सा के अभाव में मवेशी की मरने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री शकील अहमद खां: महोदय,डिमांड के अनुसार सप्लाई जरूरी है। पशुओं की चिकित्सा के लिए जितनी डॉक्टर की जरूरी है उसकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है जिस कारण सही समय पर पशुओं को दवाई बगैरह नहीं मिल पाती है और जबतक चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं होगी तबतक ये मसला हल नहीं हो पायेगा। नियुक्ति का मामला सिर्फ एक जिले का नहीं, हर जिले का है। नियुक्ति जितना हमारा डिमांड है उस लिहाज से आपको करना चाहिए और सरकार को करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा इससे तमाम जिलों में आप पशु चिकित्सक को और साथ -साथ दवाईयों का इंतजाम सही तौर पर सही समय पर कर पायें। यह पूरे बिहार में नहीं है।

...

तारांकित प्रश्न संख्या- 413

श्री मदन सहनी: अध्यक्ष महोदय,(1)अस्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि महाराजगंज अनुमंडल के गोरैयाकोठी विधान-सभा क्षेत्र गोरैयाकोठी क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर सर्वेक्षित सुविधा प्राप्त परिवारों को राशन किरासन कार्ड एवं कूपन उपलब्ध कराया जा चुका है। पुन: द्वितीय

चरण में बंधे हुए कुछ अतिरिक्त परिवारों को राशन कार्ड एवं कूपन उपलब्ध कराया गया है। इस डाटा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् लाभूक परिवारों की विवरणी निम्नवत् है- विधान-सभा क्षेत्र गोरियाकोठी, प्रखंड बसंतपुर कुछ गृहस्थि की संख्या 17061, लाभूक परिवारों की संख्या 13411 और प्रतिशत 78.60, गोरियाकोठी गृहस्थि की संख्या 36982 लाभूक परिवारों की संख्या 26505 और प्रतिशत 71.67, लकरी नवीगंज 21051 गृहस्थि परिवार की संख्या, लाभूक परिवार की संख्या 16885, प्रतिशत 80.20 लगभग 75.63 प्रतिशत परिवारों को अच्छादित किया गया है फिर भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बचे हुए शेष लाभुक परिवारों को लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत विहित प्रपत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर आवेदन देकर जांचोपरांत सही पाये जाने पर सूची में नाम उनका जोड़ा जायेगा।

टर्न-6/मधुप/03.03.16

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 413 का पूरक</u>

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री से पूछना चाहता हूँ, मैंने संख्या नहीं पूछा था कि बसंतपुर प्रखंड में कितने उपभोक्ता हैं, लकड़ी नवीगंज में कितने हैं और गोरेया कोठी में कितना है । मैं यह पूछना चाह रहा था कि 40 प्रतिशत लोग जो वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे हैं, क्यों वंचित हैं ? अगर वंचित हैं तो उनको सूचीबद्ध करने के लिए आप कौन-सा उपाय करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उनका पूरक सही है इस मायने में कि प्रश्न ही यही था कि जो छूटे हुये हैं....

श्री मदन सहनी : महोदय, मैंने उसका विस्तार से जवाब इसलिये देना मुनासिब समझा, उन्होंने कहा कि 40 प्रतिशत लोगों का नाम छूटा हुआ है जबकि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 85 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत लोगों को इस योजना से जोड़ना है।

श्री सत्येदव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । यह 75 परसेंट और 80 परसेंट का प्रश्न नहीं बनता है । प्रश्न यह बनता है कि छूटे हुये 40 प्रतिशत कैसे जुटेंगे और 40 प्रतिशत गलत जो जुटे हैं, कैसे हटेंगे, ? जॉच की क्या व्यवस्था करेंगे ? क्या विधान सभा की समिति के द्वारा करायेंगे या किसी वरीय पदाधिकारी से उन गरीबों के हित में कार्रवाई करेंगे ? क्योंकि घोर अन्याय हुआ है ।

हमारा जो 7 निश्चय है, यह सरकार गरीबों के बलबूते पर बनी है और आने वाले दिन में भी बनेगी । गरीबों के हित में कार्रवाई करने की घोषाणा करें । 40 प्रतिशत छूटे हुये गरीबों को कैसे जोड़ेंगे और जो गलत ढंग से जुटे हैं, कैसे उन्हें हटायेंगे ?

श्री मदन सहनी : महोदय, जैसा कि हमने बताया, इनकी चिन्ता यही है कि 40 प्रतिशत गरीबों का नाम छूटा हुआ है....

अध्यक्ष : उनकी चिन्ता प्रतिशत पर नहीं है, उनकी चिन्ता है कि जो लोग छूट गये हैं, उनको किस प्रक्रिया से कितने दिन में आप दे दीजियेगा ।

श्री मदन सहनी : अध्यक्ष महोदय, उसका भी जवाब हमने..... (व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये न ! नेता विरोधी दल ।

श्री प्रेम कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि सीवान जिले के गोरेया कोठी विधान सभा क्षेत्र में 40 फीसदी लोग आज भी राशन से वंचित हैं जो महादलित हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, सवर्ण जाति के जो गरीब हैं, ऐसे तमाम लोग जो छूट गये हैं, उनको जोड़ने का उन्होंने आग्रह किया था और सर्वे कराने के बारे में कहा ।

महोदय, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सारे मेम्बर कह सकते हैं कि पूरे बिहार में जो सर्वे हुआ है, उसमें आधे से अधिक लोग छूट गये हैं तो क्या सरकार नये तरीके से सर्वे कराकर एक समय-सीमा के अन्दर छूटे हुये अति पिछड़ा, महादलित, सवर्ण जाति के गरीबों को जोड़ने का विचार रखती है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हो गया न ! जवाब होने दीजिये न !

श्री प्रेम कुमार : महोदय, पहले जवाब तो करवा दीजिये ।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, पहले तो प्रश्नकर्त्ता जो सदस्य हैं, उनके सवाल का जवाब होगा, तब न नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछेंगे और माननीय सदस्य पूछेंगे ! यही नियम और यही परम्परा रही है कि पहले जो प्रश्नकर्त्ता हैं, उनके प्रश्न का जवाब होगा तब कोई माननीय सदस्य उसपर सवाल को पूछेंगे । यह सदन की प्रोपर्टी है लेकिन नियमबद्ध तरीके से उसपर सवाल पूछे जायेंगे ।

श्री मदन सहनी : अध्यक्ष महोदय, जैसा हमने बताया कि जिनका भी नाम इस योजना में छूटा हुआ है, उनको प्रखण्ड स्तर पर आर0टी0पी0एस0 काउंटर के माध्यम से यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है । इस योजना में.... (व्यवधान) जवाब तो सुन लिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, पहले पूरी बात तो मंत्री जी की सुन लीजिये ।

श्री महबूब आलम : हमलोगों को भी पूछने का समय दिया जाय ।

श्री मदन सहनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमने बताया, जो माननीय सदस्य का सवाल है, उसका हमने स्पष्ट जवाब दिया, उनका कहना है कि 40 प्रतिशत लोगों का नाम छूटा हुआ है, हमने जोड़ने का भी उपाय बताया है और जिस प्रखंड का उन्होंने चर्चा किया है, उसमें कितने गरीबों का नाम जोड़ा गया है, उसका क्या प्रतिशत है, हमने प्रखंडवार उसको बता दिया है । रही बात अन्य जगहों का, तो हमने अभी स्पष्ट बताया जवाब में कि जो भी लोगों का नाम इस योजना में छूटा हुआ है, वैसे लोग प्रखण्ड स्तर पर आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर जाकर अपना आवेदन देंगे और उसमें उस लाभुक को अगर उस लायक समझा जायेगा तो उनका नाम जोड़कर उसका लाभ दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री महोदय, यही प्रक्रिया आपको बतानी थी न ! यही प्रक्रिया तो उस समय से पूछी जा रही थी ।

श्री प्रेम कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है, सही कहा है कि प्रक्रिया यही है लेकिन हम बताना चाहते हैं कि पूरे राज्य के अन्दर बड़ी संख्या में गरीबों ने फॉर्म भरकर जमा करने का काम किया है और वर्षों से उसकी जॉच नहीं करायी जा रही है । आपके माध्यम से हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जो पब्लिक का लम्बित पेटीशन है गरीबों का, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का, महादलितों का, सवर्ण जाति के गरीबों का और समाज के सभी वर्ग के लोगों का, निश्चित तौर पर आप बताइये कि कबतक लम्बित आवेदनों की जॉच कराकर, सर्वे कराकर उनको सूची में डालने का काम करेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य राम नारायण मंडल जी ।

श्री राम नारायण मंडल : महोदय, सरकार को निदेशित किया जाय कि एक अभियान चलाकर जो छूटे हुये लोग हैं उनको समयसीमा निर्धारित करके उनकी अवधि बॉध दी जाय और उसमें निष्पादन करने का काम ये करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, महबूब आलम जी ।

श्री महबूब आलम : महोदय, सच बात यही है कि गॉव में हजारों की संख्या में खेत मजदूर, गरीब जिसके पास 3 डिसमल अपनी जमीन अपने बसोवास के लिये नहीं है, जो जमींदारों की जमीन पर बसोवास करते हैं, उनके उजड़ने और बेदखली का समस्या पैदा हो गया है, उन लोगों का हजारों की संख्या में, आसन अगर हमें आदेश देगा तो हम उसका नाम देंगे कि वे बिल्कुल गरीब हैं, न उनका नाम ए0पी0एल0 में है और न ही उनका नाम बी0पी0एल0 में है । ऐसे लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का कोई

लाभ नहीं मिल पाता है । ये लोग जब आते हैं तो हमलोगों की रुह कॉप जाती है, सरकार की रुह कॉपती है या नहीं ? ये कब करेंगे और कैसे करेंगे ? समय निर्धारित किया जाय । यह पूरे बिहार के गरीबों का सवाल है और इस सरकार को गरीबों का मैनडेट मिला है । एक डेट निर्धारित किया जाय, महोदय । आसन आश्वस्त करे कि छूटे हुये गरीबों का नाम बी0पी0एल0 में जोड़ा जायेगा और जो अमीरों का नाम जोड़ा गया है, उनको काटा जायेगा ।

(इस अवसर पर पक्ष-विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर खड़े हो गये)

अध्यक्ष : महबूब आलम जी, हमने आपको पूरक पूछने के लिये आमंत्रित किया था और आप अपनी पूरी बात कहने लगे ! एक मिनट, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाइये ।

माननीय मंत्री ने कहा है और उनके उत्तर से ही स्पष्ट था कि सब जगह कुछ-कुछ लोग छूटे हुये हैं, सरकार मानती है कि छूटे हुये हैं इसीलिये तो सरकार ने प्रक्रिया निर्धारित की है कि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जो छूटे हुये लोग हैं वे आवेदन देंगे और सरकार उसपर कार्रवाई करेगी । (व्यवधान)

पूरी बात सुनते नहीं हैं ! पूरी बात जबतक नहीं सुनेंगे तो प्रश्न का क्या हश्र होगा ? आप अगर सरकार की पूरी बात न सुनेंगे और न समझेंगे तो आपके पूरक या प्रश्न का हश्र क्या होगा ? सरकार कह रही है कि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उन्होंने व्यवस्था की है । जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा और आप लोग भी कह रहे हैं कि अगर आर0टी0जी0एस0 में आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है जो आर0टी0जी0एस0 में जो अप्लाई किया गया है, उसमें रिसीट मिलता है, उसकी संख्या के साथ आप सरकार को शिकायत करिये, जॉच कराकर सरकार कार्रवाई करेगी । सीधी बात है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण खड़े हो गये ।)

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मेरा आपसे निवेदन है । इस प्रश्न की गम्भीरता आपके भी ध्यान में आया है, यह पार्टी और क्षेत्र की सीमा से ऊपर उठकर माननीय विधायकों ने इसके बारे में चर्चा की है । ...क्रमशः...

श्री नन्दकिशोर यादव : (क्रमशः) आप जानते हैं महोदय, इस बार बजट सत्र में इस विभाग पर कोई डिवेट भी नहीं होना है और इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे आग्रह होगा कि इसको स्पेशल डिवेट में तब्दील कर दीजिए ताकि विधायक अपने क्षेत्र के समस्याओं के बारे में बता सकें और उसका समुचित निदान हो सके, मेरा आपसे यह आग्रह है ।

अध्यक्ष : सरकार ने सब कुछ बता दिया है ।

श्री मदन सहनी : जब विभाग जवाब देने में सक्षम है तो अध्यक्ष महोदय इसको स्थगित क्यों कीजियेगा ।

अध्यक्ष : बैठिए ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़ी स्पष्टता से बताया कि सरकार की प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है । मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो सरकार ने 85 प्रतिशत देहाती क्षेत्र में और 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न देने की व्यवस्था की है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार उन गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम करती है, यह माननीय मंत्री महोदय बतावें ।

(व्यवधान)

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, आज गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है और यह सरकार गरीबों के यहां बनाज पहुँचाने का भी काम नहीं कर रही है, बीच में बिचौलिया मालामाल हो रहा है, गरीब त्रस्त हो रहा है लेकिन यह सरकार कान में तेल डालकर सो रही है । मेरा आग्रह होगा कि इसपर स्पेशल डिवेट कराईए ताकि सभी चीजें जनता के सामने आ सके । सरकार यह सुनिश्चित करे कि 2रू0 किलो गेहूँ और 3 रू0 किलो चावल गरीबों तक अनाज पहुँचे, यह करना आवश्यक है महोदय ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीट पर खड़े हो गये)

श्री प्रेम कुमार : अध्यक्ष महोदय, काफी गंभीर मामला है, सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। इसके कारण राज्य के बड़ी संख्या में गरीब राज्य में राशन-किरासन से वंचित हो रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि हाऊस को ऑर्डर में ले करके महोदय, सरकार को निदेश दें कि सुनिश्चित कराये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, महबूब आलम जी, बैठिए, ललन जी बैठिए । माननीय मंत्री जी ने अपनी बात बता दी है, आप बैठिए न, सब बैठे तो आप खड़े हो गये ।

श्री विनोद कुमार सिंह : महोदय, मैं सूचना पर हूँ ।

अध्यक्ष : क्या सूचना दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न सं0-414 माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-414 (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह,स0वि0स0)

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला के नवीनगर एवं बारूण प्रखंड के विभिन्न ग्रामों में क्रमशः 3445 अदद एवं 2069 अदद चापाकल निर्मित है । इनमें से नवीनगर एवं बारूण प्रखंड में क्रमशः 459 एवं 145 पूर्व में निर्मित पुराने चापाकल बन्द हैं । साधारण मरम्मती के अभाव में बन्द चापाकलों की मरम्मती कराकर शीघ्र चालू किया जायेगा ।

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर-काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

कार्यस्थगन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 03 मार्च,2016 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कुल 4 कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय सदस्य श्री संजीव चौरसिया एवं माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार ।

श्री नन्दकिशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि कार्य-स्थगन के विषय को तो बता दीजिए कि किस विषय पर कार्य-स्थगन दिया गया है ।

अध्यक्ष : यह बिहार विधान सभा के तृतीय अनुपूरक विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण कार्य विभाग के अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद, मतदान एवं शेष मांगों के लिए गिलोटिन के द्वारा मांग की स्वीकृति के लिए आज कार्यक्रम निर्धारित है । उसमें जो माननीय सदस्य जिस विषय को उठाना चाहते हैं, वे उठा सकते हैं ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 176(3) के तहत उपर्युक्त सभी कार्यस्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है ।

शून्य-काल । माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह ।

श्री अशोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो उत्पन्न स्थिति है, उसपर इस सदन में बहस करायी जाय, इसके लिए महोदय समय निर्धारित किया जाय ।

अध्यक्ष : जे0एन0यू0 में जो स्थिति है, उसको किस बात पर ।

श्री अशोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार की हार की खीझ इसी से पता चलता है कि बिहार के लड़के जहां भी है, कन्हैया कुमार को बिना साक्ष्य के इन लोगों ने प्रताड़ित करने का काम किया है और माननीय उच्च न्यायालय,दिल्ली ने साक्ष्य के अभाव में बेल देने का काम किया है और इसी तरह से हैदराबाद में रोहित वेमुला को आत्महत्या करने पर इन लोगों ने मजबूर किया है.....

अध्यक्ष : आप अशोक जी .....

श्री अशोक सिंह : ये पूरे देश में जहां-जहां बिहार के लड़के हैं, वहां पर प्रताड़ित कर रही है केन्द्र सरकार महोदय और ये पूरे देश में शिक्षा को भगवाकरण करना चाहते हैं । इसलिए मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस विषय पर अलग से समय निर्धारित करके वाद-विवाद कराया जाय महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह ।

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, कैमूर जिलान्तर्गत किसानों का धान आज तक सरकार द्वारा क्रय नहीं किया गया है, बिचौलियों के माध्यम से धान लिया जा रहा है । क्रय किये गये धान का भुगतान भी लंबित है । किसानों का धान सरकार द्वारा क्रय किये जाने की मांग करता हूँ ।

महोदय, 1,50,000मे0टन धान खरीदने का लक्ष्य कैमूर जिला का है । एस0एफ0सी0 को 15000 एम0टी0 धान खरीदना है महोदय, 15000 में एक भी एम0टी0 धान नहीं खरीदा गया है और यहां तक कि रामगढ़ व्यापार मंडल का मुख्यालय रामगढ़ में है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार ।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, राज्य के पंचायती चुनाव में पिछड़े वर्ग के 19 जातियों को अति पिछड़े वर्ग में एवं अतिपिछड़े वर्ग के 4 जातियों को अनुसूचित वर्ग में सम्मिलित किये जाने के कारण मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अतिपिछड़ा वर्ग को 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित वर्ग को 20 प्रतिशत आरक्षण पंचायती चुनाव में उपलब्ध करायी जाय ।

महोदय,.....

अध्यक्ष : आपने तो मांग कर दिया ।

श्री प्रेम कुमार : सरकार का वक्तव्य चाहिए इस मुद्दे पर , बहुत गंभीर मुद्दा महोदय है ।

अध्यक्ष : ठीक है, आपने भी इस मुद्दा को उठाया था ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, राज्य की 40 प्रतिशत आबादी अतिपिछड़ों का है और 20 प्रतिशत आबादी महादलितों का है । हमलोगों ने सरकार से आग्रह किया था कि पंचायत का चुनाव शुरू हो गया है, 20 प्रतिशत आरक्षण जो वर्तमान में है, इसको 30 प्रतिशत करने का और महादलितों को 16 से 19 करने का । हम सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि सरकार का वक्तव्य इसपर हो ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, 18 अगस्त, 2014 को गोपालगंज जिले के सिधवलिया प्रखंड में गंडक छरकी टूटने के कारण आयी भीषण बाढ़ में हजारों किसानों की फसलें नष्ट हो गयीं और 2013 में सूखा पड़ने से किसान प्रभावित हुए । वर्ष 2013 में के0सी0सी0 ऋण लेकर खेती करने वाले प्रभावित किसानों का सम्पूर्ण ऋण माफ किया जाये ।

महोदय, यह बड़ा संवेदनशील मामला है, आज बैंकों द्वारा किसानों को परेशान किया जा रहा है । वर्ष 2013 में सूखा पड़ गया और 2014 में बाढ़ आ गयी और जिन किसानों ने के0सी0सी0 ऋण लेकर खेती किया, वे आज पैसे देने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि किसानों का ऋण माफ किया जाय ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, पी0एम0सी0एच0 के आर्थो डिपार्टमेंट में Image Intensifier Machine विगत दो वर्षों से नहीं रहने के कारण मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । मैं आपके माध्यम से सदन से मांग करता हूँ कि आर्थो डिपार्टमेंट में Image Intensifier Machine शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, 1 मार्च, 2016 को पूर्णियां के रूपौली तेलडीहा सड़क पर दिन-दहाड़े हरनाहा गांव के किसान जय प्रकाश मंडल को खेत से वापसी लौटने के दौरान बेखौफ अपराधियों ने गोली मार दी है ।

अध्यक्ष महोदय, जिले में बढ़ते अपराध पर रोक लगे एवं अपराधी की शीघ्र गिरफ्तारी हो, मैं इसकी मांग करता हूँ ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत डिहरी, यदुनाथपुर से एन0एच0-2सी रोड से सी0आर0पी0एफ0कैम्प, भरूई मुआरा होते हुए भाया ताराडीह कौड़ीयारी तक लगभग 7 किलोमीटर सड़क नहीं है ।

हम सरकार से मांग करते हैं कि इन दर्जनों गांवों को रोड से जोड़ने की व्यवस्था करें ।

अध्यक्ष महोदय, यह पूरा अति पिछड़ा आदिवासियों का गांव है, आजादी के 67 सालों के बाद भी जंगल तक जाने का कोई सड़क नहीं है, इसलिए शीघ्र इसका निर्माण कराया जाय ।

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत मनिहारी प्रखंड के मैहारपुर गांव में मंजीत सिंह फौजी को बुरी तरह पीटा गया, तत्पश्चात् अपराधियों द्वारा गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई । अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, पुलिस अपराधी को पकड़ने में अक्षम साबित हो रही है ।

अत: अपराधी के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कानूनी कार्रवाई की जाय ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, कटिहार नगर अंतर्गत ललियाही एवं हृदयगंज में 33 हजार वोल्टेज का हाईटेंशन तार गुजरने के कारण स्पर्शाघात से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है एवं दोनों मुहल्लों के निवासी प्रथम तल पर निर्माण कार्य नहीं कर रहे है एवं भारी दहशत में हैं ।

अतएव सरकार अविलम्ब हाईटेंशन तार हटाने की कार्रवाई करे ।

श्री सजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, गंभरी विषय है, आपका संरक्षण चाहिए । 2 मार्च को, 25 फरवरी से चोरी के आरोप में दरभंगा कारा में बंद तृतीस सेमेस्टर लॉ का निर्दोष छात्र विवेक गुप्ता द्वारा मंडल कारा में अपराधियों द्वारा जेल प्रशासन की मिलीभगत से रंगदारी और प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की कोशिश की, मैं जांच कर दोषी पर कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभरी विषय है, 24 तारीख को 91/16 सदर कांड संख्या में एक चोरी हुई और ये स्टेशन से अपने मित्र को लेकर आ रहे थे और अध्यक्ष महोदय, लॉ का छात्र है, दिल्ली यूनिविर्सिटी का छात्र, ये निर्दोष था, पुलिस ने इसको पकड़कर चोरी के आरोप में जेल भेज दिया, उसके बाद वहां जेल में प्रशासन की मिलीभगत से 50 हजार रूपया रंगदारी की मांग चार-पांच दिनों से मांगा जा रहा है । महोदय, इसने कल आत्महत्या करने की कोशिश की । अध्यक्ष महोदय, आप समझ लीजिए कि सात दिन हुए जेल गये । अध्यक्ष महोदय, सरकार इसको संज्ञान में ले ।

अध्यक्ष : सरकार संज्ञान ले रही है । श्री विजय कुमार सिन्हा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, लखीसराय जिला सदर अस्पताल सहित किसी भी अस्पताल में आई0सी0यू0 और ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं रहने के कारण दुर्घटनाग्रस्त, अपराध, उग्रवाद के शिकार गंभीर रोगियों की बिना ईलाज मौत हो जाती है।

अत: सरकार सदर अस्पताल में आई0सी0यू0 एवं ब्लड बैंक की सुविधा देने का कष्ट करे । अध्यक्ष महोदय, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, सात-सात पुलिसकर्मी घायल हुए

थे और ब्लड के अभाव में दो पुलिसकर्मी की पटना आते-आते मृत्यु हो गयी । अधिकतर लोगों की मृत्यु रास्ते में ही हो जाती है, इसको गंभीरता से लिया जाय और ब्लड बैंक और आई0सी0यू0 की व्यवस्था अस्पताल के अन्दर दिया जाय ।

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, बेली रोड स्थित उपरी पूल पूरब की ओर जे0डी0विमेन्स कॉलेज के आगे उतरता है, पुल के आगे बीच सड़क पर नवनिर्मित छोटा गोलम्बर पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है, फलस्वरूप वाहन आवागमन में अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है । मैं गोलम्बर को अविलम्ब निर्मित कराने की सूचना देता हूँ।

महोदय, बेली रोड स्थित जो पुल बना है और जे.डी.विमेन्स कॉलेज के पास जो बड़ा गोलम्बर है, वास्तव में पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है और जिसके कारण लगातार एक्सीडेंट हो रहा है । इसलिए वहां पर ट्रेफिक व्यवस्था को देखते हुए निर्माण करने एवं साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की व्यवस्था की जाय ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष की कम बारिश के कारण अभी गर्मी प्रारंभ भी नहीं हुआ है कि मधुबनी शहर में जलस्तर नीचे चला गया है, जिससे लोगों में हाहाकार है ।

अतः मधुबनी शहर में भूगर्भीय जल के स्तर को बनाये रखने हेतु सरकार उपाय करे ।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि सही माने में साढ़े पांच से छः फीट के तरकीबन पानी का लेयर नीचे चला गया है और 2.00 बजे रात से 6.00 बजे तक ही पानी मिल पाता है । इससे 70 से 80 हजार की आबादी प्रभावित हो रही है, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि इसपर कम-से-कम ध्यान दिया जाय ।

श्री विद्धासागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के फारविसगंज प्रखंड में बथनाहा एवं जोगबनी के बीच मीरगंजपुल क्षतिग्रस्त होने के कारण कभी-भी गिर सकती है । हजारों भारी वाहन एवं आम नागरिक का आने-जाने का मात्र एक ही सम्पर्क पुल है । पुल गिरने से भारत-नेपाल का आवागमन पूर्णतः ठप्प हो जायेगा ।

महोदय, सामरिक दृष्टिकोण से यह पुल बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत-नेपाल सीमा में भारी वाहनों का आना-जाना रहता है और यही एक साधन है, जहां से भारत-नेपाल के लोग आना-जाना करते हैं । पुल की स्थिति काफी जर्जर है, हमने इस

संबंध में कई बार ध्यानाकर्षण भी दिये थे लेकिन अभीतक इसपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और 40 किलोमीटर के रेडियस में यही एकमात्र पुल है, जहां से भारी वाहन और आम लोग इससे आ-जा सकते हैं ।

अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण-सूचना ।

ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री सदानंद सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री प्रेम कुमार : अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज चुनाव में पिछड़ी जातियों में, महादलित जातियों में अनेक जातियों को सरकार ने शामिल कर दिया है ।

अध्यक्ष : यह तो आप उठा ही चुके हैं । श्री सदानंद सिंह जी ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, इसपर हम सरकार का जबाब चाह रहे हैं ।

अध्यक्ष : सरकार जब जबाब देगी तब बतायेगी ।

(व्यवधान)

माननीय नेता, प्रतिपक्ष आपने कहा कि सरकार जबाब दे । सरकार जब जबाब देगी तब न कि अभी जबाब दे दे ?

श्री प्रेम कुमार : हम तो सवाल को रखेंगे महोदय ।

अध्यक्ष : सरकार जब जबाब देगी तो उसमें देखिएगा ।

श्री सदानंद सिंह : बैठ जाइए ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, 17 जातियों को....

अध्यक्ष : श्री सदानंद सिंह ।

श्री सदानंद सिंह : बैठे तब न । प्रतिपक्ष के नेता जी, आप जरा बैठ तो जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सदानंद सिंह जी, आप अपनी सूचना को पढ़ें ।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए सदन के वेल में आ गये)

श्री सदानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 2 फरवरी, 2016 से लगातार एक सप्ताह तक भागलपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से, अनुमंडल पदाधिकारी, भागलपुर सदर श्री कुमार अनुज एवं प्रशिक्षु आई0पी0एस0 गौरव संगला के नेतृत्व में बिना जी0पी0एस0 लगे 16

ट्रकों एवं विभिन्न गोदामों से लगभग 14000 क्विंटल से अधिक बोरी सरकारी चावल एवं गेहूँ जब्त की गयी है ।

इस कालाबाजारी और मिलावट के धंधों में कई विभागीय पदाधिकारी, ट्रक मालिकों, चावल मिल मालिकों, एफ0सी0आई0 एवं एस0एफ0सी0 के पदाधिकारियों की संलिप्तता प्रतीत होती है ।

अतः उक्त खाद्यान्न की हो रही कालाबाजारी एवं मिलावट की जांच एवं इस धंधे में शामिल दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

(व्यवधान)

टर्न-9/शंभु/03.03.16

(व्यवधान जारी)

श्री मदन सहनी : महोदय, भागलपुर जिला के सदन अनुमंडल क्षेत्र अन्तर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की कालाबाजारी के संबंध में गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर राईस मिलरों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य जगहों पर जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियों की टीम गठित कर व्यापक छापामारी करायी गयी है। छापामारी के पश्चात् 3401 बोरे में 1715.40 क्वीं0 गेहूं, 4102 बोरे में 2021.50 क्वी0 चावल, 9333 बोरे में 4574.15 क्वीं0 चावल तथा 274 बोरे में 108.20 क्वी0 सड़ा हुआ चावल जप्त किया गया था। इसके अतिरिक्त 85 बोरे में 31.45 क्वीं0 धान, 379 बोरे में 170.60 क्वीं नकटा, 70 बोरे में 40 क्वीं खुद्दी और 170 पीस खाली बोरा भी जप्त किया गया है।

छापामारी के पश्चात् 07 व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है तथा 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जिला पदाधिकारी भागलपुर के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य खाद्य निगम द्वारा श्री रमन कुमार सिंह, परिवहन अभिकर्त्ता-सह-हथालन अभिकर्त्ता, भागलपुर एवं श्री सुबोध कुमार गुप्ता, परिवहन-सह- हथालन अभिकर्त्ता, भागलपुर को तत्काल निलंबित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु स्पष्टीकरण पूछा गया है। जिला पदाधिकारी, भागलपुर को निदेश दिया गया है कि वे जिले के अन्य गोदामों का भी शीघ्र भौतिक सत्यापन कराकर प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र भेजें। साथ ही वैसे सभी विभागीय पदाधिकारी/ राज्य खाद्य निगम के कर्मी जो इस अवैध कारोबार में संलिप्त हैं, उनके विरूद्ध भी प्रपत्र क गठित कर कार्रवाई हेतु शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराये।

विभाग इस तरह के अवैध करोबार को रोकने के लिए पूरी तरह सजग है और खाद्यान्न की ढुलाई में प्रयुक्त होनेवाले वाहनों में जी0पी0एस0 लगाने का निदेश दिया गया है और इसका अनुपालन भी हो रहा है। साथ ही राज्य खाद्य निगम से सभी गोदामों का औडिट कराने का भी निदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त विभाग ने यह भी व्यवस्था की है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में प्रतिनियुक्त उठाव प्रभारी जैसे ही गोदाम से खाद्यान्न लेकर वाहन निकलता है उसकी सूचना मोबाइल द्वारा एस0एम0एस0 से अधिसूचित गोदाम प्रभारी को देंगे और गोदाम में पहुंचने पर उसकी सूचना पुनः वापस उठाव प्रभारी को देंगे। एस0एम0एस0 में वाहनों की संख्या, खाद्यान्न का प्रकार, खाद्यान्न की मात्रा एवं ड्राइवर का नाम अंकित होगा। सभी प्रयुक्त वाहन जी0पी0एस0 युक्त होंगे। विभाग ने यह भी निदेश सभी जिला पदाधिकारियों को दिया है वे सप्ताह में निश्चित रूप से टीम बनाकर छापामारी कराये और इसकी सूचना तत्काल विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

श्री सदानन्द सिंह : मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार यह बतायेगी कि अब तक कितने कर्मचारियों, पदाधिकारियों या ट्रक ऑनरों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। प्राथमिकी कितने पर दर्ज कराया है आपने, एफ0आइ0आर0 कितने पर दर्ज कराया है आपने ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, एफ0आइ0आर0 ?

श्री मदन सहनी : अध्यक्ष महोदय, अभी कई जिला में इसी तरह का छापामारी हुआ है जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और अनेकों लोगों पर एफ0आइ0आर0 भी दर्ज हुआ है। इसमें विभागीय लोगों पर भी कार्रवाई हुई है और इसमें कई जो परिवहन अभिकर्त्ता हैं और विभाग के लोग हैं उनपर भी आर्थिक अपराध इकाई से जॉच कराने का निदेश दिया गया है। कई जिले हैं जिनके बारे में यदि माननीय सदस्य कहेंगे तो.....

अध्यक्ष : आप विस्तृत रूप से किन-किन लोगों पर एफ0आइ0आर0 हुआ है वह माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दीजिए।

श्री मदन सहनी : जी महोदय, हम उपलब्ध करा देंगे।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम दूसरा प्रश्न यह पूछना चाह रहे हैं कि क्या सरकार मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाकर इतने बड़े घोटाले की जॉच करायेगी?

श्री मदन सहनी : अभी जहां भी छापामारी हुआ है और जो भी लोग पकड़े गये हैं, छापामारी में जो भी अनाज जप्त हुए हैं उसमें हमलोगों ने सभी पर कार्रवाई कर दिया है और बड़े पैमाने पर जहां पर पकड़ाये है। ऐसे दो-तीन मामले आये हैं वहां हमलोगों ने आर्थिक अपराध इकाई से जॉच के लिए निदेश दिया है।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्या हुआ कमिटी बनाने की बात ? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जॉच करायेंगे ?

श्री मदन सहनी : कार्रवाई जब अध्यक्ष जी हो चुकी है, उसका फलाफल भी मिल गया है और तत्काल उसको निलंबित कर दिया गया है और कई लोग जेल भी गये हैं तो फिर उसको किसी से जॉच कराने का क्या औचित्य है।

श्री सदान्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह होगा यह बहुत बड़े घोटाले से संबंधित है। समाचार पत्रों में निकला है कि कॉपी दे रहे हैं। आप विधान सभा की समिति बनाकर कृपया इसकी जॉच करायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री,मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ।

श्री श्रवण कुमार : महोदय, मैं बिहार राज्य लोक अभिलेख अधिनियम-2014 की धारा-17(2) के तहत् बिहार लोक अभिलेख नियमावली, 2015 की प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष : बिहार राज्य लोक अभिलेख अधिनियम-2014 की धारा-17(2) के तहत् बिहार लोक अभिलेख नियमावली, 2015 की प्रति सदन के पटल पर 14 (चौदह) दिनों तक रखी रहेगी।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

श्री अब्दुल जलील मस्तान : महोदय, मैं बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा-89(4) (यथा बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा-35) के तहत् षबिहार निम्न शक्ति शराब-आयात, निर्यात एवं बिक्री नियमावली, 2015ष की प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ।

अघ्यक्ष : बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा-89(4) (यथा बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा-35) के तहत् षबिहार निम्न शक्ति शराब-आयात, निर्यात एवं बिक्री नियमावली, 2015ष की प्रति सदन के पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी।

अघ्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।

श्री(डा0)अब्दुल गफूर : महोदय, मैं बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 की धारा-17(3) के तहत बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का विशेष प्रतिवेदन, 2015 एवं उस पर सरकार का व्याख्यात्मक संलेख की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ।

अघ्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग।

श्री जय कुमार सिंह : महोदय, मैं बिहार राज्य वित्तीय निगम के वर्ष-2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 का 57वाँ, 58वाँ एवं 59वाँ वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा-38(2) के तहत् सदन पटल पर रखता हूँ।

अघ्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही.....

(व्यवधान जारी)

श्री श्याम रजक : अघ्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेदकर के संविधान का यहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपहास और उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं उस समय इस तरह की बात उठाना यह सीधे-सीधे बाबा साहब अम्बेदकर का अपमान है। ये प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिलवा पा रहे हैं और ये मनु संस्कृति लाना चाहते हैं, मनु संहिता लाना चाहते हैं और भारत के संविधान के साथ मजाक करना चाहते हैं।

अघ्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । वित्तीय कार्य ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरणी में सम्मिलित अनुदानों के मांगों की कुल संख्या 36 है, आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है । किसी एक विभाग के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान होगा । शेष मांगों का व्यवस्थापन मुखबंद यानी गिलोटीन के द्वारा किया जायेगा । अब मैं मांग संख्या-37, ग्रामीण कार्य विभाग को लेता हूँ जिस पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्नप्रकार किया जाता है, तथा इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	- 59 मिनट
जनता दल (यूनाईटेड)	- 52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	- 39 मिनट
इन्डियन नेशनल कांग्रेस	- 20 मिनट
सी.पी.आई.(एम.एल.)	- 2 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	- 2 मिनट
हिन्दुस्तानी आवामी मोर्चा	- 1 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	- 2 मिनट
निर्दलीय	- 3 मिनट

कुल -	180 मिनट

माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री शैलेश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च,2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतानके दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग(संख्या-2)अधिनियम-2015, बिहार विनियोग(संख्या-3) अधिनियम-2015 एवं बिहार विनियोग(संख्या-4) अधिनियम-2015 के

उपबन्ध के अतिरिक्त 23,54,00,00,000/-(तेइसअरब चौवन करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

..

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो व्यापक है, जिस पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं अतएव माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा जी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत तृतीय अनूपूरक व्यय विवरणी से संबंधित कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हूॅ । जिसका शीषर्क, मद बतलाया गया है, हेड बतलाया गया है

अध्यक्ष: माननीय सदस्य अरूण बाबू पहले अपना प्रस्ताव कटौती वाला प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि इस शीर्षक की मांग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

महोदय, यह विषय..

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : आपके क्षेत्र में तो प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना तो है नहीं तो किस लिये कटौती लाये हैं ?

अध्यक्ष: अरूण बाबू आपके पूरे पार्टी के लिए 39 मिनट का समय है, आपने ही दो अन्य माननीय सदस्यों का नाम लिखकर भेजा है । इसलिए 39 मिनट में कितना आप बोलियेगा !

श्री अरूण कुमार सिन्हा : मैं यही कहना चाह रहा हूॅ कि अभी जो बात हुई पुराना सदस्य और नया सदस्य की हुजूर, एक बड़ी विचित्र बात समझ में आई, हमने जान कर इसको छेड़ा है- यह 10/- रूपया का कटौती प्रस्ताव एक बड़ा अटपटा लगता है, क्या 10/- रूपया, इतना बड़ा बजट में अगर 10/-रूपया कम कर दिया जाय तो उस पर प्रस्ताव को मान लिया जाय । यह एक अटपटा बात लगती है, लेकिन यह परम्परा है और कई लोग कह रहे थे कि पुराने सदस्य होकर भी इस बात को नहीं कहा तो यह बात छेड़ने के लिए भी इस तरह की बात कही । और दूसरा विषय यह है कि अनुपूरक बजट जो 26 फरवरी, 2016 को पेश हुआ 87 अरब 69 करोड़ 37 लाख 56 हजार और उसमें ग्रामीण कार्य विभाग शीर्षक दे दिया गया जो 23 अरब 54 करोंड़ का है,

लेकिन जो बाकी भी विभाग है, आपने इशारा भी किया कि सभी विभाग पर बोला जाय, आपका सहयोग, आपका संरक्षण के लिए आपको धन्यवाद है, लेकिन यह भी बड़ा विचित्र लगता है, इसी प्रसंगवश मैं कहना चाहता हूॅ कि जब सारे विषयों पर या 91 मद पर अनुपूरक बजट, तो एक ही हेड बनाकर देने का, हमारे बड़े भाई साहब कह रहे थे कि आपके क्षेत्र में ग्रामीण कहां है, यही बात मैं कहना चाह रहा हूॅ कि, यह अनुपूरक, यह तृतीय अनुपूरक

...

जो है से सारे विषय पर उसका पैसा, उसकी रकम दी गई है इसलिए इन सारे विषय पर जिस तरह बजट पर बोला गया, उसी तरह इसमें समय भी मिलना चाहिए, उस तरह इसका स्वरूप भी होना चाहिए, जो अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद है कि आपने इस तरह की बात कही है । अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तीसरे अनुपूरक बजट द्वारा अतिरिक्त धन की खर्च के लिए मांग हो रही है और दूसरे तरफ अध्यक्ष महोदय, अगर 2015-16 के बजट में इसके अतिरिक्त खर्चा को हम अगर ध्यान दें तो यह पायेंगे कि कई प्रमुख विभागों में अब तक जो राशि खर्च हुई है वह 50 प्रतिशत को भी पार नहीं किया तो अब ऐसी स्थिति में वह प्रमुख विषय, ग्रामीण कार्य विभाग को जोड़ ले, परिवहन, खाद्य, उपभांक्ता, सहकारिता, नगर विकास, आवास, पंचायत राज, उत्पाद- यह प्रश्न उठता है कि जब 50 प्रतिशत पैसा बचा ही हुआ है तब अनुपूरक बजट लाने का क्या औचित्य बनता है ंअब एक माह से भी कम समय बचा हुआ है, अब यदि कुछ उल्लेख, कुछ विभागों का करें जैसे पंचायती राज विभाग की योजना की जो कुल राशि है उसका 16.78 प्रतिशत ही खर्च हुआ है । क्रमशः

क्रमशः

श्री अरुण कुमार सिन्हा : उसी तरह से उद्योग विभाग का 32.68 परसेंट खर्च हुआ है । उर्जा विभाग का 37 प्वायंट समथिंग है । कृषि विभाग का 38 परसेंट है । नगर विकास विभाग का 40 से 41 परसेंट खर्च आ रहा है । समाज कल्याण का 47 परसेंट है । खाद्य उपभोक्ता विभाग का 49 परसेंट है । इसतरह से हम अगर अनुपात देखेंगे` तो सारे विभागों का यह आंकड़ा 55-60 परसेंट सब को जोड़कर होता है । इससे जाहिर है हुजूर, अब मार्च लूट इसी को कहते हैं । पैसा बचा हुआ है तो बदइंतजामी होगी , लूट -खसोट होगा । एक बात और है कि सरकार ने विभिन्न विभागों के अंदर बोर्ड और निगम बना दिया है और राशि निगम और बोर्ड में ट्रांसफर हो जाती है और निगम बोर्ड में राशि ट्रांसफर होने के बाद मनचाहे ढंग से खर्चा होगा । अध्यक्ष महोदय, ये निगम बोर्ड है -पुल निर्माण निगम, पथ विकास निगम, बुडको, राज्य स्वास्थ्य समिति , जल स्वच्छता मीशन, भवन निर्माण निगम , जीविका, महिला विकास निगम, बिहार चिकित्सा सेवाएं, बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना , क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार श्रम कल्याण समिति , बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार इत्यादि के माध्यम से कार्यों का संचालन होता है और पैसा खर्च करने की व्यवस्था होती है । अंत में इसमें यही कहना होगा कि सरकार ने पैसा निगम के माध्यम से खर्च किया । बजट पर बोलते हुए एक हमारे माननीय सदस्य ने कहा था तो उस समय तो उपयुक्त नहीं लगा लेकिन इस समय कहना यह उपयुक्त लगता है कि ''माल महाराज का और मिर्जा खेले होली । '' निगम वाले लोगों को ऐसे ही पैसा मिल गया और फिर मनमाने ढंग से उसका खर्च होगा । 13 वें वित्त आयोग के दौरान यू0पी0ए0 की सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदत राशि की तुलना में 14 वें वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को एन0डी0ए0 सरकार ने दोगुणी से अधिक राशि दी परन्तु महोदय, राज्य सरकार द्वारा यह खर्च करने की रीति-नीति और मौनिटरिंग सिस्टम की गड़बड़ी है और इसके कारण स्वीकृत राशि खर्च नहीं हो पाती है । सरकारी धन खर्च करने वाली यह सरकार इसमें तो अक्षम है लेकिन इसके बावजूद जो आंकड़ा है जो बजट आया`है उसमें इन्होंने अपनी पूरी होशियारी ,बाजीगरी दिखयी है और ये उसके माहिर खिलाड़ी है ऐसा इससे लगता है क्योंकि इन्होंने दिखाया है कि एक ओर बजट बनाते समय योजना के आकार में वृद्धि कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो दूसरी तरफ वित्तीय वर्ष के अंत में बोर्ड निगम में पैसे को ट्रांसफर करके रुपया खर्च

कर दिये जाते हैं और उसी का ढिंढोरा पीट रहे हैं । महोदय, राज्य सरकार ने तृतीय अनुपूरक के माध्यम से लगभग सभी विभागों के लिए कुछ न कुछ अतिरिक्त राशि की मांग की है । ै लेकिन विभाग वार देखेंगे तो इसकी स्वयं कलई खुल जायेगी । अभी धान का मौसम है 5 दिसम्बर 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक और 30 लाख मीर्ट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया ै लेकिन आज अभी तक का जो सरकारी आंकड़ा है, रेकर्ड है उसके अनुसार अभीतक लगभग 7 लाख मीट्रिक टन ही धान क्रय हो पाया है और उसमें भी शत प्रतिशत लोगों के पैसे का भुगतान अभीतक नहीं हुआ है। अब महोदय , अब एक माह से भी कम समय है और शेष ये 23 लाख मीट्रिक टन का कैसे क्रय सरकार करेगी और कैसे भुगतान करेगी ? यह स्पष्ट करता है कि यह सरकार झूठी बात करती है - ''झूठ बोले कौआ काटे वाली बात है ।'' यह सरकार किसानों की सुरक्षा की बात करती है और एक तरह से किसानों के साथ दुश्मनी का रुप अख्तियार की है और यह दुरंगी चाल है ।

(इस अवसर पर श्री मो0 इलियास हुसैन, माननीय सदस्य ने सभापति का आसन ग्रहण। किया)

श्री अरुण। कुमार सिन्हा : ''मुंह में राम बगल में छुरी'' ऐसी कहावत के अनुकूल है । महोदय, उल्लेखनीय है कि पैक्स के धान क्रय में वांछित 3500 करोड़ में से 250 करोड़ रुपया ही आवंटित किए गए हैं । किसानों के धान खलिहान में पड़े हुए हैं । सभापति महोदय, आज किसान हाय हाय कर रहे हैं । किसान पस्त हैं , बिचौलिए मस्त हैं और सरकार सुस्त है । किसान हाय हाय और सरकार तमाशबीन बनी है । महोदय, राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की बात लगातार करती आ रही है परन्तु खेद है कि पी0एम0सी0एच0 जो एक सबसे आदर्श और महत्वपूर्ण संस्था इस सरकार की मानी जाती है उसकी ओर भी हम देखें तो वह अप -टू- मार्क नहीं है । अन्य राज्य की अस्पतालों की क्या बात करुं । महोदय, पी0एम0सी0एच0 हो या एन0एम0सी0एच0, आई0जी0आई0एम0एस0, आई0जी0सी0एच0 वहॉ न तो पर्याप्त डौक्टर हैं , न दवाईयॉ हैं न ठीक ठाक उसके उपकरण और मशीनें हैं । राज्य भर के पी0एच0सी0 एवं ए0पी0एच0सी0 भगवान के भरोसे रहमोकरम पर है । दवा नदारद है , डौक्टर नदारद हैं और मरीज परेशान और बेहाल हैं बिल्कुल जिसको कहा जाता है कै अनाथ की तरह हैं। अंत में हुजूर, एक बात और कहना चाहता हूँ आज कुकुरमुत्ते की तरह दलाल हो गए हैं । प्राईवेट नर्सिंग होम खुले हुए हैं , सब प्राईवेट नर्सिंग होम को दोष नहीं दिया जा सकता है इसमें कई प्राईवेट नर्सिंग होम ठीक भी हैं लेकिन अधिकत्तर प्राईवेट नर्सिंग होम के ` दलाल मरीजों के पास घुमते हैं और उनको बहला-फुसलाकर कि बेहतर

इलाज होगा इन नाम पर उसको अस्पताल ले जाते हैं और जान की बात तो छोड़ दीजिये गरीब आदमी के लाखों का माल लूटे लेते हैं और अनको अनाथ बना देते है और वह बेचारा वापस हो जाता है ।

श्री ललित कुमार यादव : लगता है कि माननीय सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से तो नहीं आते हैं , इनके क्षेत्र में एक भी गांव नहीं है क्या ?

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : इनको बोलने दीजिये ।

श्री अरुण कुमार सिन्हा : पथ निर्माण का भी बुरा हाल है । एक समय था जब एन0डी0ए0 की सरकार थी 2005-2010 तथा 2012 तक हम लोग साथ में थे और जो भी माननीय सदस्य बतलाये कि उस पथ से 3 घंटा में पहुंचते हैं , दो घंटा में पहुंचते हैं लेकिन वह पथ आज उसके बाद जब से हमलोग अलग हुए हुजूर, उसके पथ निर्माण की गति धीमी हो गयी और उसका एग्जाम्पुल है अभी देख लीजिये पटना से न्यू बाई पास बिहटा-सरमेरा पथ उसकी क्या गति है ? गंगा के किनारे ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य आपका कहना है कि जब से आप अलग हुए हालत पथ की खराब हो गयी, अब तेजस्वी जी आ गए है हालत सुधरने लगी है ।

श्री अरुण कुमार सिन्हा : हुजूर, उसी का मैं उदाहरण देता हूँ । गंगा में मैरिन ड्राईव की तर्ज पर रोड बननी थी जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया थाा वह बन रही है कि नहीं बन रही है ? यह क्या हो रहा है , सारी गति रुक गयी । जितनी सड़क बन रही है उसकी मरम्मती में भयंकर लूटपाट है , हर जगह काम रुका हुआ है यानी उसकी धीमी गति है उसका रेकर्ड देख लें वह बिल्कुल जीरो प्वायंट पर काम कर रहा है । महोदय , नगर विकास के प्रति कहना है ।

सभापति (मो0 श्री इलियास हुसैन) : कृपया शांति बनाये रखें ।

टर्न-12/विजय- 03.03.16

श्री अरूण कुमार सिन्हा: हुजूर, जरा सुना जाय । आज एक भी शहर स्मार्ट सिटी चयन की योग्यता नहीं रखता । आज ही हमलोग गए थे और माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी वहां पधारे थे । आज सफाई अभियान दैनिक जागरण का चल रहा था और उसी दैनिक जागरण में यह कहा गया कि 17 वें पायदान पर है मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूं राज्य के सबसे अंतिम पायदान पर चाहे एक पायदान के उपर यह पटना शहर है और इसका आलम जरा देखिये इसके बद

इंतजामी का । बोली में ये लोग जरूर तेज हैं । मा0 मुख्यमंत्री जी एक सभा में सावधान करते हैं यहां के मेयर साहब को, अपनी इज्जत की दुहाई देते हैं, मेयर और नगर आयुक्त की लड़ाई अखबार में सुर्खी बनी हुई है । लोग अखबार गौर से देखते हैं कि आज मेयर और नगर आयुक्त की लड़ाई हुई कि नहीं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, अरूण जी, माननीय मुख्यमंत्री का यह जो पहल और चिंता है राज्य हित में है कि नहीं ? जो आपने फरमाया ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा: जी जी । मैं वही बात कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को भारी सभा में मेयर को सावधान करना पड़ रहा है और उसके बाद 17वें पायदान पर यह राजधानी आ रही है पटना का क्या हाल होगा शहरों की गंदगी का क्या हश्र होगा ? हुजूर, इसके बाद भी ये लोग ताली पीट रहे हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, अरूण जी वरीय सदस्य हैं । ग्रामीण कार्य विभाग की मांग पर बहस चल रही है । इसका जवाब तो ग्रामीण कार्य मंत्री देंगे नहीं । तो परंपरा यही रही है कि जो मुख्य विभाग है उस पर बहस होनी है उस पर बोलना चाहिए ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय मंत्री पथ पर चलते चलते कभी भूला राही आर0इ0ओ0 पर भी चला आता है ।

श्री अरूण कुमार सिंह: हुजूर, शायद वित्त मंत्री जी ने नहीं सुना । मैंने पहले ही कहा कि दो बात बहुत औबजेक्शनेबल मुझे लगता है । 10 रू0 में 10 रू0 की कटौती । पूरा पैसा इन्होंने अनुपूरक सब विभाग के लिए मांगा है और शीर्षक बना दिया ग्रामीण । मैं यही तो चाह रहा था कि यह विषय आये । आप पैसा सब विभाग के लिए मांग रहे हैं । मैं ग्रामीण कार्य पर बोलने के लिए तैयार हूं, मैं ग्रामीण पर बात करूंगा । मैं जानकर कह रहा हूं कि एक जो गलत परंपरा चली हुई है । क्या है परंपरा, परंपरा तो हम ही आप ही तोड़ेंगे । पैसा तो आपने सब पर मांगा है ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी: आपका कटौती प्रस्ताव भी 10 रू0 घटाने का ग्रामीण कार्य विभाग से ही है, अन्य से नहीं है ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा: वह नहीं देते तो पास नहीं होता हुजूर । इसलिए हम भी मजबूर आप भी मजबूर । लेकिन मैं आखिर इस बात को कहां उठाउं ।

(व्यवधान)

हुजूर, हमको बोलने दिया जाय नहीं तो थोड़ी देर में आप कहियेगा कि अपनी बात समाप्त करें । तो मैं यह कह रहा था कि राजधानी का यह आलम है और राजधानी में एक पेयजल की जो समस्या है 548 करोड़ की स्वीकृत आपके वर्षो से यह काम चल रहा था । वही कहावत हुई 9 दिन में चले ढ़ाई कोस । यह धीमी गति से चला अब उसको बंद भी कर दिया गया । महोदय, यह गलत निर्णय हुआ है । इसी तरह से गर्मी का दिन आ गया अभी पीने के पानी का भयंकर अभाव हो रहा है, चारों तरफ आक्रोश भी शुरू हो गया है, गरीब लोग और मुसीबत में हैं । क्योंकि उनको सार्वजनिक पेयजल से और नल से उनको पानी मिलता है । और पचास से सौ वर्ष पहले का पाइप जर्जर है, बीच बीच में लिकेज है हुजूर, और उसमें सिवरेज का पानी मिल जाता है, उसमें गंदा पानी आता है या पानी नहीं आता है और उस पानी को पी कर लोग बीमार पड़ते हैं और ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी सात कमिटमेंट करते हैं और उसमें उन्होंने घर घर पानी पहुंचाने की बात कही । अब गर्मी का दिन आ गया, अब कैसे पूरे बिहार को, पूरे लोग को पानी पहुंचायेंगे और इसके लिए कितना पानी के लिए कहां से कितना लंबा इंतजार होगा । मुख्यमंत्री चापाकल योजना । अभी तो पानी की बात थी तो कम से कम विधायक जाकर चापाकल दे देता था, बीच में जो पाइप फटता है पाइप को बदलवा देता था, समरसिबल बोरिंग की व्यवस्था कर देता था, कुछ भी कर देता था । लेकिन यह सारा मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना बंद, चापाकल बंद । आज क्षेत्रीय विकास योजना को भी ऐसा कट शौर्ट किया गया है कि सड़क नहीं बना सकते हैं, नाला नहीं बना सकते हैं, यह नहीं कर सकते वह नहीं कर सकते हैं । इस तरह से यह पूरी तरह से जिस विधायक के बदौलत यह सरकार है उस विधायक को बेइज्जत अफसर के सामने यह आखिर नेट वर्किंग कौन लायेगा ? अफसर लायेगा, विभाग लायेगा और विधायक टुकुड़ टुकुड़ मुंह ताकेगा ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): कोई माननीय सदस्य को बेइज्जत नहीं कर रहा है ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा: हुजूर, मैं यह बात पक्ष विपक्ष से हटकर कर रहा हूं । यह कहीं न कहीं जन प्रतिनिधि की बेइज्जती है और इस बेइज्जती के लिए मैं रिक्वेस्ट

कर रहा हूं सरकार से और मुख्यमंत्री जी से कि इस पर पुर्नविचार करें । सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं सरकार के पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है कि इतना जल्दी वह नीति रीति बनाकर घर घर पानी पहुंचा देगी । क्योंकि पानी के लिए वर्षो का इंतजार नहीं, घंटा भर भी इंतजार नहीं होता । सभापति महोदय, इसी के साथ सिवरेज सिस्टम भी पूरे बिहार में शहरो का सिवरेज सिस्टम ध्वस्त है । महोदय, अब ये लोग कह रहे हैं कंकड़बाग का जो जीरो प्वाइंट जब बरसात का समय आने वाला है तो कंकड़बाग का जीरो प्वाइंट और वहां पर संप लगना था पर एक साल पहले ही लगना था लेकिन अभी तक उस पर कार्य नहीं शुरू हुआ है । और इस बार लगता है कि पुनः अगर बरसात आ जाय तो बारिश में पूरा यह जो दक्षिण का पटना है उसको दहने से कोई नहीं रोक सकता है । प्रेमचंद उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, सामने हैं, नोजवान हैं, नवकिशोर हैं मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं और संबंधित मंत्री जी भी और ये लोग कहे थे प्रेमचंद रंगशाला के पास साइंस सिटी बनाया जाएगा दो महीने में काम शुरू होगा । तीन महीने से अधिक हो गया दूसरा सत्र शुरू हो गया आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि इस पर भी कुछ जवाब आवे । अभी तक उसकी कोई सुगबुगाहट नहीं है । महोदय, यह भी बताना चाहूंगा कि उक्त स्थान में अब कूड़ा का अड्डा बना हुआ है और लोग रात दिन आंदोलन करते हैं और पेटीशन देते हैं । और यही हाल है कंकड़बाग टेम्पो स्टैण्ड का भी लेकिन यह सरकार के लिए एक जुमला है भैंस के आगे बीन बजाय और भैंस बैठ पगुराय।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): कृपया शांति बनायें और माननीय सदस्य को सुनें ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा: महोदय, सैदपुर नाला बिलकुल ध्वस्त हो चुका है और फिर बरसात में वहां जो शनीचरा पुल टूट गया है और बन रहा है कब तक बनेगा उसकी भी गति धीमी है । और इसी तरह एक मुसलिम मोहल्ला है करबला वहां का भी पुल टूट चुका है । इसी तरह शाहगंज एक मोहल्ला है वहां पर दो साल से वह पूरा महेन्द्रू का इलाका दो साल से सिवरेज का पानी गलियों में तैरते रहता है । लोग हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, सड़क जाम करते हैं, पुलिस उनको केस मुकदमा का डर दिखाकर घर में बैठाती जाती है । यह स्थिति है । अभी तक आइ0एस0बी0टी0 का निर्माण कार्य आज तक बैरिया में शुरू नहीं हुआ । सभापति महोदय, शिक्षा की व्यवस्था भी पहले से ज्यादा चौपट हो गयी है ।

राज्य में छात्रों के अनुपात में शिक्षक नहीं हैं ।शैक्षणिक सामग्री नहीं है, शैक्षणिक माहौल नहीं है । बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है । अकेले पटना में 770 विद्यालय भवनहीन हैं और 5 हजार विद्यालय पूरे राज्य में भवनहीन हैं ।

क्रमशः

टर्न-13/बिपिन/03.03.2016

श्री अरूण कुमार सिन्हा: क्रमशः विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के हजारों पद गत् कई वर्षों से रिक्त हैं । महोदय, राज्य सरकार एस.सी.-एस.टी. छात्रों के लिए छात्रवृत्ति हेतु इस अनुपूरक द्वारा पांच सौ करोड़ की मांग की गई है लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि उड़ीसा में जो बिहार के बच्चे थे उनको स्कॉलरशीप नहीं मिला, पैसा नहीं दिया तो बाहर किया गया । तो जब बाहर किया गया तो बहुत हल्ला-गुल्ला हुआ तो सरकार को चेत आया तो फिर उसकी भर्त्ती हुई है । महोदय, राज्य में जो सात कमिटमेंट मुख्यमंत्री जी का था, उन्होंने नौजवानों को छात्रवत्ति मुहैय्या कराने का काम स्वागत योग्य है लेकिन केवल स्कॉलरशीप, छात्रवृत्ति, इस तरह का देने से, कितने

दिनों तक दीजिएगा ? यहां पर रोजगार के लिए उद्योग चाहिए और यह कृषि प्रधान बिहार है तो जब कृषि प्रधान बिहार है तो यहां पर कृषि से संबंधित उद्योग होना चाहिए । तो मैं कहना चाहता हूं हुजूर कि इस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में भी ये संवेदनशील नहीं हैं ।

महोदय, एक करोड़ युवकों को, ये कहते हैं केन्द्र सरकार की बात, एक करोड़ युवकों को कौशल विकास हेतु प्रति वर्ष 20लाख युवकों को प्रशिक्षण देने की बात हुई थी। आज देखना होगा कि कितने लोग प्रशिक्षित किए गए । यही हालत इन्दिरा आवास का भी है । लक्ष्य के मुकाबले बिल्कुल कम है । महोदय, अतिक्रमण के नाम पर पचास साल, सौ साल पुराने गरीब और दलित बस्ती को उजाड़ा जा रहा है । पटना में ही जो मलाही पकड़ी, दुसाधी पकड़ी के लोग हैं और उनको यह कहा जाता है कि अतिक्रमण है, आप कहते हैं बेघरों को घर, तो बेघरों का घर की बात आप कहते हैं तो पहले उनके मकान का व्यवस्था कर देते, तब उसको उजारते । हुजूर, सभी विभागों का एक जैसा ही हाल है । जबसे हमने इनका साथ छोड़ा है तबसे पैसा सरेंडर हो रहा है । बजट के विषय में मुझे यही कहना है कि मंत्री जी के जो सात निश्चय थे उसमें कृषि को, उद्योग को, शिक्षा को, लॉ एंड ऑर्डर को, इन सभी बातों पर जरा ज्यादा कमिटमेंट होना चाहिए क्योंकि लॉ-एंड-ऑडर को आप देख रहे हैं कि रोज अखबार में सुर्खियों में लॉ-एंड -ऑर्डर के विषय में आ रहा है ।

महोदय, मैं जरा ग्रामीण कार्य के विषय में कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत बिहार में केन्द्र सरकार ने जो राशि दी है उसे राज्य सरकार खर्च करने में विफल है । उलटे ये कहते हैं कि ये पैसा नहीं देते हैं । सड़क निर्माण के साथ-साथ सड़क मेंटेंनेंस में भी सरकार पीछे चल रही है । राज्य सरकार का यह आरोप बेबुनियाद है कि केन्द्र ने 15हजार कि0मी0 सड़क निर्माण के लिए 8,743करोड़ रूपया नहीं दिए हैं । ये गलत करके स्वयं उसके लिए पैसा नहीं देकर, यह काम भी, इसकी रफ्तार नहीं पकड़ रही है । दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत अब तक स्वीकृत ग्रामीण सड़क की लंबाई 6,750कि0मी0 की लागत से 5,576 करोड़ रूपया की जिसमें अब तक निर्माण का कार्य मात्र 1,719कि0मी0 का ही हुआ है । खर्च भी 1827करोड़ रूपए हुए हैं । अभी तक निर्माणाधीन सड़क की लंबाई पांच हजार एकतीस कि0मी0 है जिसकी लागत 3,749करोड़ रूपया है । सरकार बताए कि यह काम कब पूरा होगा, कितने समय में पूरा होगा ।

हुजूर, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अंत में हम कह रहे हैं कि यह पानी, सड़क, जल, भोजन, गरीबों की स्थिति, विधि-व्यवस्था- यह सबका सर्वांगीण विकास की गति चारों ओर रूकी हुई है । ऐसे में यह जो सप्लीमेंट्री बजट का डिमांड है, बिल्कुल बेबुनियाद है। जो पैसा बचा है पहले उसको खर्चा करके उसका ठीक से हिसाब दें । हुजूर, यह जनता आक्रोश से भरी हुई है और जनता आवाज दे रही है । यह आवाज काल की आवाज है ।

सुन लीजिए लोग । बाजे नगाड़ा काल का, डिगने वाला तेरा सिंहासन, देखना जरा संभाल के, यह कहते हुए हम इस कटौती के पक्ष में और यह जो अनुपूरक बजट है इसके खिलाफ बोलते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं ।

सभापति (श्री इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य अरूण बाबू, थक गए हैं क्या ? पांच मिनट और हैं आपके ।

श्री प्रेम कुमार :अब विजय कुमार सिन्हा बोलेंगे । दिया हुआ है उसमें ।

सभापति (श्री इलियास हुसैन): नहीं दिया हुआ है । भिजवा दीजिए ।

माननीय सदस्या श्रीमती प्रेमा चौधरी । आपका समय 10मिनट है ।

श्रीमती प्रेमा चौधरी : सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से जो बजट पेश हुआ है उसके पक्ष में बोलती हूं और यह कहना चाहूंगी कि हमारा गठबंधन की सरकार ने महोदय, हर उस मुद्दे को लाया है, चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, बजट में लाने का प्रावधान किया है ।

महोदय, मैं कहना चाहूंगी गठबंधन की सरकार के माध्यम से और इस सदन के माध्यम से कि हमारी सरकार ने महिलाओं को 35प्रतिशत् आरक्षण देने का काम किया है, मैं इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देती हूं । नीतीश जी ने ऐसा काम कर दिया जो ऐतिहासिक काम हुआ । मैं अपनी तरफ से और पूरे बिहार की महिलाओं की तरफ से धन्यवाद उनको देती हूं कि उन्होंने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है । महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि हमारी गठबंधन की सरकार ने जो काम किया है वह देखने लायक है । हर गली, मुहल्ले में चाहे सड़क का काम हो, चाहे पुल-पुलिया का काम हो, हर जगह काम हो रहा है महोदय । हमारे विपक्ष में बैठे हुए लोग शिकायत करना चाहते हैं लेकिन राज्य चलाना कोई मामूली खेल नहीं है, यह शतरंज की गोटी नहीं है कि एक घर से दूसरे घर में रख दिया और समस्या का समाधान हो गया । इसमें धैर्य रखना चाहिए और देखना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है । महोदय, पहले जो पांच साल बीता उसमें भी, जब हमारी सरकार थी, उस समय जो हमलोगों ने काम कराया था, वह पांच साल के वर्षों में एक छइटा मिट्टी भी उन सड़कों पर नहीं पड़ा है महोदय । महोदय मैं यह कहना चाहूंगी कि जो हमारा क्षेत्र है पातेपुर, हम पिछले बार हार गए थे, उसके पहले का पातेपुर, पिछले पांच सालों में वहां बी.जे.पी. के विधायक थे । जो भी रोड हमने बनाया, आज जाकर उसको देखा जाए, जर्जर स्थिति में आ गया है । महोदय, हमारा एक पुल है जो मुनमुन नदी, जो बहुआरा को जोड़ने का काम करता है महोदय, वह पुल बनना

अत्यावश्यक है । मैं आग्रह कहना चाहूंगी अपने पथ निर्माण मंत्री से कि उस पुल को अवश्य बनावें ताकि पचास हजार की आबादी को वह जोड़ने का काम करेगा ।

महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं, एक और सड़क है हमारा जो 7कि.मी. है, बड़ा खराब है। उसमें भी पैसा आया था प्रधानमंत्री द्वारा लेकिन उसपर काम नहीं हुआ, क्या कारण है कि वह सात किलोमीटर रोड पांच-सात वर्षों से यों ही पड़ा हुआ है ।

महोदय, एक गांव है जो ग्रामीण विद्युतिकरण के तहत वहां बिजली भी गया, तार, पोल, ट्रांसफॉर्मर भी लगा है, लेकिन अभी तक बिजली नहीं पहुंची है । पांच-सात वर्षों से सब कुछ लगा हुआ है । वह एक जाति विशेष समुदाय का मुहल्ला है और यादव और कुर्मी लोग ही केवल रहते हैं वहां लेकिन बिजली का काम नहीं किया गया है ... क्रमशः..

टर्न-14/राजेश/3.3.16

श्रीमती प्रेमा चौधरी, क्रमशः- वहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुंचाने का काम किया है, इसका क्या कारण है ? हमलोग भी प्रशासन को कहते रहे कि वहाँ बिजली दीजिये, हमारे सांसद महोदय भी इसको झेल चुके थे, उन लोगों ने वोट का बहिष्कार भी किया था, इस बात को हमलोग भी चुनाव में महसूस किये, हमलोगों को भी वोट उस मुहल्ले और गॉव से नहीं मिला, तो मैं चाहूंगी सदन के माध्यम से और आग्रह करती हूँ कि वहाँ अविलंब बिजली की व्यवस्था करायी जाय, आज हमें ग्रामीण कार्य विभाग पर जो बोलने का मौका मिला, उसमें अपनी बातों को रखा, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ । जय हिन्द ।

सभापति (मो0 इलियास हुसैन):- माननीय सदस्या श्रीमती प्रेमा चौधरी जी बैठ गयी। लगता है कि तैयारी नहीं थी ।

श्रीमती प्रेमा चौधरी:- हम तो तैयारी किये थे दूसरे विषय पर लेकिन आज दूसरे विषय पर बोलना पड़ा ।

सभापति (मो0 इलियास हुसैन):- ठीक है । माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद । आपका समय 10 मिनट । कृपया ध्यान देंगे ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद:- माननीय सभापति महोदय, आपके तरफ से जो पहले बोलने का मौका मिला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं । महोदय, सदन में धन्यवाद हम बिहार की जनता को भी देना चाहेंगे, धन्यवाद इसलिए कि विपरीत परिस्थितियों में बिहार की जनता ने महागठबंधन को वोट दिया और

नीतीश कुमार जी को पॉचवी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे । सभापति महोदय, आज ग्रामीण कार्य विभाग के बजट पर बहस हो रहा है और हम उसके समर्थन में बोल रहे हैं और हम सरकार की तरफ से ग्रामीण कार्य विभाग के समर्थन में अपनी बात को रखना चाहते हैं । महोदय नीतीश बाबू जब बिहार की गद्दी पर बैठे, महागठबंधन की सरकार बनी, तब से ग्रामीण कार्य विभाग एक ऐसा विभाग के रुप में पूरे देश में दिखाई देने लगा जो भाजपा के लोगों को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है । महोदय, ग्रामीण कार्य के बदले विपक्षी लोग दूसरे-दूसरे विभाग पर चर्चा किये, हम पूछना चाहते है कि ये लोग तो शहर से जीतकर आते हैं और हमलोग तो गॉव से जीतकर आते हैं, हम तो कटौती प्रस्ताव माननीय विधायक अरुण बाबू से जानना चाहेंगे कि क्या आपके क्षेत्र में एक भी ग्रामीण सड़क है, जो इसके बारे में वे जाने और एक तरफ हमारी गठबंधन की सरकार पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया । महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग खास करके जो बिहार के लिए बजट में प्रावधान किया है, उस प्रावधान में कहीं भी कटौती का जगह नहीं है, हम तो विपक्ष से चाहेंगे कि कटौती प्रस्ताव वापस लें, क्योंकि ग्रामीण सड़कें, बिहार की 80 प्रतिशत आबादी गॉवों में रहती है और वह गॉव पी0डब्लू0डी0 सड़क से नहीं जुड़ता है, एन0एच0 से नहीं जुड़ता है, वह सड़कें ग्रामीण कार्य विभाग जोड़ने का काम करता है। सभापति महोदय, आज बिहार जिसतरह से न्याय के साथ विकास और विकास के साथ सात निश्चिय के प्रति जो वचनबद्वता दोहराया है, उसमें ग्रामीण कार्य विभाग उसका एक हिस्सा है और माननीय मुख्यमंत्री महागठबंधन की सरकार के द्वारा, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा, जो बजट पेश किया गया है, वह काफी सराहनीय है..... (व्यवधान)

सभापति (मो0 इलियास हुसैन):- शांति-शांति । माननीय सदस्यगण, कृपया शांति बनाये रखें । माननीय सदस्य आप बोलिये ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद:- सभापति महोदय, मुख्यमंत्री सड़क योजना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो बिहार में दो तरह की सड़के बनायी जाती थी, पहले समान रुप से सड़क बनायी जाती थी, कोई नामकरण नहीं था, अब जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री जी की तरफ से भारत सरकार उसमें पैसा देती थी और उस सड़क को बनवाने का काम किया जाता था, दूसरा सड़क मुख्यमंत्री सड़क योजना जो नीतीश कुमार जी के आने

के बाद मुख्यमंत्री सड़क योजना बनाया गया, हाल यह है कि एक तरफ बिहार को सड़क चाहिए और दूसरी तरफ जो केन्द्र की सरकार, नरेन्द्र मोदी की सरकार जो केन्द्र में बैठी हुई है, वह बिहार को खुशहाल नहीं देखना चाहती है । महोदय, खुशहाल क्यों नहीं देखना चाहती है, इसलिए कि चुनाव के वक्त जो उन्होंने वादा किया, जो उन्होंने जनता के साथ बताने का काम किया कि हम बिहार में ऐसे करेंगे, बिहार को ऐसा सड़क देंगे, बिहार को इसतरह से ले चलेंगे लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किये । महोदय, आज हाल यह है कि एक तरफ बिहार..... (व्यवधान)

सभापति (मो0 इलियास हुसैन):- माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद जी बैठ जाय । माननीय नेता विरोधी दल ।

श्री प्रेम कुमार:- सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में ,जैसी की जानकारी इनको है कि 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे है और वे विकास को ले करके ही आ रहे हैं । मुंगेर में अटल बिहारी बाजपेयी जी ने जिस पुल को शुरु किया था महोदय, उसका लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं और एक नया मोकामा में पुल बनने जा रहा है महोदय और दीघा में जो रेलवे का पुल तैयार हो गया है, जो चालू हो गया है यानि कि वे विकास योजनाओं को लेकर ही आ रहे हैं .....(व्यवधान)

सभापति (मो0 इलियास हुसैन):- ठीक है बैठिये । माननीय उप-मुख्यमंत्री ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव:- महोदय, हमलोगों को बहुत उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और बहुत आशा है, उस दिन हम अपनी मांगों को भी रखेंगे और उनके वादों को भी याद दिलायेंगे ।

क्रमशः

टर्न-15/कृष्ण/03.03.2016

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : क्रमशः आपलोगों को तो खाली क्रेडिट लेने की आदत है । मतलब खाली विकास आप करेंगे और विनाश हमलोग करेंगे ? क्या सोच है ? नकारात्मक सोच से कैसे राजनीति चलेगी ? हमलोग चुन करके आये हैं, हमलोग काम करना चाहते है । आपलोग सहयोग कीजिये । केन्द्र में इतने मंत्री हैं, मगर वहां कुछ नहीं हो रहा है । क्यों नहीं हो रहा है? बिहार की हकमारी की जा रही है । सौतेला व्यवहार हो रहा है और आपलोग मोदी जी का गुणगान किये जा रहे हैं । तो ये सारी चीजे हैं। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए । जिसने जो काम किया है, उसको कम से कम क्रेडिट दीजिये । जिसने काम कराया, उसका आप

क्रेडिट छीनना चाह रहे हैं । इस पर राजनीति मत कीजिये । विकास हो रहा है तो और भी विकास करने की उनसे उम्मीद रखा कीजिये ।

श्री प्रेम कुमार : सभापति महोदय, बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को 15 साल का मौका दिया था । लेकिन आपने विकास नहीं किया । आपने घोटाला करवाया ।

व्यवधान

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : शांति शांति, कृपया आपलोग बैठ जाईये । माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन जी, आपका अब एक मिनट समय बचा है आप अपने क्षेत्र की बात कीजिये ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : सभापति महोदय, इसमें मेरी गलती क्या है ? हल्ला किये भाजपा वाले, इसमें हम क्या करें ? महोदय, हम कहना चाहते हैं कि भाजपा वाले लोग बिहार को विकसित नहीं देखना चाहते हैं । देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी भी थे, देश के प्रधाान मंत्री डा0मनमाहेन सिंह जी भी थे । लेकिन बिहार के सड़कों के साथ उन्होंने कोई सौदेबाजी नहीं की । जिस तरह से बिहार का 9 हजार करोड़ रूपया आज नरेन्द्र मोदी जी रखे हुये हैं । क्या उनको मिल रहा है ? सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहते हैं कि आज बिहार की जनता ने जिस तरह से हमलोगों को मैनडेट दिया है, भाजपावाले लोग बौखला गये हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : शांति शांति । माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ। आप बैठ जाईये । जनाब माा0 तौसिफ आलम, इन्डियन नेशनल कांग्रेस ।

मा0स0 प्वायंट ऑफआर्डर पर खड़े हैं । सुन लीजिये

श्री भोला यादव : सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है । उन्होंने कहा कि 15 साल शासन करने का अवसर मिला । आपने क्या किया ? मैं बताना चाहता हूं कि

व्यवधाान

पहले सुनने की कोशिश कीजिये । यदि प्रश्न को छेड़े हैं तो सुनने की भी कोशिश कीजिये । सभापति महोदय, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में 15 साल शासन रहा, माननीया श्रीमती राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में 15 साल का शासन रहा, उसी शासन की ही देन है कि आज प्रतिपक्ष के नेता के रूप में श्री प्रेम कुमार जी विराजमान हैं। नहीं तो कोई उच्च वर्ग के लोग ही इस कुर्सी पर होते । आज उनको मौका मिला है जो माननीय लालू प्रसाद जी की ही देन है । यह प्रश्न माननीय नेता,प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता है।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : अब आप बैठ जाईये । मा0स0 श्री मो0 तौसीफ आलम । आपको भी 10 मिनट का समय आवंटित किया गया है, आप ध्यान रखियेगा । आप अपने क्षेत्र की बात उठाईये ।

श्री मो0तौसीफ आलम : सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा पेश तृतीय अनुपूरक बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, आज जो महागठबंधन के तहत हमारी सरकार बनी है, हमलोग जो वादा किये थे, हमारे गठबंधन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी वादा किये थे कि गांव-गांव में बिजली, गांव-गांव में सड़क और गांव-गांव में पानी देंगे । मैं ग्रामीण कार्य विभाग के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसलिए तीनों वादों की बातें बोल रहा हूं और उन वादों को पूरा करने जा रहे है जो इस बजट में देखा गया है । खास करके ग्रामीण कार्य विभाग में जो गांव-गांव में जो रोड मैप के आधार पर डी0पी0आर0 तैयार हुआ तो हमलोग जो क्षेत्र में जाते हैं तो हमलोगों को अब बधाई मिल रहा है कि भाई, महागठबंधन के नेता ने जो वादा किये थे कि गांव-गांव में रोड बनेगा, आज जो डी0पी0आर0 बन रहा है और जो बन करके आया है, हम समझते हैं कि आज उनका वादा पूरा होने जा रहा है और इंशा अल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में जितना लाया है, हम समझते हैं कि आनेवाले बजट मे पूरा जरूर कर देंगे । सभापति महोदय, मैं खास करके भाजपा भाईयों से कहना चाहूंगा कि 2014 में जो प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह जी ने बिहार को पैसा दिया था, आज जिस तरह से बोल रहे हैं, क्या उसी आधार पर आज पैसा दे रहे हैं ? अगर नहीं दे रहे हैं तो सदन के माध्यम से भाजपा भाईयों से आग्रह करना चाहेंगे कि सदन की कमिटी बनाकर हमलोग भारत सरकार से प्रधानमंत्री सड़क जो आज अधूरा पड़ा हुआ है, उसका काम कैसे पूरा हो, हमलोगों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए । यह नहीं होना चाहिए कि 15 साल की लालू जी के सरकार ने यह यह किया, वह किया । मैं भाजपा साथियों से कहना चाहूंगा कि आप भी बिहार सरकार में 9 सालों तक रह करके आपने क्या किया ? आप की भी खामियां देखा जायेगाा । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह गलत किया और आप सही किये।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : आपका विचार अत्यंत ही सुन्दर है । अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताईये । सरकार बैठी हुयी है, उसे ग्रहण करने के लिये । अपने क्षेत्र में केन्द्रीत कीजिये ।

श्री मो0तौसीफ आलम : जी । हम भाजपा भाईयों से इतना आग्रह करेंगे कि 2014 का इस प्रस्ताव में लगभग 6 हजार किलोमीटर ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : शांति शांति ।

श्री मो0तौसीफ आलम : बोलने की क्षमता रखते हैं तो आपको सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए । हम किसी के विरूद्ध बात नहीं कर रहे हैं । आज हमारा बिहार प्रगति पर है । इसमें कोई शक नहीं है । मैं ग्रामीण कार्य विभाग को अपनी ओर से एक सुझाव देना चाहता हूं कि मेरा सुझाव यह है कि हमारे क्षेत्र में जैसे मुख्यमंत्री संपर्क योजना के तहत जो रोड बनता है, 2

किलोमीटर हो, 3 किलोमीटर हो, रोड तो बन जाता है लेकिन बीच में जो नदी-नाला रहता है, उस पर पुल नहीं बनता है, इसका प्रस्ताव लिया जाय । यह मैं सरकार से आग्रह करूंगा । मेरा क्षेत्र बहादुरगंज है । बहादुरपुर प्रखंड के अन्तर्गत कटहलबाड़ी हाट से चुन्नीबाड़ी होते हुये कुमारपल्ली हाट एक रोड मुख्यमंत्री संपर्क योजना के तहत बना है बीच में धार की वजह से पुल नहीं बना है, जिस पर आवागमन बंद है । दोनों तरफ से रोड बन गया है, पुल अभी तक नहीं बना है । ठीक उसी तरह से तुसलिया हाट से बीबीगंज जानेवाली सड़क में पुट्टीमाड़ी धार में पुल नहीं बना है । हम चाहेंगे कि रोड तो बन जाता है, पुल की योजना नहीं ली जाती है । हम चाहेंगे कि पुल की योजना को भी लिया जाय। पुल बन जाने से ग्रामीण क्षेत्रों का जो विकास हो रहा है, हमारे महागठबंधन सरकार के पहल से और जिस तरह से प्रयास है हम समझते हैं कि पूर्ण विकास नजर आयेगा, जब पुल बन जायेगा । ठीक उसी तरह से जिस तरह से मुख्यमंत्री सड़क का काम हो रहा है ,हमारे क्षेत्र में एक-दो ऐसे रोड हैं, जिस में काम तो हुआ है लेकिन गुणवत्ता की कमी है । उसके लिये भी हम आग्रह करेंगे कि गुणवत्ता पर ध्यान देकर स्थानीय विधायक का भी सुझाव लिया जाय । जब डी0पी0आर0 बनता है, आनन-फान में डी0पी0आर0बना दिया जाता है, खास करके जब रोड क काम होता है, कोई भी अभियंता, कोई भी कार्यपालक अभियंता नहीं रहते हैं । इसका मतलब है कि कार्यपालक अभियंता की भी उसमें मिली-भगत होगी । मैं ऊंगली नहीं उठा रहा हूं । लेकिन यह जांच का विषय है।

क्रमश :

टर्न-16/सत्येन्द्र/3-3-16 .

मो0 तौसीफ आलम(क्रमशः): मैं चाहूंगा और सरकार से आग्रह करूंगा कि इस बिन्दु पर भी ध्यान दिया जाय और जहां भी सड़कें बने वहां स्थानीय इंजीनियर खड़ा रहे ताकि कामकाज में गुणवत्ता हो। सभापति महोदय, हो सके तो माननीय सदस्य जो उस क्षेत्र के हैं उनको भी सूचना हो कि आज ढलाई होने वाला है आप भी प्राथमिकता के तौर पर आईए, भागीदारी निभाईए। इससे हम समझेंगे क्षेत्र का भला होगा ही, उस क्षेत्र के साथ-साथ जो वादा किये गये एम0एल0ए0 लोग विधायक लोग उनलोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में एक समस्या है कि 15-20 सालों से कुछ आर0ई0ओ0 रोड का मरम्मति नहीं हुआ है। अन्य काम में तो हमलोग मुख्यमंत्री सम्पर्क योजना के तहत डी0पी0आर0 बनवा लेते हैं लेकिन जो पुराने रोड है उसमें काम नहीं हो पा रहा है। जैसे बहादुरगंज सी0पी0डब्लू0डी0 रोड से सरंडा होते हुए 3 कि0मी0 का रोड है, कई वर्षों से उसका मरम्मति नहीं हुआ है। हम आपके माध्यम से

कहना चाहेंगे सभापति महोदय कि इस रोड की भी मरम्मति का काम किया जाय और दूसरा एक रोड है लोहगरा हाट से तुलसिया मार्ग होते हुए तुलसिया आर0ई0ओ0रोड तक इस रोड का भी 6 वर्षों से मरम्मति नहीं हुआ है इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार को आग्रह पूर्वक कहना चाहेंगे कि उसकी भी मरम्मति हो। यही कहकर के मैं आप सब को धन्यवाद देना चाहता हूँ खासकर के सभापति महोदय को जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।

सभापति(मो0 इलियास हुसैन):बहुत अच्छा सुझाव आया आपका जनता के पक्ष में। अब मैं राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य सैयद अब्बु दौजाना से आग्रह करता हूँ कि वो अपना विचार रखें। आपका भी समय 10 मिनट है।

मो0 सैयद अब्बु दौजाना: सभापति महोदय,मैं सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ है। हमारी महागठबंधन की सरकार ग्रामीण सड़कों के मामले में जो प्रगति की है वह किसी से छुपा नहीं है। आज हमारे विपक्षी भाईयों को बोलने का कोई हक नहीं है। आज राज्य के किसी कोने से आने-जाने के लिए कोई कठिनाई नहीं हो रही है।सभापति महोदय, हमारी सरकार ने पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछा दिया है। ऐसे कई ऐतिहासक पूल का निर्माण कराया गया जो आजादी से पहले बना था और ध्वस्त हो चुका था।महोदय, पहले लोगों को 100 कि0मी0 जाने के लिए 6 से 7 घंटा लगता था लेकिन आज वो पुल का निर्माण हो गया जिससे लोगों को आने-जाने में दो से ढ़ाई घंटा ही लगता है और आसानी से सफर हो जाता है। सभापति महोदय, मुझे गर्व है महागठबंधन की सरकार पर, मुझे गर्व है अपने गठबधंन के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पर, मुझे गर्व है अपने बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर सभापति महोदय,हमारे महागठबंधन की सरकार ने पूरे बिहार में ग्रामीण सड़कों का जाल बिछा दिया है। केन्द्र सरकार ने भी माना है कि बिहार में इतनी तेज रफ्तार से सड़क का विकास होना अपने आप में एक मिसाल रखता है। सभापति महोदय, हमारी महागठबंधन की सरकार ने इसी वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7750 लाख रू0 आवंटित किया जिसमें योजना मद में 5954 करोड़ 31 लाख रू0 एवं योजना मद में 1196 करोड़ 19 लाख रू0 शामिल किया गया है। सभापति महोदय हमारी गठबंधन की सरकार ने इस वित्त वर्ष 2016-17 में 5780 कि0मी0 रोड लंबी ग्रामीण पथों को निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। हमारे महागठबंधन की सरकार ने पी0एम0जी0एस0वाई सड़क अन्तर्गत 27 आई0ए0पी0 जिलों में 500 से अधिक एवं 11 आई0ए0पी0 जिलों में 250 से अधिक आबादी वाले गांव और बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने की योजना बनायी है। सभापति महोदय,सरकार ने नवम्बर 2015 में 6 हजार 96 करोड़

30 लाख रू0 1372 कि0 मी0 सड़कों का कालीकरण करने का सच किया जो मुझे एवं हमारे सदस्य को गर्व है। सभापति महोदय,बिहार के मतदाताओं ने अभूतपूर्व जनादेश दिया जिससे महागठबंधन की सरकार बनी और चुनाव में किये गये वायदे के आधार पर सात निश्चय घोषणा के अनुरूप युवाओं का आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, घर में नल का जल, घर घर तक पक्की नाली सड़कें का निर्माण, शौचालय का निर्माण आदि । सभापति महोदय,बिहार में पिछले पांच वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुआ है लेकिन केन्द्र द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना में कटौती होने से पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि,सम विकास योजना के नक्सल प्रभावित जिलों के लिए समेकित कार्य योजना के तहत धन राशि आवंटित नहीं होने से बिहार को काफी नुकसान हो रहा है। बिहार जैसे राज्य को घाटे की भरपाई के लिए अलग से व्यवस्था की जाय। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के सरकार के जमाने में जिस तरह से आन्ध्र प्रदेश को मदद की गयी थी उसी तरह बिहार की भी मदद होनी चाहिए। इसी तरह से मदद बिहार को जरूरत है। बिहार के लिए कटौती करना कानून संविधान के खिलाफ है । महागठबंधन के हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने केन्द्र सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आग्रह किये थे लेकिन केन्द्र सरकार ने बिहार के प्रति व्यक्ति आय की औसत कम होने का अन्तर बतलाकर कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य की जरूरत नहीं है सबसे पहले पहलु है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर निवेशकों को केन्द्रीय करों में छूट जरूरत थी। सभापति महोदय,महागठबंधन सरकार की कृषि रोड मैप के अधीन खाद्यान्न फसलों का उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए श्रीविधि से धान और गेहूं की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए लघु सीमांत किसानों मजदूरों के लिए उनको प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। सभापति महोदय, महागठबंधन सरकार ए0डी0बी0 के सहयोग से गंगा में सिक्स लेन कच्ची दरगाह-विदुपुर जिसकी कुल लागत 4988 करोड़ के परियोजना पर काम चालू करवाया है। गंगा पथ-वे का निर्माण, एम्स दीघा एलिवेटेड कोरीडोर का निर्माण और राज्य के कई जिलों में पुल पुलियों का निर्माण जारी है। सभापति महोदय, राज्य के राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास के लिए उन्नत कोटि के सड़कों का निर्माण कराने का महागठबंधन सरकार ने संकल्पित है। 250से अधिक आबादी वाले बसावटों को सम्पर्क पथ से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

सभापति(मो0 इलियास हुसैन):अब आपका समय समाप्त हुआ। एक मिनट बोल लीजिये।

मो0 सैयद अबू दोजाना : सभापति महोदय,मैं पहली बार बोल रहा हूँ जो भी गलत या सही होगा।

सभापति(मो0 इलियास हुसैन): बहुत अच्छा,बहुत अच्छा । बोलिये।

मो0 सैयद अब्बु दौजाना सभापति जी,मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

श्री मनीष कुमार: सभापति महोदय,ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा लाये गये द्वितीय अनुपूरक बजट मांग के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सदन के प्रति आभार प्रकट करते हुए आसन के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय,हमारे पहले भी कुछ साथियों ने ग्रामीण कार्य विभाग के संदर्भ में अपनी बातें रखीं और बातों के दौरान सच्चाई व्यक्त किया कि सचमुच बिहार की 80 प्रतिशत लगभग आबादी गांव में वास करती है और ग्रामीणों के प्रति हमारी सरकार की चिन्ता है। गांव का विकास हो इसके लिए हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी कृत संकल्पित हैं।(क्रमश:)

टर्न-17/मधुप/03.03.16

श्री मनीष कुमार : ..क्रमश:... उनकी इच्छा रहती है कि गॉव के हर ग्रामीण वासियों के चेहरे पर खुशहाली हो, बिहार वासी खुशहाल रहें, बिहार खुशहाल रहे और प्रगति के राह पर बिहार को एक ऐसे मुकाम पर ले जाया जाय जिसकी चर्चाएँ हमारे आज जो विपक्ष के साथी बैठे हैं, वे जब हमलोगों के साथ थे तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का गुणगान करते हुये कभी-कभी सचमुच मन की बात बता देते थे और अमेरिका को उन्नति के राह पर आगे बढ़ाते हुये बराक ओबामा जैसे व्यक्ति के साथ उनकी तुलना कर बैठते थे । लेकिन आज क्या परिस्थिति आ गई, जिसका उल्लेख हमारे बड़े भाई आदरणीय नेता श्री सिद्दिकी साहब ने किया कि एक समय था, क्या वातावरण था, आप उनकी गुणगान करते थे और आज क्या परिस्थिति आ गई कि आज विक्षुब्ध होकर, जो परिस्थिति बनी, आज जो आप विपक्ष में बैठे और विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए, कभी-कभी मैं उनको यह कहना चाहता हूँ कि यहॉ पर लिखा हुआ है कि संसदीय लोकतंत्र में विराधी दल सरकार के ही अंग होते हैं, जब सदन में बैठते हैं तो

स्वाभाविक है कि चर्चाएँ होती हैं, सत्ता पक्ष के साथीगण के द्वारा सरकार की उपलब्धियों को बताया जाता है, वर्णित किया जाता है और साथ-ही-साथ कुछ सलाह और सुझाव के रूप में भी अपनी बातों को रखने का काम किया जाता है । यही अपेक्षा अन्य साथियों से भी की जाती है, विपक्ष के साथीगण से भी यही अपेक्षा की जाती है कि कुछ सलाह दें और अगर सरकार के अंग हैं तो स्वाभाविक है कि सरकार के द्वारा किये गये कार्यों और उपलब्धियों की सराहना की जाय, यह अपेक्षा रखी जाती है । लेकिन परम्परा के अनुसार जब विपक्ष में साथी बैठ जाते हैं तो जो अच्छे काम होते हैं जिसका उल्लेख हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने भी किया कि जब अच्छे कार्य किये जायं तो उसकी सराहना करनी चाहिये न कि विपक्ष में बैठकर नकारात्मक सोच के तहत उसका विरोधाभास प्रकट करना चाहिये । मैं अपेक्षा रखता हूँ विपक्ष के साथियों से, अगर कल तक आप उसी उपलब्धियों की प्रशंसा करते थे तो आज क्या आ पड़ी कि आपको वह प्रशंसा आज नकारात्मक सोच में बदल गया है, इस दो-तीन महीने के अन्दर ही क्या बदलाव आ गया है ? अगर आपको सरकार के अंग के रूप में लिया जाता है तो आपसे यह अपेक्षा रखी जाती है। जब बाहर चर्चा होती है, जब एक साथी के रूप में आपसे चर्चा होती है तो आप भी खुले मिजाज से प्रकट करते हैं कि सचमुच भाई मनीष कुमार जी, नीतीश कुमार जी के राज में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है, बिहार विकास के पैमाने पर देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने लायक हो गया है, यह आप बाहर बोलते हैं । लेकिन जब अंदर आते हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाते हुये नकारात्मक सोच प्रकट करते हैं ।

यह सब बातें तो हमेशा हमारे साथियों द्वारा किया जाता है, मैं इन बातों को ज्यादा न दोहराते हुये चूंकि आज ग्रामीण कार्य विभाग के सन्दर्भ में बोलने का अवसर मिला है । मैं इस ओर अपनी बातों को रखना चाहता हूँ । मैं कह रहा था कि स्वाभाविक है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने गरीब, दुखियों और ग्रामीण स्तर के लोगों के मुख पर आवाज देने का काम किया, उन्हें बोली देने का काम किया, उन्हें अपनी मूलभूत सुविधाओं से अवगत कराने का काम किया लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, उनके सपनों को साकार करने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया और सारी मूलभूत सुविधाओं को प्रदत्त करने की जिम्मेदारी, जिसके लिए कृत संकल्पित थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम किया है । आज उसी के सन्दर्भ में ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत, स्वाभाविक है कि ग्रामीण कार्य जो ग्रामीणों से सरोकार रखता है, एक तरह से कहा जाय तो वह

ग्रामीणों के लिए लाईफ-लाईन होती है और उन ग्रामीणों के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा अनुपूरक बजट की माँग रखी गई है । मैं इस समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ ।

आज ग्रामीणों के हित के लिए जितनी भी राशि की माँग की जाय, मुझे तो लगता है कि वह कम पड़ जाती है । हमारे विपक्ष के साथी कटौती प्रस्ताव कर रहे हैं, शायद उनको ग्रामीण स्तर के परिवेश की जानकारी नहीं है । आज भी ग्रामीण स्तर बहुत गिरावट स्तर में है, उसे ऊपर लाने की जरूरत है । उसे ग्रामीण स्तर पर और मूलभूत सुविधाएँ प्रदत्त करने की जरूरत है । महोदय, लाल-बत्ती जल गया, लेकिन अभी तो मुझे और बोलना है ।

महोदय, मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए कहना चाहता हूँ कि जब लोक सभा का चुनाव था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जिन्होंने एक जिम्मेदारी ली कि झूठ कितना ज्यादा बोल सकें और झूठ का पुलिंदा बांधते हुये बिहार में कई रैलियाँ करने का काम किया और हर रैली में एक ही बात बोलते थे, दोहराते थे कि हर गरीब के खाते में 10-15 लाख रूपया की राशि चली जायेगी । मैं इस सन्दर्भ में बोलना चाहता हूँ, हालाँकि उन्होंने तो झूठ के कई पुलिंदा बांधे, बेरोजगारों को रोजगार देने का आश्वासन किया लेकिन मैं विशेष तौर पर यह बोलना चाहता हूँ, कल हमारे साथी राजकिशोर भाई बता रहे थे, आ गये, इनके क्षेत्र में एक नौजवान लड़का था जिसकी शादी लगी थी । उस लोक सभा चुनाव के कार्यक्रम के दौरान जब वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना कि अरे भाई, चुनाव अगर जीत जायेंगे तो लगता है कि 15-20 लाख रूपया राशि मिल जायेगा और उस 15-20 लाख रूपया की राशि से जिस प्रकार से शहर के लोग हनीमून मनाने के लिए, सुख-सुविधा प्रदत्त के लिए बाहर जाते हैं, वह बच्चा भी इसी आशा में अपना शादी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया । वह यह तय किया कि शादी अब हम करेंगे तो चुनाव के बाद करेंगे, कहीं हमारे भी खाता में 15-20 लाख रूपया हो गया तो हम भी हनीमून मनाने बाहर जायेंगे । महोदय, स्वाभाविक है हमारे बिहार की भोली-भाली जनता को ठगकर आदरणीय मोदी जी ने वोट लेने का काम किया, पर वह बेचारा जो शादी के लिए अपनी तिथि को भी आगे बढ़ाने का काम किया वह टकटकी निगाह से अपने खाते को देखता रहा । वह बेचारा शादी तो बाद में किया लेकिन हनीमून मनाने बाहर नहीं जा पाया । X X X

महोदय, मैं कहना चाह रहा था कि ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा जो अनुपूरक बजट की माँग की गई है, वह सचमुच बहुत कम है, जितनी राशि दी जाय, वह ग्रामीण स्तर के उत्थान के लिए बहुत कम पड़ती है । मैं जानता हूँ कि ग्रामीण कार्य विभाग के साथ किस तरह का सौतेलापन, बल्कि पूरे बिहार राज्य के साथ सौतेलेपन का व्यवहार हमारी केन्द्र सरकार के साथियों के द्वारा किया जाता है । आज तक मैं भी विधान सभा में तीसरी बार जीत कर आया हूँ लेकिन इस बार पीड़ा महसूस होती है क्योंकि इस तरह के सौतेलेपन का व्यवहार हमने कभी आज तक नहीं देखा, हमारे साथियों ने भी पहले कभी ऐसे सौतेलेपन का एहसास नहीं किया । इन्हीं के दल के हमलोगों के सर्वमान्य नेता आदरणीय वाजपेयी जी के द्वारा चलायी गयी एक बहुत महात्वाकांक्षी योजना थी और हम सब लोग उससे लाभान्वित थे, ग्रामीण स्तर के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना थी । वह योजना महात्वाकांक्षी योजना थी और उसके तहत पूरे देश की सड़कों की बनावट में सुधार आई, गुणवत्ता आई और लोगों ने ग्रामीण स्तर पर सड़क को महसूस किया, सड़क से लाभान्वित हुये। आदरणीय मनमोहन जी की सरकार आई, उन्होंने भी इस महात्वाकांक्षी योजना को बरकरार रखने का काम किया...

सभापति (मोहम्मद इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री मनीष कुमार : आखिर इनलोगों के बीच कैसी सोच आई कि वाजपेयी जी के द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजना थी, उसे भी बंद करने का इन्होंने प्रावधान लाया ! शत-प्रतिशत राशि जो प्रधानमंत्री योजना केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाती थी, इनकी नई नीति के तहत, उस राशि में कटौती कर दी गई । उन्होंने नई नीति लाने का काम किया कि अब प्रधानमंत्री सड़क योजना में राज्य सरकार की भी राशि लगायी जायेगी । यह दोहरी नीति, गलत नीति के तहत.....

सभापति (मोहम्मद इलियास हुसैन) : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री मनीष कुमार : महोदय, मैं एक मिनट और बोलना चाहता हूँ चूंकि अपने क्षेत्र से संबंधित कई बातों को मैं नहीं रख पाया हूँ, प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में । महोदय, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दो मिनट मुझे और बोलने दिया जाय । ....क्रमशः...

श्री मनीष कुमार : (क्रमशः) महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना की यह विडम्बना है, चूँकि अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ हम अपने क्षेत्र की पीड़ा को बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के अन्तर्गत हमारे क्षेत्र में कई सड़कों का कम से कम पिछले 5 बार से टेंडर निकल रहा है परन्तु डर से कोई संवेदक टेंडर नहीं डालता है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत राशि लटक जायेगी, हमारी राशि लटक जायेगी.....

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : मनीष कुमार जी, अब हो गया आपका । कृपया आप बैठ जाईए ।

श्री मनीष कुमार : महोदय, मेरा एक और आग्रह है, एक तरफ जे0एन0यू0 के अध्यक्ष कन्हैया जिन्होंने बी0जे0पी0 के खिलाफ अपनी आवाज को बुलन्द करने का काम किया तो उनके साथ देशद्रोह लगाया गया और देशद्रोह के अन्तर्गत उनको जेल भेजा गया और उसे सजा दिया गया । XXX

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, कृपया आप बैठ जाईए ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, जो शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के बारे में इन्होंने कहा, उसको निकाला जाय महोदय ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : क्या कहा ?

श्री प्रेम कुमार : इन्होंने आपत्तिजनक बात कहा है ।

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि विकास में जो बाधक है, विकास में जो बाधा डालते हैं, उनके बारे में कहा गया । प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं कहा गया है ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार : माफी मंगवाईए ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : देशद्रोह शब्द को प्रोसीडिंग्स से निकाला जाय ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, हमारा आपसे आग्रह है कि वे खेद व्यक्त करें । वे माफी मांगे महोदय ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार : ये माफी मांगे, प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा है ।

श्री श्याम रजक : सभापति महोदय, इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है । उन्होंने कहा है कि विकास में जो बाधक होगा ।

श्री प्रेम कुमार : माफी मंगवाईए ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : प्रोसीडिंग्स से हमने उसको हटा दिया । वह हट गया ।

श्री प्रेम कुमार : उनसे माफी मंगवाईए ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : प्रोसिडिंग्स से वह शब्द हट गये ।

श्री प्रेम कुमार : सत्ताधारी दल के विधायक इस तरह की बातें बोल रहे हैं, इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे महोदय । माफी मंगवाईए ।

सभापति महोदय, आपसे आग्रह है कि वे खेद प्रकट करे कि हमसे गलती से बोला गया है । वे वापस ले लें, बात खत्म हो जायेगी ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : उसको हटा दिया गया है ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : महोदय, जो आपत्तिजनक शब्द है, उसको प्रोसीडिंग्स से निकाला जाय।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : निकाल दिया गया, ऑर्डर हो गया । वह हट गया ।

श्री प्रेम कुमार : माफी मांगे । एक विधायक महोदय लगातार .....

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए वह शब्द हट गये । प्रोसीडिंग्स से उन तमाम शब्दों को हटा दिया गया ।

(व्यवधान)

आप क्या चाहते हैं ?

श्री प्रेम कुमार : महोदय, हमारा आग्रह सिर्फ इतना है कि उनके मुँह से निकला है, प्रधानमंत्री की बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया । जो आपत्तिजनक शब्द है, उसके लिए कम से कम माननीय सदस्य खेद प्रकट करें, यही मेरा आपसे आग्रह है ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, आप क्या बोले हैं ? शांति-शांति ।

श्री मनीष कुमार : यहां के बारे में जब वे बात करते हैं तो उनकी आवाज क्यों नहीं निकलती है । उस समय भी उनको बोलना चाहिए ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, आपने क्या कहा ?

श्री मनीष कुमार : महोदय, हमने क्या कहा, वह तो प्रोसीडिंग्स में भी देखा जा सकता है । मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति विकास कार्यों में रूकावट हो, बाधक हो, उसपर देशद्रोह की धारा लगनी चाहिए ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : प्रधानमंत्री के बारे में तो इन्होंने नहीं कहा ।

श्री प्रेम कुमार : ये बात बदल रहे हैं । पूरा सदन सुना है महोदय ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : नेता विरोधी दल की बात सुनिए ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, सारे सदस्य सुने हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : वे तो कह रहे है कि हमने नहीं कहा है ।

श्री प्रेम कुमार : सारा हाऊस सुना है । पूरा हाऊस सुना है, हम नहीं कह रहे हैं, पूरा सदन सुना है ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : वे सारी चीजें प्रधानमंत्री से संबंधित उनका जो वक्तव्य आया है, सब लाईन निकाल दिया जाय ।

श्री प्रेम कुमार : खेद प्रकट करें ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री प्रेम कुमार : दो दिन पहले अखबारों में महोदय, गोपाल मंडल जो विधायक हैं महोदय, उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों की जीभ काट लेंगे, जान से मार देंगे । यह गोपाल मंडल जी का बयान आया है ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : यहां नहीं कहा है ।

श्री श्रवण कुमार : नेता प्रतिपक्ष, जब हाऊस ऑर्डर में नहीं है तो बोल कैसे रहे हैं ? सभापति महोदय, पहले तो हाऊस को ऑर्डर में लीजिए और तब न नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखेंगे। (व्यवधान)

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : माननीय संसदीय कार्य मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता क्या कहना चाहते हैं, वे अपनी बात को रखें, सरकार जानना चाहती है कि वे क्या कहना चाहते हैं ? लेकिन उसके कवल जो माननीय सदस्य वेल में हैं, उनको अपने आसन पर जाना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि बार-बार दो मिनट में, एक-एक मिनट में माननीय सदस्य को वेल में भेजने के लिए यह सदन नहीं है महोदय । अगर कोई चूक हुई है, अगर कोई गलती हुई है तो आसन सर्वोपरि है, आसन का निर्णय सर्वोपरि होगा महोदय, जो आसन से निर्देश दिया जायेगा ..... (व्यवधान)

महोदय, आसन सर्वोपरि है । आसन से अनुरोध करेंगे कि आप इसमें हस्तक्षेप करें महोदय और जो आसन का निर्देश होगा, उसका पालन किया जायेगा ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है, उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी जो हुई है, हम आपसे इतना ही आग्रह करना चाहेंगे कि माननीय सदस्य इसके लिए खेद प्रकट कर दें, हमलोग वापस आ जायेंगे, मात्र इतना ही तो बात है ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सारे लोगों को वापस बुलाया जाय । मैं एक्शन लेता हूँ ।

श्री प्रेम कुमार : माननीय सदस्य, खेद प्रकट करें । जो आपत्तिजनक शब्द कहा है, उसके लिए माननीय सदस्य से माफी मंगवाया जाय । जब तक माफी नहीं मांगेगे, तब तक हमलोग नहीं हटेंगे ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार । जब आपने प्रधानमंत्री के संबंध में कुछ कहा है तो आप सदन की गरिमा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए क्षमा मांगना बहुत बड़ा पाप नहीं है । आप हाऊस को ऑर्डर में चलने दें, आपका एक शब्द हाऊस को ऑर्डर में ला देगा ।

श्री मनीष कुमार : महोदय, अगर मेरी इस तरह की बात से इन्हें ठेस पहुँची है.....

(व्यवधान)

महोदय, अगर मैंने बिहार के विकास के संबंध में चूँकि मैं बिहार का नागरिक हूँ और मुझे बिहार की चिन्ता है । माननीय नीतीश कुमार जी, हमेशा बिहार के लिए दिल्ली जाते हैं, विकास के लिए वहां लोगों के पास जाते हैं, हमारे बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार करने का काम इन लोगों के द्वारा किया जाता है, उसपर हमने चिन्ता व्यक्त करने का काम किया महोदय ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, सुनिए, आप आसन के प्रश्न का जवाब दीजिए । कृपया शांति-शांति ।

श्री मनीष कुमार : अगर मेरी बात से इन्हें ठेस पहुँची हो महोदय तो स्वाभाविक है कि मैं बहुत छोटा हूँ , प्रधानमंत्री इतने बड़े व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में मैं कभी खराब शब्द नहीं बोल सकता हूँ लेकिन मुझे खेद है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण अपने-अपने सीट पर चले गये)

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, कुमार सर्वजीत ।

माननीय सदस्य नेमतुल्लाह साहेब, आपका समय 10 मिनट ।

---

xxx - इस अंश को आसन के आदेशानुसार विलोपित किया गया ।

श्री श्रवण कुमार : महोदय, आसन से मेरा अनुरोध होगा कि इसमें पुराने सदस्य भी जीतकर आये हैं और नये सदस्य भी जीतकर आये हैं तो एक आसन से निर्देश दे दिया जाय कि जो नये सदस्य जीतकर आये हैं, अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है तो कभी-कभी क्षमा भी किया जाना चाहिए ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : ठीक है । माननीय नेता विरोधी दल, बड़े पुराने साथी हमलोगों के साथ रहे हैं, 30 साल बीत गये, मैं इनसे आग्रह करूँगा कि इन सदस्यों के बीच में जो नौजवान हैं, आप पिता तुल्य हैं, इनको आर्शीवाद और क्षमा भी दिया कीजिए । बोलिए नेमतुल्लाह साहेब ।

(व्यवधान)

आप बोलिए, आपका टाईम बर्बाद हो रहा है, आप बोलिए । कृपया शांति ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : जनाबे सदर, आज ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित जो मांग पेश की गयी है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आज ग्रामीण कार्य विभाग को पैसे की जरूरत है, इसलिए पैसे की जरूरत है, निकालने की जरूरत है कि खेतों और खलियानों में हरियाली लाया जा सके । रोडों में हरियाली लाना है, रोडों को बनाना है, ग्रामीण सड़कों को बनाना है, इसलिए इनको पैसे की जरूरत है । महोदय, विरोधी पक्ष के जो हमारे मुख्य सचेतक हैं अरूण जी, वे बोल रहे थे और हमलोग बड़े धैर्य से उनकी बातों को सुन रहे थे । उन्होंने अपने पूरे 45 मिनट में सिर्फ इर्द-गिर्द घूमते रहे, एक शब्द भी ग्रामीण सड़कों के बारे में उन्होंने नहीं कहा ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): आप बोलिए न, आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आप ग्रामीण सड़कों के बारे में बोलिए ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : आज ग्रामीण सड़कों को बनाने हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को पैसे की जरूरत है, इसलिए जरूरत है सदर महोदय, आप जानते हैं कि बिहार में सड़कों का जाल बिछाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का वादा है, महोदय, यह आप जानते हैं । ये लोग बात करते हैं 15 साल की, 15 साल में लालू-राबड़ी के राज में जितनी ग्रामीण सड़कें सुनिश्चित रोजगार योजना से बनी, आज उसी को पक्कीकरण कराने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है । जो ग्रामीण सड़कें बनी हुई थी, जिनका ईंटकरण हुआ था, उस वक्त का बना हुआ रोड आज भी मौजूद है । उस समय बहुत सारे सड़कों का जाल बिछाया गया था । हमारे गोपालगंज जिला में निविदा निकली, गड़बड़ियां होती हैं, मैंने कल ही लिखकर भेजा कि निविदा में कुछ गड़बड़ी हुई थी, कुछ त्रुटि हुई थी तो इस संबंध में हमने सचिव महोदय को लिखकर भेजा कि आप देखवाइए । पहले जो

निविदा होती थी, उसमें तो जो निविदाकार थे, पहले तो वे टेंडर डालने हेतु पहुंच नहीं पाते थे, वहां दादागिरी चलती थी लेकिन आज ऑनलाईन हो गया है एप्लाई करने के लिए लेकिन टेंडर में हर चीज को दर्शाना चाहिए, ओपेन होना चाहिए ताकि निविदाकार जो है, वे अपना टेंडर डाल सकें । अरूण जी, एक बात बोल रहे थे, वे अस्पताल के बारे में कह रहे थे । मैं पिछले सप्ताह हॉस्पीटल गया था पी0एम0सी0एच0, एक मेरे क्षेत्र के पेसेंट थे, वह वहां आया हुआ था, उसका ऑपरेशन कराना था । हम वहां गये और हमने कहा कि हमलोगों का एम0एल0ए0 वार्ड है, कहो तो हम लिखकर दे दें तो उसने कहा कि यहां तो इतनी सफाई है, इतना साफ-सुथरा बेड है कि रहने में कोई कठिनाई नहीं है । इन लोगों के राज में जब ये लोग मंत्री थे तो हॉस्पीटल मे, बहुत सारे पी0एच0सी0 में जानवर घूमा करते थे ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य आपने अच्छी बात बतायी, चूंकि यहां सरकार, तेजप्रताप बाबू भी बैठे हुए हैं....

श्री नेमतुल्लाह : और ब्रेकफास्ट के लिए दूध, अंडा एवं ब्रेड का इन्तजाम था और वह मेरे सामने आया तो इतनी अच्छी स्थिति अस्पताल की थी । महोदय, कुछ सड़कें जो बाकी रह गयी हैं, हमारी सरकार को सड़कों की जाल बिछाने की इच्छा है । अब मैं अपने क्षेत्र की बात शुरू करता हूँ । महोदय, कुछ सड़कें हैं जो हमारे मुख्य सड़क से जुड़ी हुई है लेकिन अभी वह खराब हालत में है । सदर महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण कार्य मंत्री जी को अपनी क्षेत्र की सड़कों के बारे में कहना चाहता हूँ....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री आप ध्यान दें, माननीय सदस्यों की समस्याओं को ग्रहण कीजिए ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : पकइयां से मांझा बाजार तक जानेवाली सड़क खराब है, मेन सड़क है । सिवान सड़क से निकलकर वह भगवान बाजार से निकलकर लोहजीरा होते हुए मांझा प्रखंड तक जानेवाली सड़क । महोदय, शाहपुर से निकलकर बैकुंठपुर होते हुए मांझा तक जानेवाली सड़क.....

.....क्रमशः....

मो0 नेमतुल्लाह : क्रमशः.....एन0एच0-28 से निकलकर सिकमी ग्रम जानेवाली ग्रामीण सड़कें हैं। महोदय, ये सब ग्रमीण सड़कें हैं जिनका पक्कीकरण कराना अति आवश्यक है। महोदय, एन0एच0-28 से निकलकर मधु सरिया होते हुए सहलादपुर तक जानेवाली सड़क- कविलासपुर से निकलकर पैठानपट्टी तक जानेवाली सड़क ग्रमीण सड़क है। कुछ बरौली में है, इसको अगर ले लें तो इसीलिए हम कहते हैं कि पैसा इनको कम है तो और पैसे की मांग करें, सदन देने के लिए तैयार है। महोदय, बरौली बाजार से निकलकर बगैठी होते हुए शेर तक जानेवाली सड़क, माजा-बरौली रोड से निकलकर मांझी बरौली से निकलकर सरयानयन होते हुए माधोपुर तक जानेवाली सड़कें.....

सभापति(मो0इलियास हुसैन) : इसको लिखकर दे दीजिएगा।

मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, सीवान सरखरा से रतनसराय स्टेशन होकर जो सड़क जाती है वह बहुत बुरी हालत में है। वह मांझी बरौली मिलती है। महोदय, कुछ जानकारी मिली है कि दरभंगा के साथी ने हमको कहा है कि कुछ सड़कों में बनाने में गड़बड़ी है। ये गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच में यह सड़क गुजरती है। यह सड़क बनी हुई है। यह अभियंताओं और कुछ निविदादाताओं से मिलकर इसमें काफी घटिया मैटेरियल दिया गया है। इसकी जॉच करा लिया जाय। सकरी-महाविद्यालय ये एस0सी0 फंड का है, पी0एम0जी0एस0वाइ0 पी0डब्लू0डी0 पथ- बगहजा से आनन्द नगर इन तीनों सड़कों पर इतना खराब मैटेरियल दिया गया है कि अभी पूरा बना नहीं कि टूटना शुरू हो गया है। महोदय, इसकी जॉच कराकर इसपर कार्रवाई करना चाहिए।

सभापति (मो0इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, जो जन्म लिया है वह मरेगा नहीं क्या ? जहां बनता है वहीं न टूटता है ?

मो0 नेमतुल्लाह : आज ही जन्म लिया और आज नहीं न मर जायेगा ? उसके लिए तो कुछ समय चाहिए, पूरी जिंदगी बिताने के बाद एक लंबी उम्र की दुआ करते हैं हमलोग कि एक लंबी के बाद अगर मरे तो उसको स्वर्ग में स्थान मिलता है। अगर पाप करके मरेगा तो नर्क में ही जायेगा। जैसे हमारे साथी थोड़े-थोड़े बात पर नाराज हो जाते हैं इनको नाराज नहीं होना चाहिए। हम वैसा कोई बात इनलोगों को नहीं बोलते हैं, लेकिन एक बात बोलते हैं कि ये पैसे की जो कटौती किये हैं उसको वापस ले लें। चूंकि ग्रामीण कार्य विभाग में पैसे की अति आवश्यकता है, अगर पैसा निकलेगा तो ग्रामीणों का जीवन उद्धार होगा - सड़कें चमेगी, पुलिया बनेगा और पुल पुलिया जिस तरह से बन रहा है। ऐसे कटौती तो केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में काट ही रही है और चीज में कटौती हो ही रही

है। इसलिए जो सौतेला व्यवहार केन्द्र सरकार कर रही है यह जग जाहिर है। इसलिए हम सारे लोगों को एक होकर के बिहार का, चाहे उस पक्ष के हों, चाहे इस पक्ष के हों एक होकर हमलोग दिल्ली जाकर अपनी मांग रखें। अपनी गुजारिश करें, अपनी बात कहें कि भाई, पैसा दीजिएगा तो विकास होगा। चूंकि झारखण्ड के बंटवारे के बाद सब खत्म हो गया है, इसलिए पैसा देना आवश्यक है।

सभापति (मो0 इलियास हुसैन) : अब आप समाप्त कीजिए।

मो0 नेमतुल्लाह : आपने बोलने का मौका दिया, बहुत कम समय दिया। इसीलिए दिल से धन्यवाद।

सभापति (मो0 इलियास हुसैन) : आपको 10 मिनट दिया जाता है। क्षेत्र की समस्याओं को रखिये, अग्नि की उत्पत्ति मत कीजिएगा।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : माननीय सभापति जी, आपने जो ग्रामीण कार्य विभाग के वित्तीय वर्ष-2016-17 और 2015-16 पर जो चर्चा करने का समय दिया है, उसके लिए हम आभारी हैं। सभापति जी, बिहार का जो बजट का आकार और योजना है, जो बढ़ा है। उसके साथ-साथ बिहार का जो विकास दर है स्थिरता, निरंतर और कदम-दर-कदम विकास की गति बढ़ा रहे हैं। पहले माननीय नीतीश कुमार जी ने लंबी सड़क बनाने पर जोर दिया। अब गांव और टोला के गली-गली तक सड़क बने, नाली बने उसपर जोर दिया। मित्रों, यह बड़ी बात है कि देश के सबसे अधिक जो औसतन विकास दर है, वह हासिल करके लगता है कि देश में सुंदर राज्य बनने की कल्पना की ओर जा रहे हैं। बिहार के बजट आकार को लेकर, योजना आकार को लेकर, हर मोर्चे पर एक सम्मान जनक स्थिति हासिल किया। एक दशक पहले जो हमारा 18 हजार करोड़ आकार शुरू हुआ था, अब वह डेढ़ हजार करोड़ रूपया तक पहुंच गया है। यह बड़ी बात है विकास के लिए और बिहार के लिए- हम इस अनुपूरक बजट पर चाहते हैं कि यह सर्वध्वनि से सर्वसम्मति से पास हो। याद कीजिए तत्कालीन जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री दूरदर्शी और लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रारंभ इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि केन्द्र द्वारा जो उसका प्रतिशत राशि है उसको राज्य को उपलब्ध कराकर उसको मूर्त्त रूप दिया जायेगा। इस व्यवस्था को बाद के प्रधानमंत्री तत्कालीन माननीय श्री मनमोहन सिंह जी ने लागू रखा, लेकिन ऐसी कौन सी विपदा और आपदा आ गयी कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लागू की गयी व्यवस्था को यू0पी0ए0 सरकार के द्वारा यथावत् रखा गया, लेकिन वर्तमान जो हमारे एन0डी0ए0 की सरकार है दिल्ली में उसके द्वारा इसपर रोक लगा दिया गया- रोक जो अंततः 60 और 40 का उसको जो उनके मन में आंकाक्षा थी उसको ध्वस्त और चूरचूर कर दिया है। हम चाहते हैं कि इस अनुपूरक बजट में जो भी आया है इस व्यवस्था को कायम करते हुए केन्द्र

सरकार जो पुरानी क्षति है उसको भी पूरा करे। इसमें दोहरी बात हुई इस रूप में कि 2015-16 में जानबूझकर पी0एम0जी0एस0वाइ0 के साथ राज्यों के साथ समान नीति को बदल दिया गया है। पूर्व में पी0एम0जी0एस0वाइ0 योजना में भारत सरकार की भांति राशि उपलब्ध करायी जाती थी जिसे मार्च, 2015 में बदलकर 60/40 का अनुपात कर दिया गया। यह अनुपात पूर्व से स्वीकृत योजना पर भी लागू कर दिया गया है जो सर्वथा अनुचित एवं राज्य विरोधी है। जब पिछले दिन स्वीकृत हुआ था योजना तो वैसी योजना का जो पुराना पद्धति था राज्य और केन्द्रांश उस आधार पर देना चाहिए । लगता है कि केन्द्र सरकार सौतेलापन के साथ साथ विकास विरोधी का भी प्रमाण दे रही है। इसलिए उक्त बदली हुई नीति पर पुनर्विचार करते हुए- माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13.12.15 को पत्र के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था कि पुनरीक्षित व्यवस्था से राज्य को मुक्त रखते हुए पूर्व की भांति जो राज्य और केन्द्र का अंश था उसको उपलब्ध कराने की कृपा किया जाय। इसलिए हम चाहेंगे कि बिहार का यदि विकास चाहते हैं तो जो पूर्व की जो स्वीकृत राशि है वह केन्द्र को देना चाहिए। इस रूप में देना चाहिए कि बिहार आजतक देश का मॉडल रहा है। इस रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कदम दर कदम विकास को बढ़ाकर बड़े सड़कों से लेकर, छोटे नाली और नाला तक और छोटे गांव की गलियों तक को बनाना चाहते हैं, यह बड़ी बात है। ठीक बात है कि बी0जे0पी0 का मुख्य मुद्दा रहा है कि सीटी बनाना, बुलेट ट्रेन चलाना और सुंदर सुंदर देश और दुनिया में प्रचार करना, लेकिन यह बड़ी बात है कि देश उन्नत तब होगा जब गांव का विकास होगा। भारत गांवों का देश है 60-70 परसेंट लोग गांवों में रहते हैं तो हम चाहेंगे कि जो पुरानी पद्धति थी केन्द्र और राज्य की उसको लागू करते हुए केन्द्र सरकार को इसपर विचार करना चाहिए। अभी तो कुछ बात हुई- ठीक बात है कि हमलोगों को बोलने में कुछ त्रुटि आ जाती है।

सभापति (मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य लक्ष्मेश्वर बाबू, क्या सुंदर आपके विचार हैं, बसंत का समा बंध गया, आ हा, हा, हा और बोलिये।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : जी, हम चाहेंगे कि खासकर बिहार के हित में- कल हमारे वित्त मंत्री जी चर्चा किये थे कि दक्षिण के राज्यों में स्टेट के सवाल पर दिल्ली में एक होते हैं। फिर यहां क्या हो जाता है कि चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों सारे लोग बिहारी हैं यहां। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो इस बात पर गौरव होना चाहिए कि देश और दुनिया में बिहार को गौरव प्राप्त हुआ है। जैसे लगता था कि वैशाली गणराज्य के बारे में दुनिया जानती थी, नालन्दा विश्वविद्यालय के रूप में दुनिया जानती थी उसी रूप में नीतीश कुमार के रूप में एक संस्था के रूप में जानती है। मित्रों, विकास के बारे में जानना चाहिए, हमको बड़ा कष्ट होता है खासकर जो हमारे विरोधी दल के नेता हैं-हम भी अत्यंत पिछड़ा

वर्ग से आते हैं। हम बताना चाहते हैं, हम वैसे समाज से आते हैं जो आजादी के बाद हम पहले व्यक्ति आये हैं इस विधान सभा सदन में, यह नीतीश कुमार की देन है। मित्रों, मुझे कभी भरोसा नहीं था, मैं ईश्वर से या मंदिर में भी नहीं मांगा था कि मुझको विधान सभा जाने के लिए कोई रास्ता मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने हमको बुलाकर बनाया..... क्रमशः।

टर्न–21/अशोक/ 03.03.2016

श्री लक्ष्मेश्वर राय : क्रमशः कहने का माने यह है कि विकास की प्रक्रिया अखबार और मिडिया में छपवाने से नहीं होगा, गढ़ने से ही होगा । नीतीश कुमार जी दलितों को गढ़ रहे हैं, आज हमारे लोग छोट–छोटी बतों को लेकर सदन के वेल में आ जाते हैं, हमारे जैसे लोग क्या सीखेंगे ? हमारे मन में आकांक्षा है, प्रेम बाबू से हम चाहते हैं, हमारे अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से आते हैं इनको बडी़ बातें करनी चाहिए, देश में जो पिछड़ा का रिजर्वेशन है उसको लागू करना चाहिए, केन्द्रीय सेवा में रिजर्वेशन को लागू करना चाहिए । भारत रत्न मिलना चाहिए स्व. कर्पूरी ठाकुर जी को जो देश में अत्यन्त पिछड़ को एक दिशा दिया, कमजोर वर्ग के हित में सवाल उठाया । लेकिन क्या हो रहा है? हंगामा –हम सभी से अपील करना चाहते हैं, यह सवाल भी है, ठीक है पक्ष–विपक्ष रहेगा लेकिन, आखिर क्या हो गया कि छोटी छोटी बात को लेकर हम वेल में जाते हैं हंगामा के लिए– क्या अखबार से बिहार बदलेगा ? क्या अखबार और मिडिया से बदलेगा ? नहीं बदलेगा ।आप याद कीजिए जब सारा देश के लोग, पूरा सत्ता से लेकर व्यापारी तक लगे थे नीतीश कुमार जी के विरोध में, महागठबन्धन के विरोध में । तब सबसे आगे होकर सरकार बनी बिहार में । फिर अभी हाय–हाय क्यों कर रहे हैं ? आपको बिहार के विाकस के बारे में चिन्ता करिये, आने वाला समय में, यह बिहार की जो स्थिति है वह स्थिति बदले । हम यहां अपील करते हैं सदन से, विधान सभा के सभी सदस्यों से कि हम आपसे सीखने आये हैं, आप नई दिशा दीजए । यह जो बजट है यह गली तक जाता है, हमको बिहार वाले को सोंचना चाहिए हमारे लोग बरसात में गली में नहीं जा सकते, हमारे नीतीश जी की दृष्टि दलित तक गया हैं । यह जो बुलेट ट्रेन है या जो सिटी

सेन्टर है यह बिहार में नहीं चलेगा । इसलिए नहीं चलेगा, इसका प्रमाण है, इसलिए कि जो बजट आया है उसमें बिहर में एक भी सिटी सेन्टर नहीं है, आपका नजरिया साफ है । अब छोटी छोटी बात में अी.वी. औरमिडिया में बना रहना चाहते हैं, इससे विकास नहीं होगा, जनता आपको नकार देगी, पिछले बार आपको नकार दिया है आने वाले दिनों में आपकी स्थिति और खराब हो जायेगी चूकि बिहार में शिक्षा की स्थिति बदली है ।

सभापति :(श्री मोहम्मद इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, श्री लक्ष्मेश्वर राय जी , कृपया शांति । अगर मिडिया और टी.वी. में नहीं आयेगा तो यह संस्था भी मायूस हो जायेगी ।, उसमें भी आना जरूरी है ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : इतना ही अपनी बात कह कर यह जो अनुपूरक बजट है , हम साथियों से चाहेंगे, माननीय सदस्यों से चाहेंगे कि सर्वसम्मति से यह जो विभागीय प्रस्ताव आया है इसको पास करना चाहिए ।

सभापति (श्री मोहम्मद इलियास हुसैन) : सभापति :(श्री इलियास हुसैन) : शुक्रिया, शुक्रिया । बड़े अच्छे आपके विचार, आपने अपने भाषण के माध्यम से भारत की आत्मा को आप गांव में ले गये सदन को, इसे लिए शुक्रिया । अब भजपा, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, छः मिनट आपका बचा है अरूण बाबू के बाद ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : सभापति महोदय, मैं ग्रामीणों के आवागमन से जुड़े ग्रामीण कार्य विभाग की अनुशंसा मांग पर सदन में प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करने हेतु आपके साथ साथ अपने माननीय नेता के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ । सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2015-16 में 6821करोड़ के लगभग जो बजट दिया गया, वह खर्च भी नहीं हुआ तो अनुपूरक बजट लाने का औचित्य क्या है । सभापति महोदय, इसके पहले भी द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था, 31 मार्च के अन्दर खर्च करना है और 31 मार्च के अन्दर खर्च नहीं करने पर यह वापस हो जायेगा । हम आपके माध्यम से जानना चाहते है कि यह कांसिल में जायेगा, राज्यपाल महोदय के यहां जायेगा आज तीन तारीख हो गया- तो इसका औचित्य क्या है माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे । महोदय, अभी हमारे कई नये माननीय सदस्य आये हैं, हम उनक अभिनन्दन करते हैं, स्वागत करते हैं और कई पुराने मित्र भी बैठे हैं । लाख से ऊपर की संख्या के लोग हर क्षेत्र में आशा भरी निगाहों से हमलोगों को देख रहा है और वह

जानना चाहता है कि जो हमारे विकास के डाक्टर सदन के अन्दर गये हैं मेरे विकास के लिए, कौन सा गुण सीख कर आते हैं, क्या विकास क लिए हमारी व्यवस्था बना करके आते हैं । बड़ी गंभीरता से हमारे नये सदस्य बोल रहे हैं, हम भी आये थे, हमारे दिल के अन्दर में एक अलग छवि बनी हुई थी, मैं कहना चाहूंगा अपने सदस्यों को

सभापति (श्री मोहम्मद इलियास हुसैन): किसके बारे में छवि बनी हुई थी ?

बश्री विजय कुमार सिन्हा : ये लोकतंत्र के संदर्भ में...

सभापति (श्री मोहम्मद इलियास हुसैन): पूरा करना चाहिए वाक्य को ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : इस लोकतंत्र में, अभी जो बतला रहे थे, संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष सरकार के ही अंग माने जाते हैं । हमारे महान संत कबीर दास जी की बाणी है

" निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाये,
बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाय ।"

आज विपक्ष आपका अंग है और आपको आइना दिखलाता है कि विकास के लिए क्या खामी है, आप उसको दूर करें । आज मैं बतलाना चाहता हूॅ कि आज जो 23 करोड़ का जो बजट है ।(व्यवधान) सभापति महोदय, बड़ा विचित्र स्थिति है, सभापति महोदय, आज ग्रामीण कार्य विभाग के अन्दर जो खामी है, जो कमी है, विधायकों की अनुशंसा मरम्मति एवं एम.आर. के लिए लिया जाता था, वह बंद हो गया । माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करेंगें कि 50 लाख से ऊपर तमाम विधायकों से लिया जाता था अपने गांव के उस दर्द को लोग अपनी अनुशंसा के माध्यम से प्राथमिकता तय किया करते थे । इस पर विशेष तौरपर हम आग्रह करेंगे कि वे ध्यान दें, आज बजट के अन्दर इन्होंने जो लिया है, हमारे क्षेत्र के लक्खीसराय के अन्दर दियारा क्षेत्र है, मालपुर पिपरीया रोड वर्षो से लगता है आजादी से मरहुम दूर बैठा हुआ है, कब उसका ख्वाब पूरा होगा, कब उस सड़क को लिया जायेगा, आज उसी तरह से हलसी प्रखण्ड, हमारे लक्खीसराय के हलसी प्रखण्ड के गौरा का, रामगढ़ प्रखण्ड के फुलैया का और कई जर्जर सड़क है, पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्दर भी, आपके विभाग के अन्दर भी देख-रेख होती है । आज इनके माध्यम से एम.एम.जी.एस.वाई. में प्राथमिकता जो विधायक के द्वारा तय होता है, आज न उसका शिलान्प्यास और न उद्घाटन ही विधायक के द्वारा किया जाता है, यहां तक उसकी जानकारी तक नहीं दी

जाती है । संवेदक के द्वारा कार्य हेतु संविदा निकलता है । न उसका गुणवत्तापूर्ण कार्य होता है और न समयसीमा के अन्दर कार्य होता है । सभापति महोदय, हद तो तब हो गई कि संवेदक जो शपथपत्र देता है, उस शपथपत्र को मैं चुनौती देता हूँ कि किसी के पास न इंजीनियर है, न उपकरण है, सारा झूठा शपथपत्र देता है । आप उसकी जांच करके चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण कार्य हो ? उसकी जांच करावे । इसकी जांच कर उस संवेदक को प्राथमिकता दें जो सही है, उसका लिस्ट जारी करें और जो गलत शपथपत्र दिया है उस पर आप कार्रवाई करें तब आप सुशासन का पीठ थपथपायें ।

क्या सच यह नहीं है कि रामचरित मानस में तुलसीदास कह गये हैं

" सचिव, वैद्य, गुरू तीन जो, प्रिय बोले ही भले आप,
राज धर्म तंत्र तीन जो हो गई वेगेहि नाश"

जो उसके पक्ष में सच्चाई को नकारेगा, सिर्फ गुण-गान और मक्खन लगाने की बात करेंगे उस राज्य का नाश हो जायेगा । उस व्यवस्था का नाश हो जायेग- यह व्यवस्था बदलनी होगी और इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमलोगों ने आग्रह किया था, हमने कहा था सभापति महोदय कि आप इमानदारी से सच को स्वीकार करिए, हम आपके निन्दक नियरे हैं, मेरा भी आपकी तरह, उद्येश्य है गरीब जनता के प्रति समर्पित भाव, हमे भी जनता जीता कर भेजी है, हमारा भी समर्पण उसी के साथ है । क्या यह सच नहीं है, यह विडंमना है

" जिस बाग का दुश्मन माली हो,
जिस बाग का दुश्मन माली हो,
उस हरे चमन का क्या होगा,
जिस घर में घोर अंधेरा हो,
उस घर के दुल्हन का क्या होगा ।।

महोदय, यह स्थिति बिहार के अन्दर है

सभापति(श्री मोहम्मद इलियास हुसैन) :माननीय सदस्य श्री सिन्हा साहब, किसी चमन का माली दुश्मन हो ही नहीं सकता, अगर दुश्मन हो गया तो वह माली नहीं है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : आज लहू बह रहा है, सभापति महोदय, आज सैकड़ों में लाशें गिर चुकी है दो-तीन महीना के अन्दर में, हत्या, अपरहण, लूट, बलात्कार हो

गया- उस घर को कौन लूट रहा है ? किसकी जिम्मेवारी है उसकी रक्षा करने का ? कौन माली है यहां का ? उस माली की जिम्मेवारी, रिसपौंसब्लिटी तय होनी चाहिए । क्या यह व्यवस्था, उनको लेना होगा, इस जिम्मेवारी को । कहने के लिए तो सभापति महोदय बहुत सारी बातें हैं, समय कम दिया गया है, आगे मौका मिलेगा । मैं अपने माननीय सदस्यों को कहूंगा इस सदन के अन्दर जब भी बैठे तो यह सोच कर बैठे कि पक्ष और विपक्ष नहीं हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं.. क्रमशः

टर्न-22:03-03-2016-ज्योति

क्रमशः

श्री विजय कुमार सिन्हा : नहीं, हमलोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं और लोकतंत्र के प्रहरी के रुप में ईमानदारी से पवित्रता से सच्चाई को उजागर करेंगें और हमको मिलेगा इंसाफ लेकिन हमारे मंत्री जी दुल्हन की तरह सज धज कर बैठते हैं उनसे उम्मीद है कि जो ये माली हैं वे खूबसूरती से` सजायेंगे लेकिन जिन्हें वे चमन को लूटने का` अवसर` दे रहे हैं` वह लोकतंत्र में एक अपराध है ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य , राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जनाब ललन पासवान- दो मिनट कृपया ध्यान देंगे , समय सीमा आपके सामने तय है ।

श्री ललन पासवान : शुरु करने से पहले ही कड़ा निर्देश। कर देते हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : मैं लिखा हुआ बोल रहा हूँ अपना कोई आदेश नहीं है ।

श्री ललन पासवान : आधा मिनट तो ऐसे ही निर्देश पर मार देते हैं । दलित की बात है नहीं बोलने दीजियेगा तो बरियारी बैठ जायेंगे , कहिये तो बैठ जांय ?

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : बोलिये न । इधर देखिये ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, आप ही की तरफ देख रहे हैं , कहाँ इधर देख रहे हैं?

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : समय बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, बिहार में 45 हजार गांव हैं और 45 हजार गांव में आज भी आजादी के 67 साल गुजर गए इधर के लोग हों या उधर के लोग हों

सब लोगों को मौका मिला लेकिन आजतक 45 हजार गांव के लोगों को सड़क नहीं मिली । 22-23 हजार गांव आज भी सड़कों से अछूता है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य सही बात नहीं बोल रहे हैं , सर्वे करा लीजियेगा तो पता चल जायेगा । हम जहॉ से आते हैं, कई सड़के आज भी जो बन रही थीं आज भी अधूरी हैं । सिरसिया से भगवान पुर पथ 26 कि0मी0 7 वर्षो से टेण्डर होने के बाद लंबित है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : अपने शरीर का पोस्चर ठीक करिये आसन की तरफ और इधर ही देखिये ।

श्री ललन पासवान : अच्छा, सभापति महोदय, आप ही की तरफ । सभापति महोदय, बगल में एक दूसरी सड़क है जो 7 वर्षो से लंबित है । रोहतास जिला में चेनारी प्रखण्ड के बसनहरा, नेऊरी ,सदोखर , तुर्की, चंदनपुरा भाया चेनारी 17 कि0मी0, 2006-07 में टेण्डर हुआ था, एन0पी0सी0सी0 करा रहा था ,ब्लैक लिस्टेड है ,आजतक उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ । भारत सरकार कहती है बिहार सरकार, बिहार सरकार कहती है भारत सरकार यह जो भारत सरकार और बिहार सरकार का जो दौर है कब खतम होगा ? पंडुका पुल झारखण्ड और बिहार को जोड़ने वाला आजादी के बाद से आजतक लंबित है । हमलोगों ने अखबार में देखा , प्रधानमंत्री जी के पैकेज में है , मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की कि पण्डुका पुल बनेगा , नोहट्टा के बगल में पण्डुका पुल 2 हजार करोड़ का तो उसका अभीतक शिलान्यास नहीं हुआ । दो राज्यों को जोड़ने वाली सड़क है । हमारे यहॉ कई पुल-पुलिया बची हुई हैं , हम मानते हैं कि बिहार में आज भी हजारों पुल पुलिया हैं बगल में देवडीही से जाने का , सोन उच्च स्तरीय नहर के बगल में एक पुल है मड़ई नदी जो बगल में खडिहा के तरफ सड़क जाती है वहॉ आज पुल है जिसके चलते आज लोग उस पहाड़ की तरफ नहीं जा पाते हैं । भुअरा बगल में सिया ड्रेनेज टू सी भुअरा से लेकर सी0आर0पी0एफ0 से लेकर इसतरह से दर्जनों नहीं सैकड़ों गांव , पहाड़ पर 70 गांव हैं , इन्सान वहॉ पैदलपशु लेकर जाता है। रोहतासगढ़ पंचायत पीपरडीह पंचायत ,बगल में अधौरा के 109 गांव पूरा पहाड़ पर कहीं सड़क नहीं है । पशु इन्सान पथरीली पहाड़ पर पैदल चढ़कर उतरता है एक जगह भी तनिक सड़क नहीं है । ग्रामीण विकास का बजट पेश हो रहा है आज भी मैं कह रहा हूँ इसलिए कि बिहार के 45 हजार गांवों में फिफ्टी प्रतिश।त गांवों में , 22 से 23 हजार गांव हैं जहॉ सड़क नहीं है । चाहे उधर वाले हों या इधर

वाले हों ईमानदारी से कलेजा पर हाथ रखकर बतावें तो मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी और बगल में बगल में श्रवण कुमार जी है इनके भी इलाकों में सब गांव सड़क से नहीं जुड़े हैं । यह सच बात कहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : यह आप कैसे जानते हैं ? श्रवण। जी का गांव जाना हुआ है ?

श्री ललन पासवान : घुमा हुआ हूँ , नीतीश जी के` प्रचार में कई बार घूम चुका हूँ । आपको बताने की जरुरत नहीं है । इसलिए मेरे यहॉ और सड़क है , एक मिनट सर । सभापति महोदय, एक सड़क है आलम पुर से प्रगट नाथ गुप्ता धााम , 20 कि0मी0 सड़क और दूसरी सड़क है आलमपुर मौलीपुर से पचौराघाट औरईयॉ होते हुए फुलवरिया गुप्ता धाम वह भी 20 कि0मी0 सड़क ,एक सड़क है सासाराम से ताराचण्डी –गुप्ता धाम ये पहाड़ो पर लाखों श्रद्धालु जाते हैं । सड़कें नहीं बनी हैं । चाहे वन विभाग का पर्यावरण का मामला हो ,चाहे ग्रामीण विकास विभाग की निष्क्रियता का मामला हो चाहे सरकार के कमजोर संकल्प का मामला हो लेकिन पहाड़ पर जाने के लिए सड़क नहीं है । बगल में दुर्गावती जलाशय परियोजना से एक सड़क जाती है उसमें ट्रैक्टर के पलटने से अभी 11 लोग मर गए । प्रति वर्ष गुप्ता धाम जाने में चार तरफ से सड़क है जैसे मैंने कहा कि करमचट बांध से होकर दुर्गावती से गुप्ता धाम जाने में सड़क नहीं बनी है , हम सदन के माध्यम से मांग करते हैं कि गुप्ता धाम जाने के लिए चारों तरफ से माननीय श्रवण कुमार जी, संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं वह कम से कम कृपा करके इन सड़को को बनाईये ललन पासवान के लिए बल्कि लाखो लाख जो श्रद्धालु इन पहाड़ो पर जाते है नदियों में बह जाते हैं ं उनको लाभ मिले।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): आपका 5 मिनट हो गया अब सी0पी0आई0एम0एल के श्री सत्यदेव राम जी आरम्भ करें ।

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने तो अच्छा किया है इन्होंने इनके साथ समझौता किया और जिन सवालों को माननीय सदस्य उठा रहे हैं उसके लिए भारत सरकार से परमीशन लेना पड़ेगा । जिन इलाकों में ये सड़क बनाना चाहते हैं वह वन क्षेत्र में वगैर भारत सरकार के इजाजत के एक गांव भी सड़क से नहीं जुट सकता है । भारत सरकार से एन0ओ0सी0 लेकर आयें बिहार सरकार तैयार है।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : आपका कहना सही है , सब वर्जित है ।

श्री सत्यदेव राम : सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का समय दिया है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ । महोदय, हमारी स्थिति विचित्र है । महोदय, विचित्र इसलिए है

कि दो मिनट मे मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं` यह खुद मुझे समझ में नहीं आती है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : समझ में ले लीजिये और दो चार श।ब्द बढ़ जोयगा , बोलिये । घबराईये नहीं बोलिये ।

श्री सत्यदेव राम : सभापति महोदय, मैं न बजट के पक्ष में बोलूंगा और न कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलूंगा । मैं बिहार के गांवों की जनता के लिए बात रखना चाहता हूँ । मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात कह रहा हूँ कि अगर जो सवाल मैं रखूंगा वह बिहार के गांवों के गरीबों के ही सवाल होंगे । मैं इस आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात रखने जा रहा हूँ महोदय, कि सड़क एक समय सीमा के अंदर बन जाती हैं तो अगला बजट सत्र होगा उस बजट सत्र में इस वादा के साथ कह रहा हूँ कि निश्चित रुप से सरकार के बजट का समर्थन करुंगा) मैं अभी जो प्रस्ताव करने जा रहा हूं कि छः महीना के अंदर ये सड़के बन जाती हैं तो इनके अगले प्रस्ताव का मैं समर्थन करुंगा ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : अभी से ही समर्थन शुरु कर दीजिये ।

श्री सत्यदेव राम : जी, बिना बनले महोदय ? आपका आदेश हो और छः महीना में सरकार उसको बना देती है तो अगले बजट सत्र में मैं उसका समर्थन कर दूंगा । टियर के अंदर एक सड़क है महोदय भयासांढ़ ये सड़कें जब बरसात आती है तब हमलोग ब्लौक पर धरना देते हैं , प्रदर्शन करते हैं और उससे भी काम नहीं चलता है तो ग्रामीण लोगों से चंदा मांग कर उसकी भराई करते हैं तब लोग किसी तरह से आ जा सकते हैं । उस सड़क की यह` हालत है ं। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया है । मैं जिस बिहार विध।ान सभा क्षेत्र से आता हूँ आंदर प्रखण्ड में जो सड़क है , जर्जर हालत में है इमरजेंसी में भी जाना मुश्किल हो जाता है ।

क्रमशः

श्री सत्यदेव रामः क्रमशः इसलिए मैं आशा करता हूं कि ग्रामीण कार्य विभाग इस सड़क की नोटिस लेगा और निश्चित रूप से इसको कराने का काम करेंगे तो मैंने वादा किया है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं महोदय कि आज भी गांव के बहुत सारे गांव सड़को से तो जुड़े हैं लेकिन आज बहुत सारे गांव सड़कों से नहीं जुड़े हैं । मेरे पंचायत कृष्णपाली के एक टोला देवरिया है महोदय इस टोला देवरिया गांव में जहां ढ़ाई सौ सिर्फ 25 महादलित परिवार हैं उस ढ़ाई सौ परिवार वाले टोले को किसी तरफ से कहीं से सड़क नहीं जोड़ती है । हमने बहुत कोशिश किया महोदय लेकिन उसमें न तो कोई फंड लग पा रहा है, न मुखिया का फ्रंड लग पा रहा है, न विधायक फंड लग पा रहा है । इसलिए कि वह सारी जमीन सामंतों की है और दलितों को देना नहीं चाहते । इसलिए हम सरकार से यह मांग करते हैं कि सरकार उन दलित लोगों को मुख्यपथ से जोड़ने के लिए जमीन का अधिग्रहण करे खरीद करे और दलितों के लिए सड़क को 6 महीने के अंदर बनाये । तीसरी जो बात मैं यह कहना चाहता हूं महोदय कि सड़के गांव में चली जाती हैं लेकिन सच्चाई यही है कि गांव के जो दलित और गरीब है, अति पिछड़े हैं वे लोग सड़कों से वंचित रहते हैं । और इस तरह से अगर हम सर्वे करायेंगे हमारे सर्वे में था कि कम से कम आधे गांव के दलित मुख्य पथ से वंचित है उन्हें आज भी पगडंडी का सहारा लेना पड़ता है और बीमार हालत में खाट पर बीमार को लेकर जाना पड़ता है । मैं इसलिए यह बात नहीं कर रहा हूं । मैं आरोप प्रत्यारोप की कोई बात नहीं कर रहा हूं । मैंने पहले भी कहा बिहार की जनता और गांव के गरीबों की बात रखूंगा ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): समय सीमा है ।

श्री सत्यदेव रामः सभापति महोदय, इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से भी यही उम्मीद रखूंगा कि 6 महीनों में हमारा जो प्रस्ताव है, मांग है निश्चित रूप से पूरा होंगे तो अगले बजट का हम वादा पूरा करेंगे ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सत्यदेव बाबू आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सत्यदेव रामः मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत । आप कहां थे मैंने तीन तीन बार आपका पुकारा ।

श्री कुमार सर्वजीतः महोदय, मैं तीन बार खड़ा हुआ था ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): 12 मिनट आपका है ।

श्री कुमार सर्वजीत: माननीय सभापति महोदय, आपने जो मुझे बोलने समय दिया है मैं आपका आभारी हूं। मैं ग्रामीण कार्य विभाग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, यह जो विभाग है वह पूर्ण रूप से गांव के गरीबों के हृदय से जुड़ा हुआ यह विभाग है । पर जो व्यक्ति, विपक्ष के लोग गरीब के, गरीब जनता के हृदय की बात को नहीं समझते हों वैसे ही व्यक्ति कटौती का प्रस्ताव लाने की हिम्मत जुटा पाते हैं। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना किसके लिए बनता है ? गरीब का बेटा, दलित का बेटा, अकलियत का बेटा, पिछड़ा का बेटा वही व्यक्ति उस सड़क पर चलता है । प्रधानमंत्री सड़क योजना जहां से जिस गांव के लिए दिया जाता है पिछड़े हुए इलाके के लिए दिया जाता है तो उस सड़क पर विपक्ष के कोई भी नेता उस पर चलते हैं क्या? विपक्ष के सभी नेता तो बी0एम0डब्लू0 पर चलते हैं । पूंजीपतियों की यह पार्टी है । गरीबों के लिए यह सड़क बनता है गरीब का बेटा उस पर चलता है । और बड़े पैमाने पर सभापति महोदय पूरे बिहार में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क जो अधूरा है उसमें रोज हजारों व्यक्ति हजारो गरीब का बेटा मोटर साइकिल से चलता है और उसकी मृत्यु हो रही है । मैं इस सदन के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा ? भारत सरकार ने पैसा रोका है 60-40 रेशियो का भारत सरकार ने जो प्रावधान लाया है कि हम 60 में 40 परसेंट पैसा देंगे। गरीब का बेटा सड़क पर चलता है, दलित का बेटा सड़क पर चलता है । सभापति महोदय, इसमें मुझे साजिश की बू आती है । क्योंकि जब प्रधान मंत्री का विगत चुनाव में क्षेत्र में रैली होता था तो गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा-बेटी साइकिल से सभा सुनने जाती थी और सभा सुनकर जब आती थी तो घर में वह यही चर्चा करती थी कि यह गरीब और दलित का देखने वाला पार्टी नहीं है इसलिए अपना बहुमूल्य मत दिया हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश जी को । शायद इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब गरीब के बेटा को सड़क पर नहीं चलने देंगे और मैं इसमें कटौती करता हूं और 40 प्रतिशत ही देंगे 60 प्रतिशत राज्य को देना पड़ेगा और मैं इतना ही दूंगा। सभापति महोदय, अभी हमने सुना था जो प्रधान मंत्री सड़क योजना बनती है क्या विपक्ष के नेता उस सड़क पर चलते हैं ? क्या विपक्ष के नेता उस सड़क को कभी युज करते हैं । वे शहर से चुनाव जीतते हैं ? और जो व्यक्ति शहर से चुनाव जीतता है क्या वह गरीब गुरबा का, क्या वह दलित के बेटा के

भावना को समझ सकता है ? क्या दलित का बेटा किस परेशानी में रहता है क्या विपक्ष के नेता यह समझ सकते हैं ? मैं आग्रह करूंगा अगली बार अगर विधान सभा चुनाव हो तो शहर को छोड़कर और गरीब जहां बसते हैं, गरीब का बेटा जहां बसता है आप वहां जाकर चुनाव लड़कर आयें तब शायद आपको एहसास होगा कि गरीब का बेटा, दलित का बेटा गांव में किस हालत में रहता है। सभापति महोदय, अभी मैं सुन रहा था चर्चा में कहा गया कि गांव में नली और गली बन रहा है मैंने इतिहास देखा है सभापति महोदय, विपक्ष के साथियों को ऐसा लगता है कि जब गरीब का बेटा गांव से अपने पैर में आधा किलो एक किलो मिट्टी लगाकर के और उनके दरवाजे पर जाता है किसी काम के लिए तो उनको बड़ी खुशी होती है कि एक दलित का बेटा अपने पैरों में मट्टी लगाकर मेरे शरण में आया है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है । शायद इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है जो माननीय मुख्यमत्री हमारे निश्चय किये हैं कि हम गांव में नली और गली बनायेंगे शायद इसी का वो विरोध करना चाहते हैं और शायद इसीलिए उस योजना का वह विरोध करते हैं और इन्होंने कटौती प्रस्ताव लाया है । सभापति महोदय, हमारी सरकार ने निर्णय लिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे गठबंधन ने निर्णय लिया कि गरीब का बेटा अब नल का पानी पीयेगा । क्यों विरोध कर रहे हैं चापाकल नहीं है । मैंने अपने क्षेत्र में देखा है मैं जहां से चुनाव जीतकर आया हूं सभापति महोदय वहां गरीब का टोटल चापाकल वहां के किसी व्यक्ति ने बेच डाला । क्या गरीब का बेटा पैसा से पानी खरीद कर पीयेगा ? हमारी सरकार ने निश्चय किया अब गरीब का बेटा, दलित का बेटा नल का पानी पीयेगा । ये विपक्ष के लोग जो बिसलरी पीते हैं सभापति महोदय । इनको नल के पानी से क्या लेना देना है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, क्या आपने कभी इसकी सूचना संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को या सरकार को दिया है कि सारे चापाकल बेच दिया गया है ?

श्री कुमार सर्वजीत: दिया गया भी है सभापति महोदय । और गरीब का बेटा पानी के बिना पांच साल तरस कर मरा है । मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से कि आखिर कौन सी वजह है क्या प्रधानमंत्री सड़क योजना में पैसा नहीं देना चाहते हैं ? हमारी सरकार ने निश्चय किया कि गरीब के बेटे के दरवाजे तक हम सड़क बनाना चाहते हैं इसमें क्या परेशानी है इनको ? गरीब

का बेटा आज देश के प्रधानमंत्री पूंजीपतियों को सड़क पर चलने के लिए उनके ऑफिस से उनके दरवाजे तक बी0एम0डब्ल0 कार कैसे जायेगा ऐसी योजना है आपके पास । आप शहर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं । कौन रहता है शहर में । कोई दलित का बेटा शहर में रहता है क्या ?

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): शांति । कृपया शांति । माननीय सदस्य स्पष्ट नहीं हो रहा ऐसा सड़क कौन लोग बनाना चाहते हैं ?

श्री कुमार सर्वजीत: महोदय, हमारे भारत सरकार की योजना आयी कि हम शहर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): कौन बनाना चाहते हैं ?

श्री कुमार सर्वजीत: भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री कभी उन्होंने ऐसा कहा कि मैं किसी गांव के गरीब बेटा के गांव को मैं स्मार्ट गांव बनाना चाहता हूं ।

क्रमश:

श्री कुमार सर्वजीत : क्रमशः सभापति महोदय, पूरे हिन्दुस्तान के सभी सांसदों को एक-एक गांव गोद लेने का संकल्प था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और मैं उस संकल्प को आपके सामने एक्जाम्पुल के रूप में रखना चाहता हूं । विपक्ष के लोगों से जानना चाहता हूं कि अगर इसमें सच्चाई है तो वह यह प्रस्तुत करें कि आपके दल के कितने सांसदों ने गांव को सुखी-सम्पन्न बनाया है इस योजना के तहत, वह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं । सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के करनी और कथनी में बहुत अंतर है । सांसद किसको गोद लेते हैं ? जहां दलित का बेटा, गरीब का बेटा जहां रहते हैं, इस देश के बड़े-बड़े, गरीब के बड़े-बड़े, बिहार के बड़े दलित नेता कहलाने वाले लोग उनके दल के गठबंधन में शामिल हैं । हमलोग ऐसे दलित के बेटा को शर्म से सर झुकता है जब गरीब का बेटा, दलित का बेटा का सड़क बनाने का पैसा की जब बात होती है तो दलित का बड़ा-बड़ा नेता अपने माननीय प्रधानमंत्री का चेहरा देखता है और नीचे झुका करके हाउस से बाहर चले जाते हैं । आने वाला 2019 में यह दलित का बेटा, पूरे बिहार का गरीब-गुरूवा का बेटा इसका जवाब देने के लिए खड़ा है सभापति महोदय ।

अंत में मैं ग्रामीण विकास विभाग, ऐसे विभाग का मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं क्योंकि यह गरीब-गुरूवा, दलित सभी के हृदय से जुड़ा हुआ यह विभाग है और मैं यह भी मांग करता हूं कि हमारा जो बोधगया विधान सभा क्षेत्र है सभापति महोदय, वहां भगवान बुद्ध के गुरू का स्थान है वहां पर, वहां पर सड़क नहीं है, प्रधानमंत्री सड़क योजना अधूरा है और जो विदेशी पर्यटक आते हैं तो कहते हैं कि नरेन्द्र मोदी का तो हमने बड़ा भाषण सुना और यह प्रधानमंत्री सड़क योजना भी अधूरा है, यह क्या संदेश लेकर लोग जाना चाहते हैं ? कई ऐसे सड़क हैं । मैं सभापति महोदय के माध्यम से मांग करता हूं जो भी सड़क हमारे विधान सभा में प्रधानमंत्री सड़क योजना से अधूरा है, मैं मंत्रीजी से मांग करूंगा आपके माध्यम से कि उसमें विशेष ध्यान हो, पर्यटक स्थल है । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री प्रेम कुमार : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है प्रधानमंत्री सड़क योजना के संबंध में । पूरे देश में और खासकर बिहार में सभी लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से चयन किया गया है तो गांव का काम हो रहा है और साथ ही बताना चाहता हं कि काम चल रहा है महोदय ...

(व्यवधान)

महोदय, ये बोधगया में रहते हैं । बोधगया गांव नहीं है । बोधगया शहर है महोदय ..

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): जो बाकी होगा, लिख देंगे । कृपया बैठिये । बैठिये । शांति। शांति ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री अमितव भूषण ।

श्रीमती अमिता भूषण : सभापति महोदय, वह अमितव भूषण नहीं, अमिता भूषण है ।

श्रीमती अमिता भूषण : सम्मानित सभापति महोदय, बिहार सरकार के माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2016-17 के ग्रामीण कार्य विभाग को आवंटित धनराशि और उसके क्रियान्वयन की रूपरेखा के संदर्भ में समर्थन स्वरूप आपके समक्ष उपस्थिति दर्ज कराने का आपका और सदन का आभार प्रकट करती हूं ।

महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि भारत के गांव का विकास हो और भारत के प्रत्येक गांव अपने आप में पूर्ण और सम्पूर्ण है । उनकी प्रसिद्ध उक्ति है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, जो आज आजादी के 69साल के बाद भी यह उक्ति अक्षरश: सत्य है । महोदय, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बनी भारत सरकार ने पूर्व में गांव की महत्ता को हमेशा स्वीकार किया है और इस दिशा में सतत प्रयासरत् भी रही है । इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया और उसे सुदृढ़ किया जिसे माननीय श्रीमती सोनिया गांधीजी और पूर्व प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह जी ने यू.पी.ए. गठबंधन की सरकार के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का जाल बिछाने का काम किया था । इसकी सफलता और आवश्यकता उनकी सोच को पुख्ता करता है । महोदय, इसी परम्परा के तहत हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमारजी ने बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए गांव के विकास पर विशेष ध्यान दिया और इसी कड़ी में उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ अपने सात निश्चय को प्रमुख स्थान दिया है । महोदय, महिला होने के नाते और इस सदन के सदस्य होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी के इस प्रयास और उनके निश्चय और सोच को तहेदिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जबकि मेरा मानना है कि नारी हमेशा देना ही जानती है, वह जननी है । दुर्गा के रूप में वह शक्ति देती है, लक्ष्मीरूपण वह धन देती है और सरस्वती के रूप में वह विद्या देती है । पर आज के आधुनिक युग में उसे सशक्तिकरण की जरूरत आन पड़ी है । आधी आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के नाते माननीय मुख्यमंत्रीजी ने ग्रामीण परिवेश की

महिलाओं को सशक्त करने और गांव-गांव के विकास के लिए हर घर कल, हर घर बल्ब, हर घर थाली यानी सड़क और हर घर शौचालय को अपना निश्चय बनाया जो आज के दिन इनका ही नहीं, मेरा भी नहीं, यह सभी माननीय सदस्यों का और सभी व्यक्तियों का एक दृढ़ निश्चय है । अभी भी मैं जब आपके सामने खड़ी हूं तो मेरा रोम-रोम पुलकित हो रहा है और आज वह दृश्य याद पड़ता है जब गांव की पगडंडियों से, सड़कों से जब हम गुजरते थे तो गलियों में, खास कर बच्चों में दोपहिया वाहन पर हवा में उनके लहराते दुपट्टे को देखा जो दुपट्टा उनकी डोलची में रखे हुए किताब के आवरण का भी काम कर रहे थे । स्वचालित दो पहियों पर सवार उन बच्चियों को वह पंख मिले जो उन्हें समाज में उन उचाइयों तक पहुँचाने में सफल हुए हैं जिसकी सिर्फ अनुभूति की जा सकती है जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन): माननीय सदस्या, मोतरमा, अब अपने क्षेत्र की समस्या पर आइए।

श्रीमती अमिता भूषण: बोलुंगी और कहीं-न-कहीं यह सारी सोच ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित है । ये बच्चियां अगर गांव में सड़कें नहीं बनेगी, गांव में पुल, पुलिया नहीं बनेगे तो बच्चों के सपने कहां जाएंगे ? कहीं-न-कहीं आज वो साइकिल से चल रही हैं तो गांव में सड़कें मिली हैं, हमारी सरकार ने बनाया है । इसी के कारण उनके सपने आज इतने उड़ान भर रहे हैं ।

माफी चाहती हूं महोदय । ग्रामीण कार्य विभाग के लिए बजट में धन का आबंटन एक प्रक्रिया है लेकिन इस प्रक्रिया को मूर्त्त रूप देने के लिए दृढ़ निश्चय, ठोस रूपरेखा, क्लोज मोनिटरिंग और सुपरवीजन की जरूरत है जो हमारे गठबंधन की सरकार में है । इस गठबंधन के सभी सदस्य और साथ में इस सदन के भी सभी सदस्य इसके प्रति संकल्पित थे क्योंकि ग्रामीण विकास में हम सबों का विकास समाहित है । जिस तरह से इस राज्य के हर जिले में चार से पांच घंटे में राजधानी आया-जाया जा सकता है, वह दिन दूर नहीं जब हम बिहार के हर टोले से हमारे भाई-बहन चार से पांच घंटे में राजधानी हमलोग आ सकेंगे । यह माननीय मुख्यमंत्री जी के ग्रामीण कार्य विभाग के लिए सोची-समझी रणनीति और सतत सहयोग से ही संभव हो पाएगा ।

अंत में मैं सदन के प्रति एवं सभी अपने खासकर अपने पार्टी के हमारे सचेतक जावेद जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि मुझे आप लोगों ने समय दिया और मैं आपलोगों के बीच अपनी बात रखी और मैं सरकार का

जो यह खासकर यह बजटीय प्रावधान है उनकी क्रियान्वयन की रूपरेखा का मैं पूर्णत: समर्थन करती हूं । धन्यवाद । जयहिंद ।

टर्न–25/राजेश/3.3.16

सभापति (मो0 इलियास हुसैन):– माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी । आप दो मिनट में अपनी बात को रखेंगे ।

श्री राजू तिवारी:– आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सीधे अपने विधान सभा क्षेत्र पर आता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन प्रखंड हैं एवं एक नोटिफाईड एरिया है । महोदय, अरेराज प्रखंड में 50 से 60 प्रतिशत घर और गॉव रोड से जुड गया है लेकिन हमारे विधान सभा में पहाड़पुर और संग्रामपुर । पहाड़पुर प्रखंड की जो 16 पंचायतें है, उसकी हालत बहुत ही दयनीय है, यहॉ पर आज भी सरकार में बैठे सिनियर लोग बोलते हैं कि पॉच साल में हमलोग पटना पॉच घंटे में चले आयेंगे लेकिन हमारे यहॉ बरसात के दिनों में ऐसा गॉव भी है, जहॉ अगर किसी की तबियत खराब हो, तो दो से ढ़ाई घंटा लग जाता है उसको प्रखंड के अस्पताल आने में, इसलिए महोदय लिस्ट तो बहुत लंबा है, लेकिन आप दो मिनट का टाईम दिये हैं,अगर आदेश हो तो मैं बोलूं.....

(व्यवधान)

सभापति (मो0 इलियास हुसैन):– आपको बुरा नहीं लगे, लंबी अवधि है, फिर मिलेंगे कभी ।

श्री राजू तिवारी:– जी–जी । लेकिन हम बता रहे हैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी को अवगत कराना भी चाहेंगे और हम लिखकर दे भी देते हैं।

सभापति (मो0 इलियास हुसैन):– आप दे दीजिये ।

श्री राजू तिवारी:– महोदय, हमारे यहॉ पहाड़पुर में विशेष रुप से ध्यान दे करके और संग्रामपुर में रोड बनाया जाय । एक चीज और आखिर में हम अपनी बात को समाप्त करते हुए बोलना चाहता हूँ कि अभी–अभी हमारे सिनियर माननीय सदस्य सर्वजीत जी के द्वारा पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच स्मार्ट सिटी में है,आज उनके माध्यम से पता चला है कि बीी0एम0डब्लू0 के लिए ही वे रोड बनवा रहे है। धन्यवाद ।

सभापति (मो0 इलियास हुसैन):– माननीय सदस्य श्री प्रहलाद यादव । आपको 5 मिनट में अपनी बात को रखना है, चूंकि बहुत ही टाईट प्रोग्राम है, 4.45 बजे अप0 से सरकार का जवाब होगा । आप ध्यान देंगे, पुराने सदस्य है ।

श्री प्रहलाद यादवः- महोदय, मैं ग्रामीण कार्य विभाग का जो मांग का बजट रखा गया है,उसके समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, समय बहुत कम है, ज्यादा तो बोलना नहीं चाहूंगा, केवल अपने क्षेत्र पर ही सीधे आऊंगा, तो उससे ज्यादा फायदा होगा। महोदय, मैं ग्रामीण कार्य विभाग के माननीय मंत्री जी से आगह करुंगा कि कुछ ऐसे हमारे क्षेत्र में सड़क है, जो बनाना बहुत ही जरुरी है। एक है अवगिल एन0एच0-80 से मानिकपुर, दूसरा है खाबा एन0एच0-80 से किरणपुर होते हुए पीढ़ी-अभयपुर स्टेशन, यह ग्रामीण सड़क है सर, एक है मिल्की एन0एच0-80 से वह सीधे चला जाता है पीढ़ी बाजार स्टेशन, तो माननीय मंत्री जी के पड़ोसी हमलोग हैं, और पड़ोसी के बगल का रोड है,उसके बाद एक रोड है लखीसराय विद्यापीठ से ले करके पिपरिया होते हुए आपका पठुआ गॉव, वह रोड जो है, वह ग्रामीण है, एक प्रखंड जो दियारा में है, उसको जोड़ता है, यह बहुत ही इम्पौरटेंट रोड है, दूसरा रोड एक चानन का गया है, किउल स्टेशन से धनबा गोपालपुर होते हुए कुंदर होते हुए जमुई जिला में मिला है, यह भी ग्रामीण सड़क है, यह भी बहुत ही जरुरी है और यह एक दूसरे जिले को जोड़ता है, इसके अलावे एक रोड लखीसराय जिला में है, वह है खुरियारी से ले करके बिजुलकी होते हुए हलसी प्रखंड को जोड़ता है और बहुत ज्यादा घनी आबादी उसपर निर्भर करता है, इसके बाद एक रोड है श्रीकिशुन पंचायत जो लखीसराय के सूर्यगढ़ा विधान सभा में पड़ता है,जो कजरा से होते हुए शिवडीह होते हुए लखना तक,यह भी बड़ा ही इम्पौरटेंट रोड है, इसके बाद एक रोड है बसौनी, जो लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड में पड़ता है, बसौनी मोड़ से ले करके लहसुरवा-कटहरा आदिवासी टोला तक यह जाता है, तो इसतरह से महोदय, इस रोड को बनाना जनहित में बहुत ही जरुरी है और अब आपके द्वारा लाल बत्ती भी जल गया.... .... (व्यवधान)

सभापति (मो0 इलियास हुसैन):- आप लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दीजियेगा ।

श्री प्रहलाद यादवः- महोदय एक मिनट । माननीय नेमतुल्लाह जी, जो बताये, सड़क का नाम बताये हैं हुजूर, वह एक तरफ से बना है और दूसरे तरफ से टूटते गया है और वह एजेंसी कौन है तो वह केन्द्रीय एजेंसी है, हमलोगों का बिहार सरकार का एजेंसी नहीं है, एक तरफ से टूट रहा है और दूसरी तरफ से वह बनता जा रहा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि वे इसकी जांच तो करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा, फिर

जनहित के लिए पैसा दिया जाता है, यह गरीब का पैसा होता है और उसको मान लीजिये कि एक तरफ से बनावें और एक तरफ से साफ हो जाय, यह तो दुर्भाग्य है, इसलिए इसको निश्चित रुप से जांच करवा लिया जाय, इन्हीं शब्दों के साथ अब हम विशेष। क्या बोलू, चूंकि हमें समय कम मिला था, इसलिए अगर आगे मौका मिलेगा, तो ज्यादा बोलूंगा, हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य बहुत तरह की बात बोलें, ये विधि-व्यवस्था पर बोले और चीज पर बोले, तो उनसे आग्रह करुंगा कि ये निगेटिव नहीं बल्कि पोजिटिव सोचे ।

सभापति (मो0 इलियास हुसैन):- माननीय सदस्य रत्नेश सादा । आपका भी समय 5 मिनट, अगर श्रवण जी रिक्वेस्ट करेंगे, तो सात मिनट कर देंगे ।

श्री रत्नेश सादा:- माननीय सभापति महोदय, मैं ग्रामीण कार्य विभाग के तृतीय अनुपूरक बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, हमारी सरकार का जो लक्ष्य था 2005 में, जब सरकार बनी, तो बिहार के किसी कोने से 6 घंटा में राजधानी पहुंचने का जो लक्ष्य था, उसका पूरा कर चुकी हमारी सरकार माननीय नीतीश कुमार, अब माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निश्चय कार्यक्रम है कि जो 5 घंटा में राज्य के किसी कोने से राजधानी पहुंच जाय । माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार केन्द्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2013-14 राज्य के लगभग 20.199 करोड़ के पथ की स्वीकृति की गयी । महोदय, केन्द्र द्वारा इस राशि को 60 और 40 प्रतिशत कर दिया गया और जो भी योजना दी गयी केन्द्र सरकार को, उन्होंने उस योजना में यह हवाला देकर बंद कर दिया कि इसमें पैसा नहीं है .....

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015 में अपने संसाधन से 692.30 करोड़ रुपये खर्च करके 2196.66 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का कालीकरण किया गया है। सभापति महोदय, 1100 करोड़ रुपये के व्यय पर 50 पथों की कुल लंबाई 181 किलोमीटर की स्वीकृति दी गयी । अध्यक्ष महोदय, नवार्ड योजना के तहत 40 अदद पुलों का निर्माण एवं 259.65 करोड़ रुपये व्यय पर पूर्ण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में राज्य सरकार के विभिन्न जिलों के 250 से अधिक वाले बसावटों को जोड़ा गया । महोदय, राज्य की एजेंसी द्वारा शत-प्रतिशत जो राशि खर्च की गयी उसकी स्वीकृति योजना जैसा कि अभी तक 9648 करोड़ रुपया केन्द्र के उपर बाकी है 2014 एवं मॉर्च 2015 में 65 करोड़ रुपये पथ एवं पुलियों की

स्वीकृति दी गयी । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध करायी गयी ।

क्रमशः

टर्न–26/कृष्ण/03.03.2016

श्री रत्नेश सादा : क्रमश : लेकिन भारत सरकार ने रूपये की कमी का हवाला देकर अगस्त,15 में इस योजना को वापस कर दिया । अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्रांक 17/6/2015 – 342749 दिनांक 20 नवंबर,2015 द्वारा रात को यह सूचना दी गयी है । क्या यह सौतलेपन का व्यवहार नहीं है ? जब 2014 के लोक सभा चुनाव के बाद इन्होंने बिहार की अनदेखी करने का काम किया । जब बिहार में विधान–सभा का चुनाव हुआ तो इन्होंने बिहार के लोगों को ऐसे कर के कहा कि मांगो, कितना लोगे ? 40 लोगे, 50 लोगे, 100 लोगे, सवा सौ लोगे । इस तरह से बोली लगाकर इन्होंने जो वादा किया विशेष राज्य की सवा सौ करोड़ पैकेज देने की, इन्होंने इसमें भी वादा खिलाफी की । मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद जी क्या किये ? भाई, एक बात याद कर लीजिये । 1989 के बाद जब लालू जी आये बिहार में, तो हम जैसे गरीब के बेटे–बेटियों को, गरीब–गुरूवा को मुंह में आवाज देने का काम किया । यह देन लालू प्रसाद की देन है । उस समय हमलोग आपलोगों के समक्ष अच्छा कपड़ा पहन कर नहीं बैठ सकते थे । उस समय आपलोगों के सामने हमलोग जूता नहीं पहन सकते थे । लेकिन आज लालू के राज में मुंह में आवाज भी आयी है और अच्छे कपड़े पहनने का भी मौका मिला है । महोदय, आज जब 2005 में नीतीश कुमार जी गद्दी पर बैठे तो चाहे वह महादलित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या किसी भी सवर्ण समाज के लोग हों, सबको आरक्षण दे करके, खास करके महादलित के बेटे–बेटियों और सभी वर्गो के बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया है । महोदय, इतना ही नहीं, महादलितों के लिये टोला स्वयं सेवक, विकास मित्र, 3 डिसमिल जमीन और दशरथ मांझी कौशल योजना के तहत इन्होंने विकास करने का काम किया । यह हमारे माननीय मुखिया की देन है । कल इनके पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि भाई बिहार के मुखिया लालू यादव और नीतीश कुमार विधायकों को संरक्षण दे रहे हैं । मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सुशासन का राज है, सुशासन कायम है। चाहे कोई भी अपराधी हो, विधायक हो या मंत्री हो, सबके ऊपर कानून का शिकंजा कसा गया है । महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि

अंडर वर्ल्ड के अपराधी के गिरोह के सदस्य भागलपुर के दीपक साह को इनके केन्द्रीय मंत्री गिरधारी सिंह 2 नवंबर,2015 को मोबाईल हॉस्पीटल का उद्घाटन किया। क्या केन्द्रीय मंत्री का यही काम है कि अपराधी को संरक्षण दे, जो हाई कोर्ट एवं पुलिस और सुप्रीम कोर्ट का फरारी है और उस पर मुकदमा है । ये कहते हैं कि हमारी सरकार में हत्यायें हो रही है । मैं इन से पूछना चाहता हूं कि अपराधी को कौन संरक्षण दे रहा है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्री रत्नेश सादा : अपराधी को कौन संरक्षण दे रहा है ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रत्नेश जी, एक सामान्य परम्परा है कि दूसरे सदन के सदस्य या ऐसे लोग जो अपने को डिफेंड करने के लिये यहां उपलब्ध नहीं होते हैं, उन पर आरोप नहीं लगाया जाता है । आप अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

अब आप समाप्त कीजिये ।

(व्यवधान)

रत्नेश जी, बोलिये न । आप खत्म कीजिये न । अब आप अपनी बात समाप्त कीजिये न ।

श्री रत्नेश सादा : समाप्त कर दिये महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री,ग्रामीण कार्य विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री शैलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, तृतीय अनुपूरक बजट के वाद-विवाद के क्रम में ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित विषय पर आपने बोलने का अवसर प्रदान किया और माननीय सदस्यों में श्रीमती प्रेमा चौधरी जी, चन्द्रसेन प्रसाद जी, मो0तौसीफ आलम साहब, सैयद अबु दोजाना साहब, मनीष कुमार जी, मो0नेमतुल्लाह साहब, लक्ष्मेश्वर राय जी, सत्यदेव राम जी, ललन पासवान जी, कुमार सर्वजीत जी, श्रीमती अमिता भूषण जी, राजू तिवारी जी, प्रह्लाद यादव जी, रत्नेश सादा जी ने अपने-अपने सुझाव दिये और इसमें जो अच्छे सुझाव दिये गये हैं, अच्छे विचार व्यक्त किये गये, हम उनका आभार प्रकट करते

हैं और महोदय, आप जो हमें बोलने का अवसर दिये, इसके लिए भी हम आभार प्रकट करते हैं ।

महोदय, अनुपूरक बजट की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री सड़क योजना में 2281 करोड़ रूपये का बजट था। हमलोगों ने केन्द्र से प्रधानमंत्री सड़क योजना में कम से कम उनसे यह मांग की थी कि 4200 करोड़ हमलोगों को तत्काल चाहिए । इस संबंध में हम सदन को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमलोगों न े पहला पत्र 22.04.15 को, दूसरा पत्र 08.09.15 को और तीसरा पत्र 18.09.15 को दिया । इस के द्वारा हमलोगों ने केन्द्र सरकार से यह मांग की थी कि 2281 करोड़ का प्रावधान किया जाय । लेकिन बाद में केन्द्र सरकार ने इसको बढ़ाकर 2781 करोड़ का बजट प्रावधान किया । इसलिए 2781 में 2281 को अगर घटा देते हैं तो 500 करोड़ का अतिरिक्त तृतीय अनुपूरक बजट सदन में लाना पड़ा । महोदय, दूसरी बात उससे महत्वपूर्ण है कि बिहार एक गरीब राज्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बल-बूते पर विकास और प्रगति के पथ पर इसको ले जाना चाह रहे हैं । हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा किये लेकिन केन्द्र द्वारा हमलोगों के साथ लगातार सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है । नवंबर,15 में अचानक एक चिट्ठी आयी और उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना में 60 और 40 रेसियों का निर्धारण किया। महोदय, दु:ख की बात यह है कि 60 और 40 का इन्होंने जो रेसियो किया, केन्द्र का 60 और राज्य का 40 रहेगा। महोदय, जो काम चल रहा है, जो हमारा केन्द्र के यहां 9,247 करोड़ बाकी है जिसमें केन्द्र के द्वारा 905 करोड़ मिला, उसमें भी यह लागू किया । यह बहुत दु:ख की बात है । लेकिन उसके बावजूद हमलोगों ने इसका विरोध भी किया । हमलोगों ने केन्द्र से आग्रह भी किये कि कम से कम जो काम चल रहा है, उसमें इसको लागू नहीं किया जाय । लेकिन केन्द्र ने हमलोगों की एक बात नहीं सुनी । जिसके कारण हमलोगों यह क्षति उठाना पड़ रहा है । इस तरह 1854 करोड़ और 500 करोड़ अगर मिला देते हैं तो 2354 करोड़ का अनुपूरक बजट यहां हमलोगों को लाना पड़ रहा है । हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार विकास के लिये चिन्तित रहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा कि बिहार जैसे गरीब राज्य के लिये यह 60 और 40 नहीं किया जाय । जहां तक मेरी बात है हमने भी ग्रामीण विकास मंत्रालय से आग्रह किया कि इसको तत्काल बिहार जैसे राज्य में यह उचित नहीं है, इसको रोका जाय । लेकिन केन्द्र ने इसको नहीं माना । महोदय, यह जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ये सारे लोग जानते हैं, सत्ता और विपक्ष भी इस बात को जानते हैं कि प्रधान मंत्री

सड़क योजना की शुरूआत हमलोगों के सर्वमान्य नेता अटल बिहारी बाजपेयी जिनका नाम हम बहुत सम्मान से लेते हैं, श्रद्धा के साथ लेते हैं, उनके द्वारा यह योजना चलायी गयी थी और इसमें शत-प्रतिशत राशि केन्द्र का रहता था । लेकिन कौन-सी ऐसी विपदा आ गयी, कौन-सी ऐसी परिस्थिति आ गयी कि माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके किये हुये जो शत-प्रतिशत केन्द्र की राशि दी जाती थी, उसमें 60 और 40 का रेसियो लागू किया गया ? उसके बाद आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह हुये । उन्होंने भी इस चीज को जारी रखा । उन्होंने कोई कटौती करने का काम नहीं किया । लेकिन केन्द्र ने बिहार के साथ सबसे बड़ा गलत काम करते हुये रोकने का काम किया, जिसके कारण बिहार आज सड़कों के क्षेत्र में काफी पीछे पड़ रहा है । बिहार एक गरीब प्रांत है ।

क्रमश :

टर्न-27/सत्येन्द्र/3-3-16

श्री शैलेश कुमार(क्रमशः): हमारे मुखिया अपने बुद्धि विवेक से इसको आगे ले जा रहे हैं। महोदय, एक बात हम बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। हम नहीं जानते कि लोक लाज कहां है, किनके पास है लेकिन इतना हम जरूर आग्रह करेंगे महोदय कि पार्लियामेंट का चुनाव था और यहीं पर आये थे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, उन्होंने गांधी मैदान में बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। वो चर्चा हमलोग नहीं करना चाहते है कि काला धन, 15 से 20 लाख की चर्चा लेकिन हमारे कुछ सदस्यों ने इस बात की चर्चा की, उन्होंने चर्चा इस बात की कि आरा का जब भाषण था तो उन्होंने कैसे डाक लगाने का काम किया कि कितना चाहिए, इतना इतना सवा लाख करोड़। हमलोग उम्मीद करके बैठे हुए थे कि इस बार का जो बजट आयेगा महोदय, उसमें हमलोगों को उचित जो मांग है वह रखा जायेगा लेकिन जब बजट चार दिन पहले केन्द्र सरकार की ओर से आया तो हमलोगों ने उसको देखा तो पाया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कों का था उस मद में मात्र 19 हजार करोड़ रू0 वो दिये पूरे देश में।महोदय, ये कल्पना करने की बात है कि सिर्फ बिहार का 9 हजार 647 करोड़ रू0 में अगर 905 करोड़ जो केन्द्र से मिला शेष महोदय 8 हजार 742 करोड़ अगर बिहार को केन्द्र दे दे तो पूरे देश में क्या जायेगा? लेकिन महोदय हम इस बात को कहना चाहते हैं कि केन्द्र गरीब राज्य को गरीब करना चाह रही है और अमीर को अमीर। हमलोग उम्मीद किये थे कि इस बार के विशेष पैकेज में बिहार को 13 हजार 820 करोड़ रू0 मिलेगा लेकिन महोदय हमलोगों को नहीं मिला। महोदय, एक

चीज और सदन को हम बताना चाहते हैं कि हमलोग जब प्रधानमंत्री सड़क योजना में दिसम्बर,14 में हमलोगों का जो केन्द्र में बाकी था, 1924 करोड़ का प्रस्ताव भेजे थे डी0पी0आर0 भेजे थे बनाकर के कि इसका हमलोगों को स्वीकृति मिले और हमलोग उस काम को करें लेकिन केन्द्र ने यह कहकर लौटा दिया कि तत्काल इस पर विचार नहीं किया जा रहा हे। महोदय, इसके बाद हमलोग पुनः 1357 करोड़ रू0 का डी0पी0आर0 बनाकर के तैयार बैठे हुए हैं। एक हजार कि0मी0 का अभी भी डी0पी0आर0 मेरे पास तैयार है लेकिन महोदय दुख की बात है कि केन्द्र की ओर से असहयोग रहने के कारण हमलोगों का सड़क के क्षेत्र में सारा काम अबरूद्ध है। महोदय,हमारे मुख्यमंत्री जी चिन्तित हैं मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को विकसित करते हुए उच्च कोटि के बारहमासी सड़कों का निर्माण कराया जाय। यह हमारी प्राथमिकता है कि राज्य में जो सभी अनजुड़े गांव और टोले हैं उनमें सम्पर्कता प्रदान की जाय। नये पथों को लिया जाय और पुराने पथों का मरम्मति कराया जाय। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे बसावट का तो मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि बसावट तक कम से कम सम्पर्कता प्रदान करने के लिए पथ बनाया जाय इसके लिए हमलोग दृढ़संकल्पित है।महोदय, हम सदस्यों को एक बात की जानकारी देना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे बिहार में 1 लाख 40 हजार 220 कि0मी0 है कुल पथों की संख्या जिसमें एस0एच0, एन0एच0, मेजर डिस्ट्रीक्ट रोड 17622 है। कुल सड़क का 87.43 प्रतिशत ग्रामीण कार्य विभाग के पास है और एस0एच0, मेजर डिस्ट्रीक्ट रोड का 12.57 प्रतिशत उसके पास है। हम डाटा कुछ पेश करना चाहते हैं। हमारे कुछ सदस्य यह चर्चा कर रहे थे महोदय, 2006 से जनवरी तक का है यह डाटा। महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में अभी तक हमलोगों ने 640 17. 950 कि0मी0,आपकी सरकार आपके द्वार में 7738.560 कि0मी0, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, नये पथ पुल में 4408.960 कि0मी0, अनु0जाति के लिए विशेष अंगीभूत योजना के तहत 564.450 कि0मी0, नाबार्ड सम्पोषित राज्य योजना के लिए 2632 कि0मी0, सीमा क्षेत्र विकास अन्तर्गत 7.270 कि0मी0, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 4477.790 कि0मी0, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत 35325.860 कि0मी0 महोदय,हमलोगों ने 53 हजार 126 हजार कि0मी0 सड़क का निर्माण किया है जिसमें खर्च 26 हजार 747 करोड़ रू0 का है। अभी कुछ माननीय सदस्य यह चर्चा कर रहे थे और अभी बता रहे थे कि हमलोगों ने इतने सड़कों को बनाया है। महोदय, अभी हमारे पास जो लक्ष्य है वो 50 हजार कि0मी0 सड़क बनाने का और लक्ष्य है। महोदय,कुछ सदस्य चर्चा कर रहे थे बसावट के बारे में। हम जानकारी देना चाहते हैं

कि बिहार में कुल बसावट की संख्या 1 लाख 60 हजार 590 है जिसमें हमलोगों ने 60 हजार 284 बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान कर दिया है और शेष बचे करीब 48-50 हजार बसावट जो बचे हैं जिसको सम्पर्कता प्रदान की जानी है। महोदय,इनको सम्पर्कता प्रदान करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमलोग बर्ल्ड बैंक और ब्रीक से बात कर रहे हैं और ऋण लेने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय,बसावट हमारे मुख्यमंत्री जी की एक नई सोच है, एक अनुठा पहल है। हमारे माननीय सदस्य इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि बसावट तक सम्पर्कता कैसे पहुंचे इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नया पहल करते हुए सेटेलाईट के सहारे मैपिंग की व्यवस्था की है जिसमें सारे जितने भी गांव है जो छुटे हुए बसावट हैं वो सारे बसावट आ जायेंगे जो सात निश्चय का यह भी एक पार्ट होगा। महोदय,मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हमलोग एक सीमावर्त्ती जिला किशनगंज को मॉडल जिला के रूप में चयनित किये हैं जिसके तहत वहां 650 कि0मी0 सड़कों का बनाना है। हमारे मुख्यमंत्री जी बढ़ते हुए बिहार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते हैं।

श्री प्रेम कुमार: अध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्री जी ने सारी बातों का का उल्लेख किया है लेकिन सड़कों के गुणवत्ता के बारे में कुछ नहीं कहा। महोदय, जो सड़कें बन रही है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, आपकी सरकार आपके द्वार और अनुसूचित जाति के लिए विशेष अंगीभूत योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। एक तरफ सड़क बनाये जा रहे हैं और दूसरी ओर टूट रहे हैं इसलिए हमलोग सदन का बहिष्कार करते है।

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण सदन से वाक आउट कर गये।)

श्री शैलेश कुमार: महोदय, सच बात यह है कि विपक्ष के लोग सुन नहीं सकते है अभी कटौती प्रस्ताव में अरूण बाबू बोल रहे थे- माल महाराज का मिर्जा खेले होली। माल है जनता का और हमलोगों का जो शेयर है, कम से कम अरूण बाबू पूरी बात तो सुन लीजिये अभी हमारे एक विधायक बोल दिये तो इसके लिए इतना हंगामा आपलोगों ने कर दिया लेकिन हम यह जानना चाहते हैं भाजपा के अगर सदस्य रहते तो जरूर हम उनसे पूछते कि माल किनका है? जनता का है और बिहार का जो शेयर है, उसमें हमलोगों को शेयर नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है अभी बता रहे थे अरूण बाबू मुंह में राम बगल में छुरी। यह किनके पास है ये तो बैठे हुए ऊपर वाले जाने। हमलोगों को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।यह कोई हमलोग नहीं बोले हैं, बोले हैं इसी गांधी मैदान में आरा के मीटिंग में प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हमलोग सवा लाख करोड़ देंगे। नौजवानों को नौकरी देंगे। अरूण बाबू बता रहे थे कि भैंस के आगे

बिन बजाना, सारे सदस्य सुने होंगे किनको बोले केन्द्र भी इस बात को जान रहा है लेकिन उसके बावजूद अगर वो रहते तो और सारी बात बोलते लेकिन हम जो उपलब्धि है वह उपलब्धि बतलाना चाह रहे हैं कि महोदय हमारे नेता चिन्तित है इस बढ़ते हुए बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, केन्द्र अगर हमको सहयोग करे तो 1919 तक में हमलोग इसे एक विकसित प्रदेश के रूप में ले जायेंगे।हम बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है और जन प्रतिनिधि सेवक होता है। हमारे मुखिया हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी जनता के बीच सेवक के रूप में काम करने का काम किये इसीलिए दो तिहाई बहुमत से पुनः हमलोग सत्ता में आये और अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे महोदय तो वो दिन दूर नहीं है कि बिहार में और दिल्ली से....

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी अब समाप्त कीजिये।

श्री शैलेश कुमारः बिहार और दिल्ली में जिस तरह जनता ने खारीज करने का काम किया 1919 में फिर इनको देश से खारीज करने का काम करेंगे इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले माननीय सदस्य अरूण बाबू से आग्रह करेंगे कि वो अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें और प्रोसिडिंग का पार्ट इसको बनवा दिया जाय।

....

अध्यक्षः माननीय मंत्री ने जो लिखित वक्तव्य दिया है वो कार्यवाही का भाग बनेगा।

(परिशिष्ट-1 द्रष्टव्य)

सरकार का उत्तर समाप्त हुआ।

क्या माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

टर्न-28/मधुप/03.03.16

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की माँग 10 रूपये से घटायी जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए ''ग्रामीण कार्य विभाग'' के संबंध में, 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2015, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2015 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2015 के उपबंधों के अतिरिक्त 23,54,00,00,000/- (तेइस अरब चौवन करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माँग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2015, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2015 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2015 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त :-

माँग संख्या- 01 कृषि विभाग के संबंध में 53,80,99,000/- (तिरपन करोड़ अस्सी लाख निनानवे हजार) रूपये

माँग संख्या- 02 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 7,00,00,000/- (सात करोड़) रूपये

माँग संख्या- 03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 28,55,93,000/- (अठाइस करोड़ पचपन लाख तिरानवे हजार) रूपये

माँग संख्या- 04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 5,56,00,000/- (पाँच करोड़ छप्पन लाख) रूपये

माँग संख्या- 08 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 1,00,00,000/- (एक करोड़) रूपये

माँग संख्या- 09 सहकारिता विभाग के संबंध में 3,29,81,32,000/- (तीन अरब उनतीस करोड़ एकासी लाख बत्तीस हजार) रूपये

माँग संख्या- 11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 6,39,99,83,000/- (छः अरब उनचालिस करोड़ निनानबे लाख तिरासी हजार) रूपये

माँग संख्या- 12 वित्त विभाग के संबंध में 8,23,84,000/- (आठ करोड़ तेइस लाख चौरासी हजार) रूपये

माँग संख्या- 15 पेंशन के संबंध में 2,08,35,48,000/- (दो अरब आठ करोड़ पैंतीस लाख अड़तालिस हजार) रूपये

माँग संख्या- 16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 1,26,95,56,000/- (एक अरब छब्बीस करोड़ पंचानवे लाख छप्पन हजार) रूपये

माँग संख्या- 18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 11,17,42,000/- (ग्यारह करोड़ सतरह लाख बेयालिस हजार) रूपये

माँग संख्या- 19 पर्यावरण एवं वन विभाग के संबंध में 12,33,96,000/- (बारह करोड़ तेंतीस लाख छियानवे हजार) रूपये

माँग संख्या- 20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 5,71,22,60,000/- (पाँच अरब एकहत्तर करोड़ बाइस लाख साठ हजार) रूपये

माँग संख्या- 21 शिक्षा विभाग के संबंध में 7,26,25,54,000/- (सात अरब छब्बीस करोड़ पचीस लाख चौवन हजार) रूपये

माँग संख्या- 22 गृह विभाग के संबंध में 1,07,53,19,000/- (एक अरब सात करोड़ तिरपन लाख उन्नीस हजार) रूपये

माँग संख्या- 23 उद्योग विभाग के संबंध में 3,82,20,00,000/- (तीन अरब बेरासी करोड़ बीस लाख) रूपये

माँग संख्या- 24 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के संबंध में 15,00,01,000/- (पन्द्रह करोड़ एक हजार) रूपये

माँग संख्या- 26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 22,41,64,000/- (बाईस करोड़ एकतालिस लाख चौंसठ हजार) रूपये

माँग संख्या- 27 विधि विभाग के संबंध में 59,50,000/- (उनसठ लाख पचास हजार) रूपये

माँग संख्या- 30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 8,03,87,000/- (आठ करोड़ तीन लाख सतासी हजार) रूपये

माँग संख्या- 31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 40,000/- (चालीस हजार) रूपये

माँग संख्या- 32 विधान मंडल के संबंध में 96,10,000/- (छियानवे लाख दस हजार) रूपये

माँग संख्या- 33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 41,79,47,000/- (एकतालिस करोड़ उनासी लाख सैंतालिस हजार) रूपये

माँग संख्या- 38 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के संबंध में 5,65,70,000/- (पाँच करोड़ पैंसठ लाख सत्तर हजार) रूपये

माँग संख्या- 39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 33,28,00,000/- (तैंतीस करोड़ अठाईस लाख) रूपये

माँग संख्या- 40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 47,57,44,000/- (सैंतालीस करोड़ संतावन लाख चौव्वालिस हजार) रूपये

माँग संख्या- 41 पथ निर्माण विभाग के संबंध में 1,84,00,00,000/- (एक अरब चौरासी करोड़) रूपये

माँग संख्या- 43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 12,65,00,000/- (बारह करोड़ पैंसठ लाख) रूपये

माँग संख्या- 44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 1,66,50,16,000/- (एक अरब छियासठ करोड़ पचास लाख सोलह हजार) रूपये

माँग संख्या- 45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 27,14,94,000/- (सताईस करोड़ चौदह लाख चौरानवे हजार) रूपये

माँग संख्या- 46 पर्यटन विभाग के संबंध में 8,30,71,000/- (आठ करोड़ तीस लाख एकहत्तर हजार) रूपये

माँग संख्या- 47 परिवहन विभाग के संबंध में 3,18,24,00,000/- (तीन अरब अठारह करोड़ चौबीस लाख) रूपये

माँग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग के संबंध में 67,86,00,000/- (सड़सठ करोड़ छियासी लाख) रूपये

माँग संख्या- 50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 51,66,80,000/- (एकावन करोड़ छियासठ लाख अस्सी हजार) रूपये

माँग संख्या- 51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 21,52,71,30,000/- (एक्कीस अरब बावन करोड़ एकहत्तर लाख तीस हजार) रूपये

से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुईं ।

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

''बिहार विनियोग विधेयक, 2016''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दकी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग विधेयक, 2016'' को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग विधेयक, 2016'' को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग विधेयक, 2016 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग विधेयक, 2016 पर विचार हो ।''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडश: लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''नाम इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : अब स्वीकृति का प्रस्ताव । माननीय प्रभारी मंत्री ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''बिहार विनियोग विधेयक,2016 स्वीकृत हो । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार विनियोग विधेयक,2016 स्वीकृत हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग विधेयक,2016 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 3 मार्च,2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 24 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च,2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

ग्रामीण कार्य विभाग - परिशिष्ट-1

तृतीय अनुपूरक बजट 2015–16 (23 अरब 54 करोड़ का)

1. वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्रामीण कार्य विभाग का बजट प्रावधान **5612.29 करोड़ (पाँच हजार छः सौ बारह करोड़ उन्तीस लाख)** रू0 था।

2. द्वितीय अनुपूरक बजट में निम्नांकित 2 योजनाओं में अतिरिक्त बजट प्राप्त हुआ है।
   - नाबार्ड–**249.46 करोड़ (दो सौ उन्चास करोड़ छियालिस लाख)** रू0
   - पी0एम0जी0एस0वाई–**(केन्द्रांश–1069.17(एक हजार उनहत्तर करोड़ सतरह लाख)रू0**
3. केन्द्र की भाजपा सरकार की राज्य विरोधी नितियों के एवं राज्य के प्रति सौतेला व्यवहार के कारण पुनः मुझे तृतीय अनुपूरक बजट 500 करोड़+1854 करोड़ = कुल **2354 (तेईस सौ चौवन करोड़) रू0** का बजट सदन में लाने की जरूरत पड़ रही है।
4. बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मद में कम से कम **4200 करोड़ (बयालिस सौ करोड़) रू0** के बजट प्रावधान करने की मांग विभिन्न पत्रों यथा पहला पत्र 22.04.2015, दूसरा पत्र–08.09.2015 एवं तीसरा पत्र 18.09.2015 के द्वारा केन्द्र सरकार से की गई थी लेकिन उनके द्वारा **वित्तीय वर्ष 2015–16** में मात्र **2281 करोड़ (बाईस सौ एकासी करोड़ रू0)** की राशि का की प्रावधान किया गया। बाद के दिनों में उक्त प्रावधानित राशि को बढ़ाकर **2781 करोड़ (सताईस सौ एक्कासी करोड़)** रू0 किया गया जिससे तृतीय अनुपूरक बजट लाना पड़ रहा है। यदि केन्द्र सरकार वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ही बजट प्रावधान को **2781 करोड़ (सताईस सौ एक्कासी करोड़)** रू0 रखती तो तृतीय अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता नही पड़ती। अतः **2781–2281=500 करोड़** का अतिरिक्त तृतीय अनुपूरक बजट लाना पड़ रहा है।
5. इतना ही नही वित्तीय वर्ष 2015–16 के नवंबर 2015 में जानबूझकर पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत राशि उपलब्ध कराने की निति को ही बदल दिया गया। पूर्व में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना में राज्य सरकार को शत–प्रतिशत राशि उपलब्ध करायी जाती थी जिसे माह नवंबर 2015 में बदलकर **60:40** का अनुपात कर दिया गया। यह अनुपात पूर्व से स्वीकृत योजना पर भी लागू कर दिया गया जो सर्वथा अनुचित एवं राज्य विरोधी है। उक्त बदली हुई निति पर पुर्न विचार करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13.12.2015 को पत्र के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था कि **"पुनरीक्षित व्यवस्था से राज्य को मुक्त रखते हुए पूर्व की तरह शत–प्रतिशत राशि उपलब्ध कराने की कृपा की जाय"।**
6. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि तत्कालिन दूरदर्शी एवं लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इस महत्वकांक्षी योजना का प्रारम्भ इस शर्त के साथ किया गया था कि केन्द्र द्वारा शत–प्रतिशत राशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराकर इसे मूर्त रूप दिया जाय।

इस व्यवस्था को आदरणीय तत्कालिन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा भी बरकरार रखा गया।

ऐसी कौन सी आपदा आन पड़ी की भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता तत्कालिन प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लागू की गई व्यवस्था, जिसे यू0पी0ए0 सरकार के द्वारा भी यथावत रखा गया, में परिवर्तन करते हुए 60:40 प्रतिशत का फार्मूला वर्तमान मोदी जी के सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया।

7. तृतीय अनुपूरक बजट में 500 करोड़ रू0 के अतिरिक्त पी0एम0जी0एस0वाई0 Matching State Share (40%) के लिए **1854 करोड़ (अठारह सौ चौवन करोड़ रू0)** की मांग का प्रस्ताव भी तृतीय अनुपूरक बजट में लाया गया है।
8. उपरोक्त परिस्थिति उत्पन्न होना, केन्द्र सरकार की सौतेले व्यवहार का ही दुष्परिणाम है।

9. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन स्वीकृत कोर नेटवर्क के अनुसार पथों की कुल लम्बाई –**57,379 (संतावन हजार तीन सौ उनासी) कि0मी0**

पाँच केन्द्रीय एजेंसीयों के बीच निर्माण हेतु आवंटित किये गए पथों की कुल लम्बाई – **15,526 (पन्द्रह हजार पाँच सौ छब्बीस) कि0मी0**

बिहार सरकार के अधीन BRRDA को वर्ष 2000–01 से वर्ष 2013–14 तक चरणवार निर्माण हेतु स्वीकृत किए गए पथों की कुल लम्बाई –**36,272 (छत्तीस हजार दो सौ बहतर) कि0मी0**

जिसकी कुल लागत –**20,199 करोड़ (बीस हजार एक सौ निनानवे करोड़)रू0**

प्राप्त स्वीकृतियों के विरूद्ध भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी गयी कुल राशि–

11,456 करोड़ (ग्यारह हजार चार सौ छप्पन करोड़)रू0

जनवरी 2016 तक उपरोक्त राशि को व्यय करते हुए **20,493 कि0मी0 (बीस हजार चार सौ तेरानवे कि0मी0)** पथ एवं **55 पुलों** का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष **13,334 कि0मी0 (तेरह हजार तीन सौ चौतीस)** पथ एवं **289** पुलों का कार्य प्रगति पर है। जिन्हें पूर्ण कराया जाना है। इस कार्यो को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के पास **8743 करोड़ रू0 (आठ हजार सात सौ तेतालीस)** बकाया है। बकाया राशि के अभाव में उक्त योजना का कार्य प्रायः ठप सा पडा गया है।

इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन स्वीकृत कोर नेटवर्क में से **5581 कि0मी0 (पाँच हजार पाँच सौ एक्कासी)** पथों की योजना की स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा की जानी है।

दिसम्बर 2014 से अप्रैल 2015 के बीच **2924 कि0मी0** लम्बाई के पथो का डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराया गया था। जिसे 7 माह अपने पास लम्बित रखने के पश्चात् वापस कर दिया गया कि **राज्य के लिए बजट में समुचित राशि का प्रावधान होने पर इन पर स्वीकृति प्रदान हेतु विचार किया जायेगा।** इस कारण लगभग **1397 कि0मी (तेरह सौ सनतानवे)** पथों का तैयार डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु भेजा ही नही गया तथा **1000 कि0मी0 (एक हजार कि0मी0)** पथों का डी0पी0आर0 तैयार करने का कार्य भी रोक दिया गया।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से पुनः इन डी0पी0आर0 को अद्यतन दर पर पुनरीक्षित कर समर्पित करने के संकेत मिले है, जिनपर कार्य किया जा रहा है।

वित्तीय 2015–16 से योजना के वित्तीय समपोषण (शत प्रतिशत केन्द्र समपोषित) की व्यवस्था को बदलते हुए केन्द्र एवं राज्य के बीच में **60:40** के अनुपात मे बाँट दिया गया है। यह व्यवस्था पूर्व स्वीकृत एवं अब तक लम्बित योजनाओं के साथ–साथ भविष्य में प्राप्त की जाने वाली नयी स्वीकृतियों पर भी समान रूप से लागू होगी।

वित्तीय समपोषण के परिवर्तित व्यवस्था के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत योजनाओं एवं भविष्य में स्वीकृति प्राप्त की जाने वाली योजनाओं के लिए समेकित रूप से राज्य सरकार पर Matching State Share (40%) के लिये लगभग **9213 करोड़ रू0 (नौ हजार दो सौ तेरह करोड़)** का वित्तीय बोझ आयेगा। इस राशि के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश (60%) **13820 करोड़ रू0 (तेरह हजार आठ सौ बीस करोड़)** की राशि भी चरणवार रूप से वित्तीय वर्ष **2019–20** तक उपलब्ध करायी जायेगी।

10. इस प्रदेश में कुल बसावट की सं0–**1,08,590 (एक लाख आठ हजार पाँच सौ एकानवे)** है। जिसमें से **60,284 (साठ हजार दो सौ चौरासी)** को एकल संपर्कता प्रदान की जा चुकी है।

    अभी भी **48,307 (अरतालीस हजार तीन सौ सात)** बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान की जानी है।

11. शेष बचे बसावटों **48,307 (अरतालीस हजार तीन सौ सात)** को एकल संपर्कता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक, ब्रीक्स से ऋण लेने का प्रयास कर रही है ताकि राज्य के हर बसावट को एकल संपर्कता प्रदान की जा सके।

12. विभिन्न माननीय सदस्यों के द्वारा ये मांग होती रही है कि उनके क्षेत्र में अनेको बसावटों को राज्य कोर नेटवर्क में शामिल नही किया गया है। छुटे हुए बसावटों को राज्य कोर नेटवर्क में शामिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक अनूठा पहल किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभाग को निर्देश प्राप्त हुआ है कि छुटे हुए बसावटों को शामिल करने के लिए सेटेलाईट का सहारा लिया जाय। सेटेलाईट के माध्यम से छुटे हुए बसावटों को कोर नेटवर्क में शामिल करने हेतु विभाग कार्रवाई कर रही है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय में 1 निश्चय को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करेगी।
13. माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर बिहार के एक जिला किशनगंज को मॉडल जिला के रूप में चयनित किया गया है। इस जिलें में लगभग **650 कि0मी0** सड़क का निर्माण ANNUITY मॉडल के आधार पर किया जाना है। उक्त ANNUITY मॉडल को लागू करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग तत्पर है।

1. वर्ष 2006 से अब तक (2015–16) तक कितना पुल बना

योजना का नाम	लम्बाई(मी0 में)	लागत (करोड़ में)
पी0एम0जी0एस0वाई0	1982.25	79.29
नाबार्ड	2140.70	85.60
कुल	4123.55	164.89

2. 2016–17 का लक्ष्य – पुल का

योजना का नाम	लम्बाई(मी0 में)	लागत (करोड़ में)
पी0एम0जी0एस0वाई0	3000	240.00
नाबार्ड	5500	454.31
कुल	8500	694.31

3. सड़क 2015–16 तक

लम्बाई(मी0 में)	लागत (करोड में)
53126	26747

4. 2016–17 का लक्ष्य – सड़क

योजना का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0 में)	पुल की लम्बाई (मी0 में)	लागत (करोड में)
पी0एम0जी0एस0वाई0	7000		5600.00
नाबार्ड		5500	454.31
एम0एम0जी0एस0वाई0	1980		1579.95

5. नाबार्ड से कितना ऋण लिये है–1833.24 करोड़ (एक हजार आठ सौ तेतीस करोड़ चौबीस लाख)

2016–17 में कितना लेना है – 454.31 करोड़ रू0

6. 2016–17 का बजट – 5954.31 करोड़ रू0 (पाँच हजार नौ सौ चौवन करोड़ एकतीस लाख)

6.1 स्थापना मद में – 250 करोड़ रू0 (दो सौ पचास करोड़)

6.2 योजना मद– 5704.31 करोड़ रू0 (पाँच हजार सात सौ चार करोड़ एकतीस लाख)

6.3 मरम्मति मद में – 1100 करोड़ रू0 (एक हजार एक सौ करोड़)

6.4 गैर योजना स्थापना मद –96.1874 करोड़ रू0 (छियानवे करोड़ अठारह लाख चौहतर हजार)